R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 01
01 से 15 अक्टूबर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

वन नेशन-वन इलेक्शन
क्या होगा साकार...?

एक देश-एक चुनाव के लिए देश में नहीं है
पर्याप्त सुविधा और संसाधन

विपक्षी पार्टियों को इसके लिए तैयार करना
सरकार के सामने बड़ी चुनौती

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

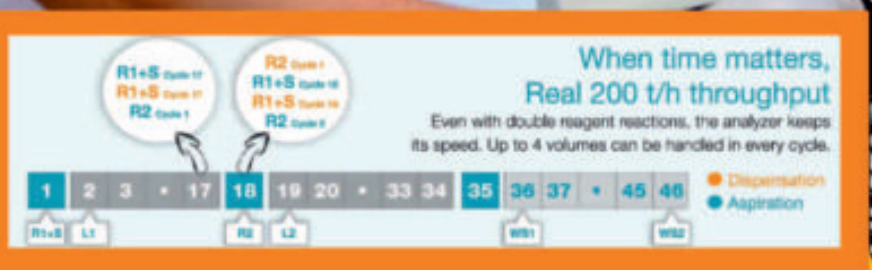

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

भर्राशाही

9 | सीपीए को लेकर दो विभागों...

शिवराज सरकार ने जिस राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को तीन मार्च 2022 को बंद कर दिया था, अब उसके पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार सीपीए अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से ही शुरू हो पाएगा।

डायरी

10-11 | ...तो 23 माह सीएस...

मप्र के नए मुख्य सचिव 1989 बैच के आईएएस अफसर अनुराग जैन होंगे। जैन को मुख्य सचिव बनाने से किसी भी अफसर को सुपर सीड नहीं किया गया है। यानि 1989 बैच के ये पहले अधिकारी हैं। वहीं 1988...

विडंबना

13 | वनरक्षकों से वसूला...

करे कोई और भरे कोई की तर्ज पर वन और वित्त विभाग के अधिकारियों की गलती और लापरवाही का खामियाजा प्रदेश के 6592 वनरक्षकों को उठाना पड़ेगा। यानी प्रदेश में कार्यरत 6592 वनरक्षकों से 165 करोड़ वसूला जाएगा। दरअसल...

योजना

15 | अब झुग्गीमुक्त होगा भोपाल!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने अब तक के कार्यकाल में यह दिखा दिया है कि वे जो कहते हैं, उसे जरूर करते हैं। अब मुख्यमंत्री का सपना यह है कि राजधानी भोपाल को झुग्गीमुक्त बनाया जाए। इसके लिए शहर में 1800 एकड़ में बसी झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में 2029 तक इससे जुड़ी तैयारियों को पूरा करने का सुझाव दिया है। ऐसे में यदि इस पर अमल हुआ तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। यह तब संभव होगा जब...

राजनीति

30-31 | हरियाणा की कास्ट...

हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में इन दिनों 36 बिरादरी शब्द खूब चर्चा में है। एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा 36 बिरादरी की दुहाई दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियां बिरादरियों के समर्थन को...

महाराष्ट्र

35 | हर कोई मुख्यमंत्री...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरह अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है, उसी तरह महायुति में भी इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान आ रहे हैं। इसी क्रम में पुणे में अजित...

बिहार

38 | नई दबंग जातीय व्यवस्था उजागर

जब खबर आई कि बिहार में दबंगों ने दलितों की बस्ती में आग लगा दी। देश के बड़े नेताओं की तरह दिल्ली में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों तक को भी यही भान था कि बिहार में दबंगों का मतलब ठाकुर या भूमिहारों ने यह काम किया...

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
41 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष 23, अंक 1, पृष्ठ-48
1 से 15 अक्टूबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

...फिर किस काम के हम मंत्री

शायर मुनव्वर राणा का एक शेर है...

बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है
बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है

उपरोक्त पंक्तियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी हद में रहना चाहिए, चाहे वह मंत्री हो, संत्री हो या फिर आम आदमी। लेकिन राजनीति में ऐसा कम देखने को मिलता है। पद और प्रतिष्ठा मिलते ही माननीय अपनी हदें भूल जाते हैं... अपने साथियों और सहयोगियों को भुला देते हैं। ऐसा ही मंजर इन दिनों मप्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कुलीनों के कुनबे वाली सरकार है। यह कुनबा चाल, चेहरा, चरित्र के लिए जाना जाता है। लेकिन सरकार में ही इसका लोप है। दरअसल, प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री सहित 32 मंत्री हैं। इनमें से 10 राज्यमंत्री हैं। लेकिन कई राज्यमंत्रियों की स्थिति ऐसी है कि न उनके पास काम है, न अधिकार। आलम यह है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वे किस काम के मंत्री हैं। दरअसल, नई सरकार में कई ऐसे राज्यमंत्री हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें राज्यमंत्री के पद से नवाजा है। सरकार बने हुए अब 10 महीने हो गए हैं। लेकिन अधिकांश मंत्रियों के पास नाम का विभाग है। उनके पास उन विभागों में काम करने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि राज्यमंत्रियों का कद बढ़ाने के लिए सरकार ने जिलों का प्रभार तो दे दिया है, लेकिन उनके विभाग में ही ज्यादा पावर उनके पास नहीं है। जानकारी के अनुसार स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री भी अपने कामकाज से खुश नहीं हैं। उनके पास भी ज्यादा अधिकार नहीं हैं। उन राज्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक अपनी बात पहुंचाई है। गौरतलब है कि इसे लेकर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। राज्यमंत्री दबी जुबान में बात तो करते हैं लेकिन उनका कहना है कि हमें जो काम मिला है, वह कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के 4 राज्यमंत्रियों को काम देने में कैबिनेट मंत्रियों की कंजूसी अब सामने आ रही है। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने राज्यमंत्रियों को दो काम प्रमुखता से दिए हैं। पहला- विधानसभा से आने वाले विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देखें। ये सवाल अतारांकित हों, यानी वो जिन्हें विधानसभा प्रश्नकाल में नहीं लेती। दूसरा- महकमे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों की फाइलें देखें। साफ है कि राज्यमंत्रियों को ज्यादा बड़ा काम नहीं मिला। दबी जुबान में राज्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें जो काम मिला है वह काफी नहीं है। कुछ और काम चाहिए। तभी तो परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। वाकई यह स्थिति राज्यमंत्रियों के लिए विकट है। एक तरफ सत्ता और संगठन बार-बार कह रहे हैं कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस का निरंतर आंकलन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यमंत्रियों के पास करने के लिए कुछ विशेष नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आंकलन कैसे होगा? गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र से जीतकर आने के बाद विधायकों को जब प्रदेश सरकार में मंत्री का ओहदा मिला तो, क्षेत्र में यह संदेश भी गया कि अब हमारे यहां के काम धड़ाधड़ होंगे। लेकिन सरकार बनने के 10 माह बाद भी स्थिति यह है कि कुछ राज्यमंत्रियों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि राज्यमंत्रियों के पास जो काम आ रहे हैं, वे एक आम कार्यकर्ता की तरह लेकर कैबिनेट मंत्रियों के पास पहुंच रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार ये किस काम के मंत्री हैं। हालांकि बताया जाता है कि राज्यमंत्रियों की इस स्थिति की खबर मुख्यमंत्री और संगठन तक पहुंच गई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में राज्यमंत्रियों के पास भी करने के लिए कुछ ऐसा काम होगा, जिससे उन्हें मंत्री के ओहदे के रसूख का अहसास हो सके।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बंद खदानें फिर खुलेंगी

मप्र की बंद कोयला खदानों का उपयोग अब एम-सैंड (यांत्रिकी क्रिया द्वारा पत्थर से निर्मित रेत) बनाने में उपयोग किया जाएगा। खदानों से पर्याप्त मात्रा में कोयला निकालने के बाद पत्थरों का बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाता है। इन पत्थरों से रेत बनाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार कोल इंडिया से भी बात कर रही है।

● **प्रिया सूर्यवंशी,** बैतूल (म.प्र.)

ई-ऑफिस खोले सरकार

सतपुड़ा और विंध्याचल भवन राजधानी भोपाल की सबसे पुरानी इमारतों में शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं। सरकार को ई-ऑफिस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जिससे आग जैसी घटनाओं में सरकार का नुकसान न हो।

● **महक सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

विकास के लिए राशि बढ़ी

मप्र के विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक राशियां मिलेंगी। नई सरकार के गठन के बाद फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे थे। इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान भी कर दिया था।

● **परशुराम मिश्रा,** जबलपुर (म.प्र.)

बेटियों को न्याय कब मिलेगा?

महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा दुनिया के सर्वाधिक प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। इससे दुनिया का कोई भी कोना अछूता नहीं हैं। यह बेहद गंभीर मामला है। देश में अपराधों पर अंकुश न लगने की बड़ी वजह है दोषियों को समय पर उनके किए की सजा न मिल पाना। 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में हुए निर्भया कांड, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। उसके दोषियों को भी सजा मिलने में सालों लग गए। हाल-फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना है। ऐसे में देश में सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है। ताकि बेटियों और उनके परिजनों को न्याय के लिए दर-दर भटकना न पड़े।

● **निदा कुरैशी,** ग्वालियर (म.प्र.)

कड़ी कार्यवाही करे सरकार

जेएईएस द्वारा मप्र में संचालित की जा रही गाड़ियों का मप्र के आरटीओ दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने की अपेक्षा छत्तीसगढ़ आरटीओ में रजिस्ट्रेशन है और रोड टैक्स भी छत्तीसगढ़ सरकार को भरा गया है, जबकि किसी अन्य राज्य के आरटीओ में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में संचालित किया जाता है, तो उस राज्य के आरटीओ कार्यालय में उनका पंजीयन होना चाहिए। लगभग 10 माह में 325 करोड़ रुपए का भुगतान एनएचएम द्वारा जेएईएस को किया गया है जो कि अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार होने के साथ एक जांच का विषय है। सरकार को सख्ती से इस विषय में जांच करने की आवश्यकता है। ताकि भ्रष्टाचारियों को सजा मिल सके।

● **महेंद्र पुरोहित,** भोपाल (म.प्र.)

कब मिलेगा कैशलेस इलाज

वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने इसी तरह की योजना लागू करने की मांग शुरू की थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुविदा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इस वर्ग के अन्य कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आदेश पूर्व में जारी हो चुके हैं, जबकि सुविदा कर्मचारियों को लेकर फिलहाल प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार को सुविदा कर्मचारियों के लिए भी प्रक्रिया जल्द शुरू करवानी चाहिए।

● **आनंद कुमार,** राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

जदयू-राजद में वीडियो वॉर

बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं सत्तारूढ़ जनता दल (यू) और राष्ट्रीय जनता दल के मध्य आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। राजद नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रत्येक दिन याद दिला रहे हैं कि उन्होंने भाजपा का दामन थाम किस प्रकार बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। राजद ने गत दिनों एक पुराना वीडियो जारी किया जिसमें नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो बगैर आवाज का है। राजद नेता जगदानंद सिंह इसके बारे में दावा कर रहे हैं कि नीतीश बाबू राबड़ी देवी से 2017 में गठबंधन तोड़ने के लिए माफी मांग रहे हैं। राजद के इस वीडियो से तिलमिलाई जदयू ने भी इसका जवाब एक वीडियो जारी कर दिया है जिसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में लालू यादव भी बेटे तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में राजद कई ऐसे राज खोलेगी जिससे नीतीश कुमार को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना तय है कि एक-दूजे पर कीचड़ फेंकने के काम को दोनों ही दल आने वाले दिनों में परवान चढ़ाएंगे जिससे और कुछ नहीं तो जनता जनार्दन का मनोरंजन होता रहेगा।

राहुल पर हुड्डा भारी

24 अकबर रोड में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा को लेकर हो रही है। कानाफूसियों का बाजार गर्म है कि कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुछ युवा नेताओं को टिकट देना और कुछ विवादित नेताओं का टिकट काटना चाहते थे लेकिन हुड्डा ने ऐसा होने नहीं दिया और 90 सीटों में से लगभग 75 सीटों पर हुड्डा की पसंद के नेताओं को ही टिकट मिला है। खबर जोरों पर है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा में शामिल रहीं युवा कांग्रेस नेता श्वेता ढुल को राहुल कलायत सीट से पार्टी प्रत्याशी बनाना चाह रहे थे लेकिन हुड्डा हिसार सांसद जयप्रकाश के पुत्र विकास सहारण के नाम पर अड़ गए और अंतत: उन्हें ही पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। इसी प्रकार समालखा सीट से वर्तमान विधायक धर्म सिंह छौकर और भिवानी से सीटिंग विधायक राव दान सिंह के नाम पर राहुल गांधी को आपत्ति थी। इन दोनों ही नेताओं पर ईडी की जांच चल रही है। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा इन दोनों को टिकट दिए जाने के लिए भी अड़ गए और अंतत: पार्टी आलाकमान को सभी सीटिंग विधायकों को टिकट दिए जाने का फैसला लेना पड़ा।

छोटी बहू के फिरे दिन

समाजवादी पार्टी की दूसरी बहू अपर्णा यादव के दिन अब फिरते नजर आ रहे हैं। सपा संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिता की राजनीतिक विरासत उन्हें ही मिली है। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह के रहते हुए ही समाजवादी पार्टी की विरासत पर दावा ठोंकना शुरू कर दिया था। 2017 में मुलायम सिंह ने बामुश्किल अखिलेश यादव को मनाकर अपर्णा को लखनऊ कैंट सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया था और चुनाव मैदान में उतारा था। अपर्णा पराजित हुईं और उसके बाद सपा में वे पूरी तरह हाशिए में डाल दी गईं। 2022 में सपा परिवार की छोटी बहू ने समाजवादी विचारधारा को गुड बाय बोल भाजपा का दामन थाम लिया था। तब से लगातार ये कयास लगते रहे हैं कि भाजपा उन्हें कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर सौंपेगी, जिससे यादव परिवार में आई दरार गहराएगी। लेकिन ऐसा तत्काल नहीं हुआ। मुलायम सिंह की छोटी बहू को लंबा इंतजार करना पड़ा। वे इस दौरान भाजपा, विशेषकर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रिय मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहीं। गौमाता के लिए तो उनका प्रेम पहले से ही सर्वविदित रहा है।

अनिल विज के बागी तेवर

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इस बार कांग्रेस के खेमे में भारी उत्साह तो भाजपा खेमे में हताशा का माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। टिकट बंटवारे में असंतुष्ट कई भाजपा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं तो कईयों ने खुलकर पार्टी लाइन से हटकर बोलना शुरू कर दिया है। भाजपा आलाकमान स्पष्ट कर चुका है कि सत्ता वापसी के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही राज्य सरकार की कमान संभालेंगे। लेकिन दिग्गज नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर भाजपा आलाकमान को असहज करने का काम कर दिखाया है। विज का कहना है कि वे राज्य में सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और प्रदेश की जनता उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती है इसलिए यदि पार्टी को बहुमत मिला तो वह मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी अवश्य करेंगे। विज की इस बयानबाजी से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता प्रदेश भाजपा के भीतर फूट को सामने लाने का काम किया था।

खट्टर से परहेज

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति इस बार कुछ बदली हुई नजर आ रही है। पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से परहेज कर रही है। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों से खट्टर को दूर रखा जाना कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। खट्टर को जब 2014 में हरियाणा का पैराशूट मुख्यमंत्री बनाकर मोदी-शाह ने भेजा था तो पंजाबियों ने इस फैसले को काफी पसंद किया था। लेकिन अब वही खट्टर भाजपा में नेगेटिव नेता करार दे दिए गए हैं, जिनसे सभी समुदायों के वोट छिटक सकते हैं, इसलिए खट्टर को हाशिये पर ढकेल दिया गया है। हरियाणा में मनोहरलाल खट्टर के आने के बाद जबरदस्त जाट आरक्षण आंदोलन चला था। लेकिन खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया था। मूरथल के एक ढाबे पर महिलाओं से गैंगरेप का आरोप लगाकर हरियाणा के समुदाय को बदनाम भी किया गया और अंत में उसमें कुछ नहीं निकला।

पूत के पांव पालने में...

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। लेकिन प्रदेश में इस कहावत को 2018 बैच के एक आईएएस अधिकारी साकार कर रहे हैं। आलम यह है कि साहब की अभी तक जहां भी पदस्थापना हुई है, साहब ने वहां जमकर मलाई काटी है। वर्तमान में साहब मालवा क्षेत्र के एक जिले में पदस्थ हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब जबसे इस जिले में पदस्थ हुए हैं, तबसे उन्होंने कमाई के सारे रिकार्ड तोड़ने की होड़ लगा दी है। बताया जाता है कि साहब आत्मविश्वास से इस कदर लबरेज हैं कि उन्होंने तो कलेक्टर से दौड़ कर ली है कि जिले में कौन सबसे अधिक कमाई करता है। साहब लक्ष्मी बटोरने में इस कदर माहिर हैं कि उन्होंने सबको साधकर काम करने की नीति अपनाई है। सूत्र बताते हैं कि साहब की कमाई की पोल न खुल जाए इसके लिए वे चौथे स्तंभ पर अपनी कमाई का 25 फीसदी खर्च कर डालते हैं। बताया जाता है कि साहब जबसे जिले में पदस्थ हुए हैं। उन्होंने जिलेभर में काली कमाई करने वालों से अपनी संगत बढ़ा ली है। इसका असर यह हो रहा है कि जिले में पदस्थ अन्य अफसर साहब से जलने लगे हैं। पूर्व में साहब ने मालवांचल के ही एक जिले में सीईओ बनने के लिए बड़ी रकम दी थी। बताया जाता है कि उक्त जिले में भी साहब ने जमकर चांदी काटी थी। प्रारंभिक पदस्थापना में साहब जिस तरह कमाई कर रहे हैं, उसको देखकर हर कोई यही कह रहा है कि पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। इनके पिताश्री इनकम टैक्स कमिश्नर हैं।

दो बेचारे, डीओपीटी के सहारे...

ब्यूरोक्रेट्स का तमगा मिलने के साथ ही हर युवा में एक अजब तरह की अकड़ आ जाती है। जो इस अकड़ के बाद भी संभल जाता है, वह अच्छा अफसर बन जाता है। जो बहक जाता है, उस पर शुरू में ही दाग लग जाता है। ऐसा ही दाग मप्र कैडर के 2022 बैच के दो युवा आईएएस अफसरों पर लग गया है। सूत्रों का कहना है कि यूपीएससी में चयन के बाद जब ये अफसर मसूरी में ट्रेनिंग के लिए गए तो वहीं उन पर ऐसा दाग लगा कि अब वे उससे मुक्ति के लिए डीओपीटी के सहारे हैं। जानकारी के अनुसार मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान मप्र कैडर के 2 युवा आईएएस अफसरों के साथ ही 10 अफसरों ने पत्थरबाजी कर कुछ लोगों से लड़ाई कर ली थी। इनमें मप्र के खंडवा और गुना के दो लड़के भी थे, जिनका चयन यूपीएससी में हुआ था। पत्थरबाजी और लड़ाई के बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए इनकी परीवीक्षा अवधि बढ़ाने का दंड दे दिया गया। इस दंड के फलस्वरूप फील्ड में पदस्थ करने की बजाय इन्हें मंत्रालय में भेज दिया गया है। उधर, राज्य सरकार ने डीओपीटी को चिट्ठी लिखकर इनके संदर्भ में सुझाव मांगा है। यानि इनका भविष्य डीओपीटी के सहारे है। अब देखना यह है कि इनको लेकर डीओपीटी क्या निर्देश देता है।

साहब सुस्त... ठेकेदार रुष्ट

सरकार युवा अफसरों पर विश्वास कर रही है। सरकार का मानना है कि युवा जोश पूरे दमखम के साथ विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन एक युवा आईएएस अधिकारी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। आलम यह है कि साहब की सुस्ती सरकार के साथ ही ठेकेदारों पर भी भारी पड़ रही है। दरअसल, हम जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, वे 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साहब पर विश्वास करते हुए सरकार ने राजधानी भोपाल के एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ ही कई योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें स्मार्ट सिटी के अलावा अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, नगरीय प्रशासन में भी बड़ी जिम्मेदारी साहब के पास है। लेकिन वे इनमें इस कदर उलझ गए हैं कि कहीं भी समय नहीं दे पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब काम में बेहद सुस्त हैं और निर्णय लेने की बजाय टालते रहते हैं। इसका खामियाजा विभिन्न शहरों में सीवरेज व पानी सप्लाई के कामों को करने के लिए बनाई गई कंपनी को हो रहा है। आलम यह है कि ठेकेदार परियोजनाओं के तहत मिले काम को तो कर रहे हैं, लेकिन साहब की निष्क्रियता के कारण उन्हें उनके काम का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे वे हैरान-परेशान और नाराज हैं। वहीं साहब के निर्णय नहीं लेने से प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। यहां बता दें कि जिले के प्रभारी मंत्री की बैठक में शामिल नहीं होने के कारण साहब चर्चा में आए थे।

अपने बन गए बेगाने

प्रदेश के धनपतियों में गिने जाने वाले एक विधायक इन दिनों अपनों की दगाबाजी में इस कदर फंस गए हैं कि उनका सुख-चैन तक छिन गया है। माननीय महाकौशल क्षेत्र के एक जिले से आते हैं। इस जिले में माननीय जमीन के अंदर छिपी खनिज संपदा से कमाई करते हैं। इसी क्रम में साहब ने कभी अपनी आंख, नाक और कान रहे एक व्यक्ति के नाम से खदानें और प्रापर्टी लीं, लेकिन ऐन मौके पर वे उन्हें दगा दे गए और उनका साथ छोड़कर अलग हो गए। हालांकि माननीय भी कम नहीं हैं और अपनी संपत्ति पाने के लिए पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंतर्गत गत दिनों माननीय ने अपना साथ छोड़कर जाने वाले और अब खनन कारोबारी बन चुके उक्त व्यक्ति के कुछ ट्रकों को रुकवा दिया। माननीय को लगा कि उन्होंने उसे बड़ा झटका दिया है। लेकिन वे यह देखकर दंग रह गए कि उक्त व्यक्ति ने माननीय की शिकायत सरकार के मुखिया तक कर दी। तब जाकर माननीय को यह अहसास हुआ कि गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चीनी हो गया है। यानि उनसे भी दो कदम आगे निकल गया।

लूट सके तो लूट...

राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट... यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन इन दिनों प्रदेश में जमीनों के धंधे में ऐसा ही कुछ हो रहा है। धारा-16 की आड़ में एक अधिकारी राजनीतिक सांठगांठ से जमकर कमाई कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नगरीय प्रशासन विभाग की धारा-16 के तहत प्रदेश के बड़े शहरों में बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को धड़ाधड़ अनुमतियां दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए रेट भी तय कर दिए गए हैं। यही नहीं सरकार की बड़ी कुर्सी के साथ मिल-जुलकर विभाग के डायरेक्टर ने विभागीय मंत्री और विभाग को दरकिनार कर धारा-16 की अनुमतियों का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए हर जिले में दलालों को सक्रिय कर दिया गया है। जिसको भी धारा-16 के तहत अनुमति की जरूरत पड़ती है, वह सीधे साहब के गुर्गों से आकर सांठगांठ करता है और तय रकम देकर अनुमतियां हासिल कर लेता है। क्योंकि ये अनुमति की फाइल डायरेक्टर और सीधे साहब से जुड़ी होती है। अनुमति देनी है डायरेक्टर को और मलाई काटनी है साहब को। इस पूरे खेल से विभाग एक तरफ है और डायरेक्टर और साहब के बीच खेल चालू है।

सरकार विभागों के खर्च पर पहरा

70 योजनाओं पर पाबंदी

वित्त विभाग ने पूर्व में ही 33 विभागों के 70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगा दी है। इन योजनाओं के लिए पैसा खर्च करने से पहले वित्त विभाग की हरी झंडी लगेगी। यानी कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही विभाग इन योजनाओं में पैसे खर्च कर सकेंगे। जिन योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लागू की गई है वह सीधे आम व्यक्ति से ताल्लुक रखती हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में यह बताया गया है कि ये पाबंदी मार्च 2025 तक लागू रहेंगी। मतलब साफ है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले तक ये रोक इसी महीने से लागू रहेंगी। मप्र में अब सड़क मरम्मत, शहरी सड़कों के सुधार के लिए कायाकल्प योजना, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के सुधार, उन्नयन, डामरीकरण और नवीनीकरण के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, लाखों किसानों में बंटने वाला एक हजार करोड़ के करीब बोनस का पैसा, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संबल योजना अब वित्त विभाग की बिना मंजूरी के खजाने से नहीं निकलेगा, सीएम सोलर पंप स्कीम, बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार की ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन, तीर्थ यात्रा योजना के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी।

आर्थिक संकट से जूझ रही मप्र सरकार के वित्त विभाग ने अब फिजूलखर्ची रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वित्त विभाग ने जहां कई योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगा दी है। इन योजनाओं के लिए पैसा खर्च करने से पहले वित्त विभाग की हरी झंडी लगेगी। यानी कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही विभाग इन योजनाओं में पैसे खर्च कर सकेंगे। जिन योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लागू की गई है वह सीधे आम व्यक्ति से ताल्लुक रखती हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में यह बताया गया है कि ये पाबंदी मार्च 2025 तक लागू रहेंगी। वहीं वित्त विभाग ने 25 करोड़ से अधिक के आहरण पर पाबंदी लगा दी है। यानी विभाग वित्त विभाग की अनुमति के बिना इतनी राशि का आहरण नहीं कर सकते हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही डॉ. मोहन यादव ने वित्तीय मैनेजमेंट पर सबसे अधिक फोकस किया है। इसके लिए उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि जनहितैषी योजनाओं पर सबसे अधिक फोकस किया जाए। इसको देखते हुए वित्त विभाग ने अन्य विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने फंड का उपयोग आवश्यक योजनाओं पर ही करें। उधर, वित्तीय प्रबंधन के लिए एकमुश्त राशि निकालकर रखने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है तो कई योजनाओं के लिए धन की निकासी से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। 25 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आहरण वित्त विभाग से पूछे बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार का जोर पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर है। इससे अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को गति दी जा रही है। इस प्रयास की न केवल भारत सरकार प्रशंसा कर चुकी है बल्कि अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई है। खनिज, आबकारी जैसे क्षेत्रों से आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो कर चोरी रोकने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। प्रदेश में जीएसटी से आय लगातार बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिसंबर में 2,976 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला था, जो 2023-24 के दिसंबर में 3,304 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी 11 प्रतिशत की वृद्धि रही। वित्तीय वर्ष में इस अवधि तक 23,471 करोड़ का राजस्व मिला, जो पूर्व वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक रहा। राजस्व बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक कर मुख्यालय स्थित डेटा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एनालिटिक्स टीम लगाई। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बिल्डिंग मटेरियल आदि क्षेत्र से जुड़े प्रकरणों की छानबीन करके 442 करोड़ रुपए जमा करवाए। ऑडिट कराकर 80 करोड़ रुपए जमा कराने के साथ कर चोरी के 1,106 प्रकरणों में 438 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास कर लगाने के अवसर सीमित हैं। पेट्रोल-डीजल पर पहले से सर्वाधिक वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) मप्र में लिया जा रहा है, इसलिए इसमें वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। अब आबकारी और खनिज साधन ऐसे क्षेत्र हैं, जहां से आय बढ़ाई जा सकती है। आबकारी से 2019-20 में जहां 1 हजार 829 करोड़ रुपए की आय होती थी, वो 2023-24 में बढ़कर 13 हजार 845 करोड़ हो गई। 2024-25 में इसे बढ़ाकर 16 हजार करोड़ रुपए पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही उम्र की आबकारी नीति का अध्ययन भी कराया जा रहा है।

सरकार का फोकस है कि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छोटी व मझोली औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं में बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया जा रहा है तो स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को फिर पैरों पर खड़ा करने के लिए बिना ब्याज का ऋण दिलवाया जा रहा है। कोरोना महामारी के समय जब आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थीं, तब पूंजीगत कामों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने का जो काम शुरू हुआ वो अब गति पकड़ चुका है। पूंजीगत कार्यों में व्यय जीएसडीपी का चार प्रतिशत से अधिक हो गया है। 2019-20 में जहां 29,241 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे थे, वो 2023-24 में 60,689 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस बार भी 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। पूंजीगत कामों के लिए भारत सरकार के निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के कारण विशेष केंद्रीय सहायता योजना में 3,829 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले। अब फोकस उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनाने पर है। निवेशकों की तलाश की जा रही है। 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। साथ ही छोटी और मझौली श्रेणी की इकाइयों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर काम भी किया जा रहा है। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्राथमिकता में रखा है ताकि रोजगार की मांग का दबाव कम हो।

● **अरविंद नारद**

सीपीए को लेकर दो विभागों में खींचतान

शिवराज सरकार ने जिस राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को तीन मार्च 2022 को बंद कर दिया था, अब उसके पुनर्गठन की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार सीपीए अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से ही शुरू हो पाएगा। इसके पहले सीपीए का सेटअप नए सिरे से तैयार करना होगा। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग को सौंपे गए सीपीए के काम उनसे वापस लेकर फिर से सीपीए को सौंपना होंगे। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग एक्शन में आ गया है। विभाग ने लोक निर्माण विभाग को फाइल भेजकर सीपीए की संपत्तियां उसे हस्तांतरित किए जाने को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है। लेकिन लोक निर्माण विभाग संपत्तियां हस्तांतरित करने के लिए राजी नहीं है, इसलिए विभाग ने फिलहाल फाइल को होल्ड कर दिया है। लोक निर्माण विभाग सीपीए का आधिपत्य अपने पास रखना चाहता है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार से सीपीए के पुनर्गठन के लिए आर्थिक व तकनीकी सहयोग मांगा है। यानी नवगठित सीपीए की शहर के विकास में भूमिका बढ़ भी सकती है। इस बीच सीपीए के पुनर्गठन की कवायद के बीच इसके आधिपत्य को लेकर दो विभागों में खींचतान जारी है। ढाई साल पहले सीपीए को बंद करने के बाद इसकी संपत्तियां (सड़कों-बड़े सरकारी भवनों का मेंटेनेंस) लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं। लेकिन लोक निर्माण विभाग अब सीपीए की संपत्तियों को छोड़ना नहीं चाहता है।

वहीं पुराना सीपीए सड़कों के साथ सरकारी भवन और पार्कों के निर्माण व मेंटेनेंस का काम करता था। सीपीए ने राजधानी बनने के बाद सरकारी मकानों और मंत्रालय व अन्य भवनों का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर के साथ चर्चा में सीपीए का दोबारा गठन करने की बात सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी। सीपीए के पुराने सेटअप में एक प्रशासक, एक उप प्रशासक और एक सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, तीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक डीएफओ के साथ उनके अधीनस्थ अन्य इंजीनियर, वन अधिकारी आदि कार्यरत थे। अब सीपीए का सेटअप दोबारा बनेगा। सीपीए के पास 92.5 किमी सड़कों का रखरखाव था। मंत्रालय सहित करीब 24 सरकारी भवनों का रखरखाव सीपीए कर रहा था। शहर के अलग-अलग इलाकों में हुए पौधरोपण और सीपीए द्वारा निर्मित बड़े पार्कों का रखरखाव भी सीपीए कर रहा था। अब इन संपत्तियों की स्थिति का दोबारा परीक्षण होगा। इनमें से कितना सीपीए को वापस मिलता है और कितना पीडब्ल्यूडी व वन विभाग के पास रह जाएगा, इस पर निर्णय करना होगा। नए सिरे से गठित होने वाले सीपीए के बारे में यह सब निर्णय लेने के लिए शासन स्तर पर वरिष्ठ अफसरों की एक समिति बनेगी। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।

20 अगस्त 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीपीए को बंद करने की घोषणा की थी। इसके 196 दिन बाद 3 मार्च 2022 को कैबिनेट बैठक में सीपीए को बंद करने के निर्णय पर मोहर लगी थी और उसके 28 दिन बाद 31 मार्च को सीपीए पूरी तरह बंद हो गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर से सीपीए को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सीपीए के पुनर्गठन को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। चूंकि सीपीए की संपत्तियां पीडब्ल्यूडी के आधिपत्य में हैं, इसलिए विभाग की एनओसी के बगैर प्रस्ताव को कैबिनेट में नहीं लाया जा सकेगा। यही वजह है कि नगरीय विकास विभाग ने एनओसी लेने के लिए पीडब्ल्यूडी को फाइल भेजी है। जानकारों का कहना है कि विभाग सीपीए का आधिपत्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसके पास मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल, विधानसभा भवन, विधायक विश्रामगृह, शहीद स्मारक, पर्यावास भवन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, आवास के मेंटेनेंस के अलावा भोपाल के प्रमुख मार्गों और पार्कों को संधारित करने का काम सीपीए के जिम्मे था। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का काम देख रहा था। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन कार्यों का बजट करोड़ों में है। मंत्रालय का रेनोवेशन 107 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को तोड़कर करोड़ों की लागत से नए भवन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी यह काम पीडब्ल्यूडी के जिम्मे है, यदि सीपीए का पुनर्गठन होता है तो यह काम फिर से सीपीए के पास चला जाएगा। यानि स्वयं ही सीपीए के हाथ में उसके पुराने प्रोजेक्ट आ जाएंगे। यही वजह है कि दोनों विभाग सीपीए का आधिपत्य अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि सीपीए के पुनर्गठन की प्रक्रिया कब पूरी होती है और लोक निर्माण विभाग सीपीए के हिस्से वाले काम नगरीय प्रशासन विभाग को सौंपता है या नहीं।

● **कुमार विनोद**

एनओसी मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगा काम

जानकारों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा एनओसी दिए जाने के बाद ही सीपीए के पुनर्गठन का काम आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि सीपीए दोबारा चर्चा में तब आया, जब गत मार्च में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सीपीए को दोबारा चालू करने की मांग की। इसके बाद मुख्य सचिव ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीपीए के पुनर्गठन को लेकर अभिमत दिया कि पीडब्ल्यूडी सीपीए के पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर सीपीए को पुनर्जीवित करने के लिए मंत्रालय से आर्थिक और तकनीकी सहायता करने का अनुरोध किया था। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग तेजी से सीपीए की कवायद में जुटा है, लेकिन उसे अब तक एनओसी नहीं मिल पाई है। एनओसी मिलने के बाद ही सीपीए के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकेगा।

11 माह सीएस रहेंगे अनुराग जैन

मप्र के नए मुख्य सचिव 1989 बैच के आईएएस अफसर अनुराग जैन होंगे। जैन को मुख्य सचिव बनाने से किसी भी अफसर को सुपर सीड नहीं किया गया है। यानि 1989 बैच के ये पहले अधिकारी हैं। वहीं 1988 बैच खत्म हो गया है। अनुराग जैन की नियुक्ति का आधार अनुभव और सीनियोरिटी है। वैसे तो अनुराग जैन अगस्त 2025 में रिटायर होंगे। यानि ये 11 माह तक मुख्य सचिव बने रहेंगे। लेकिन देश में जिस तरीके का चलन बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी एक्सटेंशन दिया जाएगा। अनुराग जैन 30 मई 2020 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। अनुराग जैन को प्रधानमंत्री की पसंद का अधिकारी माना जाता है। इसके पहले उन्हें केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा चुकी है। आईएएस अनुराग जैन वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर हैं। इसके बाद अब वे वापस भोपाल लौटेंगे। अनुराग जैन लंबे समय से केंद्र में रहे हैं। ऐसे में उनके मुख्य सचिव बनने से केंद्र और राज्य सरकार में अच्छा समन्वय हो सकेगा। मप्र की बात को वे केंद्र में अच्छे से रख पाएंगे। केंद्र सरकार में रहते हुए वे अलग-अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय का कार्य भी कर चुके हैं।

जैन मंडला, मंदसौर और भोपाल में कलेक्टर रह चुके हैं। वे 2005 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव थे। उन्होंने 2011 से 2015 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव पद का दायित्व संभाला। उन्होंने मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त सचिव के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। 2018 में हुए मप्र के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में उनकी वापसी हुई और उन्होंने वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाली। कमलनाथ सरकार में वर्ष 2020 में वे फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। तब से वहीं पदस्थ हैं।

जैन की नियुक्ति में राजनीति

कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाने में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी योगदान तो नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं से भी जैन को सीएस बनाने के लिए पूछा तो नहीं गया। क्योंकि मोहन यादव तो झारखंड जाने से पहले राजेश राजौरा को बधाई दे चुके थे। पर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अनुराग जैन को थोपा है, उससे तो यही लगता है कि कहीं प्रदेश के बड़े नेताओं की भूमिका भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को डोमिनेट करने में तो नहीं है। अब देखना यह है कि कहीं स्वच्छ, कड़क प्रशासन देने के लिए अनुराग जैन जाने जाते हैं, ऐसे में हमेशा प्रशासनिक गर्माहट बनी रहेगी।

मप्र पर दिखेगा प्रभाव

अनुराग जैन तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं। अनुराग जैन को व्यक्तिगत रूप से या संगठन के प्रमुख के रूप में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रमुख हैं ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा उत्कृष्टता का वेब रत्न पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (राज्य सरकार) और नैसकॉम आईटी उपयोगकर्ता पुरस्कार। जैन नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों में गहरी रुचि रखते हैं और आईटी और ई-गवर्नेंस पहलों और इसके कार्यान्वयन में योगदान देते हैं। आईटी और ई-गवर्नेंस के उपयोग के बारे में विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों के दौरान व्यक्त किए गए उनके विचारों को अच्छी तरह से मान्यता मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि अनुराग जैन का असर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरी तरह दिखेगा। अनुराग जैन के कारण सीएम सचिवालय की प्रशासनिक व्यवस्था तो ठीक होगी ही, इकबाल-2 का नजारा भी दिखेगा। वहीं प्रदेश की सियासत में भी गर्माहट महसूस की जाएगी। क्योंकि जिस तरह समीकरणों पर कुंडी मारकर केंद्र सरकार ने उन्हें थोपा है, उससे आने वाले समय में एक कड़क प्रशासन व्यवस्था का नजारा देखने को मिलेगा। इसका संकेत इससे मिलता है कि अनुराग जैन पूर्व में जहां भी पदस्थ रहे हैं, उनका कदम अनुशासन और प्रशासन दिखता रहा है। मप्र का सीएस बनने से जैन को भी कुछ हद तक नुकसान हुआ है। अगर वे केंद्र में फाइनेंस सेक्रेटरी बनते तो उनका कद बढ़ता तथा वे विश्व बैंक जैसे संस्थाओं में नौकरी कर सकते थे। इससे उनको आर्थिक हानि पहुंची है।

अब इसके बाद राजौरा की बारी

अनुराग जैन के सीएस बनने के बाद अब 1990 बैच आरंभ हो जाएगा। क्योंकि 1989 बैच के सभी अफसर रिटायर हो चुके होंगे। और 1990 बैच में सबसे पहला नाम राजेश राजौरा का है। क्योंकि उनके बैच के भी लगभग अफसर रिटायर हो जाएंगे। जब तक राजौरा मुख्यमंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव की भूमिका में चौथी और पांचवी मंजिल के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मोहन यादव की पसंद से मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। जैन अड़ियल रवैया और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं।

मंडलोई बने एसीएस, राजन अटके

अनुराग जैन के सीएस बनने से मोहम्मद सुलेमान को फायदा हुआ है। वे मंत्रालय में ही पदस्थ रहेंगे। और उनकी खुशी इस बात की है कि मुझसे जूनियर अफसरों की बजाय मेरे ही बैच के सीनियर अफसर को मुख्य सचिव बनाया गया है। अनुराग जैन और सुलेमान की बेहद करीबी दोस्ती भी है। वहीं मंत्रालय में पदस्थ प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को अच्छा खासा फायदा हो गया। एक माह बाद वे अपर मुख्य सचिव बनाए जाते, परंतु अनुराग जैन का आदेश भारत सरकार से राज्य की सेवाएं सौंपने में दिन बीत चुका था। इसी को देखते हुए मुख्य सचिव वीरा राणा के रिटायर होने से पद खाली नहीं रखा जा सकता था, इसी का फायदा नीरज मंडलोई को मिल गया। वहीं पर अब प्रमुख सचिव अनुपम राजन अपर मुख्य सचिव बनने की दौड़ में दो माह पिछड़ गए। अब उन्हें इंतजार करना होगा मलय श्रीवास्तव के रिटायर होने का।

नए डीजीपी की खोज शुरू

मप्र के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना नवंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसको देखते हुए उनके स्थान पर नए पुलिस महानिदेशक के लिए विशेष महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने मांगा है। इसमें उन अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए जाएंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम छह माह बाकी हों। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के अगले डीजीपी के लिए 4 अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें 1988 बैच के अरविंद कुमार, कैलाश मकवाना, 1989 बैच के अजय कुमार शर्मा और इसी बैच के गोविंद प्रताप सिंह शामिल हैं। लेकिन इनमें से कौन मप्र का अगला पुलिस महानिदेशक बनेगा, यह तो आने वाले समय ही बताएगा।

उधर, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डीजीपी बनने के लिए मई 2024 में एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिसके अनुसार डीजीपी के लिए वही आईपीएस अधिकारी पात्र है, जिसने पूरे सेवाकाल के दौरान 10 वर्ष रेंज की पोस्टिंग में काम किया है। वहीं जिसने इंटेलीजेंस, आईबी, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, एसपीजी, महिला अपराध सेल, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, एंटी करप्शन विजिलेंस, साइबर सेल आदि में काम किया हो, डीजीपी के लिए फिट होगा। सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार के इस सर्कुलर के अनुसार, राज्य सरकार ने पीएचक्यू से डीजीपी के लिए 3 नाम मांगे हैं। इसके लिए पीएचक्यू को एक प्रोफार्मा भरकर भेजना है। जिसमें 3 कॉलम हैं। इन कॉलमों में पुलिस अधिकारी का योग्यता मापदंड भरना है। लेकिन अभी तक पीएचक्यू ने उक्त प्रोफार्मा को भरकर भेजा नहीं है। जब ये नाम आएंगे, तब जाकर नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।

किसी की टोपी, किसी के सिर

केके सोनगरिया पीएचई के प्रमुख अभियंता हैं। ये अप्रैल 2024 में रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन संविदा आधार पर इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि पहले भी वे मोटी रकम देकर ईएनसी बने थे और दूसरी बार भी ऐसा ही करके वे ईएनसी बने हैं। यानि सोनगरिया हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। आजकल इन्होंने गुर्गे पाल रखे हैं। इसका नजारा अभी हाल ही में नलकूप विभाग के मुख्य अभियंता के रिटायरमेंट की पार्टी में देखने को मिला। मुख्य अभियंता रिटायर हुए तो भोपाल के एक आलीशान होटल में दारू पार्टी दी गई, जिसका सारा भार विभाग पर आ गया। इस खर्च की टोपी टर्न हो रही है। साहब की रिटायरमेंट पार्टी के खर्च का जिम्मा किसी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी को दिया नहीं गया था। ऐसे में अब विभागीय मंत्री के स्टाफ में कार्यपालन यंत्री जो धूम मचा ले धूम की तर्ज पर काम कर रहे हैं, उन्होंने आव देखा न ताव, और कह दिया है कि खर्च तो 50 हजार का है, पर इस अधिकारी से मैं 10 गुना वसूलूंगा। उन्होंने उनकी प्रतिनियुक्ति सेवाएं समाप्त करने की एक नोटशीट सरकार को भेज दी। अब क्या होता है, देखने की बात है। पर मंत्री के यहां पदस्थ उक्त कार्यपालन यंत्री जो विकलांग कोटे से नौकरी कर रहे हैं। वे हमेशा उटपटांग हरकतों से बाज नहीं आते। जब खबरची इनकी पोल पट्टी को छापते हैं तो ये लोगों से अप्रोच लगवाकर गिले-शिकवे दूर करते हैं। वैसे इस विभाग का हाल ही कुछ ऐसा है कि विभाग की मंत्री भी कहती हैं कि अभी तो मेरे चुनाव का खर्च ही नहीं निकला है। उधर, साहब भी इतने बड़े तीरंदाज हैं कि वे भोली-भाली मंत्री को दिवास्वप्न दिखाकर जहां मन करता है, वहां साइन ले लेते हैं।

बिना काम के स्पेशल डीजी

मप्र में स्पेशल डीजी के 12 पद हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अधिकतर पद खाली हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि पुलिस ट्रेनिंग संजीव झा के रिक्त होने के बाद अभी तक भरा नहीं गया है। वहीं पर अभियोजन डीजी सुषमा सिंह के रिटायरमेंट के बाद भी पद खाली पड़ा हुआ है। जबकि पुलिस हाउसिंग में दो डीजी हो गए हैं। वहीं पर प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव भी महिला अपराध में ही पदस्थ हो गई हैं। ऐसे में अफसरों को स्पेशल डीजी बनाकर वहीं पर रखा गया है, जबकि ट्रेनिंग और अभियोजन खाली पड़ा है।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर

मप्र के आईपीएस अफसरों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की होड़ सी मची हुई है। सांई मनोहर पहले से ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं और अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इनके अलावा आलोक रंजन भी प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं सचिन शर्मा, योगेश मुद्गल, आदित्य प्रताप और आबिद खान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने कि इच्छुक हैं। वैसे देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स की लगातार कोशिश रहती है कि उन्हें केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। इसके लिए वे लगातार कोशिश करते रहते हैं।

प्रभारी एडीजी बनाने का चलन

प्रदेश में इन दिनों प्रभारी एडीजी बनाने का चलन भी बढ़ गया है। आलम यह है कि जिन स्थानों पर पहले से ही आईजी पदस्थ हैं, वहां उनकी देखरेख के लिए प्रभारी एडीजी को ऊपर से थोप दिया गया है। प्रभारी एडीजी बनाने की इस प्रक्रिया से पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि नियमानुसार एसपी या अन्य अफसरों को केवल आईजी को जवाब देना होता है, लेकिन एडीजी की पदस्थापना के बाद उसे उन्हें भी जवाब देना पड़ रहा है। वैसे अधिकतर जिलों में पदस्थ आईजी एडीजी ही हैं। लेकिन कुछ रेंज में आईजी और एडीजी पदस्थ हैं। फिर भी उसके बाद सरकार ने मॉनीटरिंग करने के लिए रेंज के प्रभार एडीजी को दिए हैं। ये सभी एडीजी 1995 बैच तक के अफसर हैं।

4 पदों के लिए 12 नाम

लंबे इंतजार के बाद राज्य पुलिस सेवा के 1995-97 बैच के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के अवार्ड के लिए डीओपीटी को नाम भेजा जाएगा। 4 पद के लिए 12 नाम जाएंगे। इसमें 1995 बैच के प्रकाश परिहार और 1997 बैच के दिलीप सोनी, सीताराम सत्या, अवधेश बागरी, राजेंद्र वर्मा, सुरेंद्र जैन के नाम प्रमुख होंगे। गौरतलब है कि रापुसे से भापुसे की डीपीसी का लंबे समय से इंतजार चल रहा है।

● **राजेंद्र आगाल**

महिला बटालियन की उपयोगिता क्या?

मप्र पहले से ही पुलिस अमले की कमी से परेशान है। प्रदेश में आबादी के मान से पुलिस बल नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में महिला बटालियन बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि प्रदेश में पहले भी महिला बटालियन बनाई गई थी, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो सका, नतीजे में यह बटालियन धीरे-धीरे खत्म हो गई। अब नए सिरे से तीन बटालियन बनाई जाएंगी। जिनका नाम मप्र की तीन पवित्र नदियों के नाम पर होगा। नर्मदा, क्षिप्रा और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मप्र में हैं। तीनों ही नदियां अलग-अलग क्षेत्रों से निकलती है। इन तीन पवित्र और पूज्यनीय नदियों के नाम पर मप्र पुलिस महिला बटालियन बनाने जा रही है। लेकिन प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक वीथिका में सवाल उठने लगा है कि आखिरकार महिला बटालियन का प्रदेश में औचित्य क्या है?

दरअसल, जानकारों का कहना है कि मप्र दूसरे राज्यों की देखादेखी करता रहा है। प्रदेश के पड़ोसी राज्य उप्र में तीन महिला बटालियन हैं। इसको देखते हुए मप्र भी अपने यहां तीन महिला बटालियन बनाने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि उप्र मप्र से बड़ी आबादी वाला राज्य है। वहां पर 4.16 लाख का पुलिस अमला है। वहां की जरूरतों को देखते हुए पीएसी की 33 बटालियन बनाई गई हैं। इनमें से 3 बटालियन महिलाओं की हैं। अगर मप्र की बात करें तो यहां पर 1.26 लाख का पुलिस अमला है। वहीं एसएएफ की 24 बटालियन हैं। आमतौर पर एक बटालियन में 900 से लेकर 1000 तक जवान होते हैं। इस तरह करीब 24000 जवान तो एसएएफ की बटालियनों में ही हैं। जबकि एसएएफ की बटालियनों की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। ऐसे में इन बटालियनों में पदस्थ जवान बैरेकों में आराम फरमाते रहते हैं। अगर 3 महिला बटालियन बनाई गई तो 3 हजार महिला जवान फील्ड से कम हो जाएंगी।

आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मप्र में महिला बटालियन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वे इस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ एसएएफ में पदस्थ जवान अपने मुख्यालय में डेरा डाले रहते हैं, वहीं जिला बल में पदस्थ जवानों को 12 से 18 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ रही है। इसका असर कानून व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। दरअसल, जिला बल में जितने जवानों की जरूरत है, उतने जवान आज भी प्रदेश में नहीं हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कह दिया, उसे करने के लिए अधिकारी बिना सोचे-समझे सक्रिय हो जाते हैं। जानकारों का कहना है कि फिलहाल मप्र में महिला बटालियन की जरूरत नहीं है। फिर भी न जाने क्यों इसके लिए कवायद की जा रही है।

दरअसल, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर बटालियन अलग-अलग हो। जो 26 हजार पद खाली हैं, उन्हें भरा जाए। लेकिन सरकार को यह भी सोचने की जरूरतर है कि हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे में एसएएफ के जवानों को बैठाकर पैसा देने के लिए नई बटालियन की जरूरत क्या है। एसएएफ के जवान महीनों खाली हाथ बैठे रहते हैं। लेकिन इस बात को भलीभांति जानने वाले पुलिस महानिदेशक मुख्यमंत्री को यह समझाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। उधर, प्रदेश में तीन महिला बटालियनों के गठन की कवायद चल रही है। दरअसल, पुलिस मुख्यालय के अफसरों की हाल ही में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में इन बटालियनों को बनाने का प्लान तैयार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने पहले से ही इन बटालियनों के नाम तय कर दिए हैं। इसलिए इन तीनों बटालियनों के नाम यही रहेंगे। अब इनका मुख्यालय कहां पर होगा, कितनी संख्या में महिलाओं को इन बटालियनों में रखा जाएगा। बटालियन बनाने की पूरी प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजे जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों के साथ पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में जो बैठक की थी, उसमें यह तय हुआ था कि महिला बटालियनों को लेकर जल्द काम करना है। इसके बाद से ही पुलिस मुख्यालय होमवर्क में जुट गया है। प्रदेश पुलिस में पहले भी एक महिला बटालियन थी, जिसका नाम रानी दुर्गावती वाहिनी रखा गया था। कुछ साल यह अस्तित्व में रही, इसके बाद यह खत्म हो गई। दरअसल इस बटालियन में कई व्यवहारिक दिक्कतें सामने आई थीं। इसके बाद इसे खत्म कर दिया गया था। हालांकि प्रदेश में अभी 23वीं बटालियन में महिला बल की एक कंपनी है।

● **विकास दुबे**

हर जिले में पुलिस बैंड

मप्र में पुलिस अमले की कमी के बीच मुख्यमंत्री ने हर जिले में पुलिस बैंड बनाने का निर्देश दिया है। यही नहीं उन्होंने 15 अगस्त पर पुलिस बैंड को बजाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश को अमलीजामा पहनाने के लिए अफसरों ने भी जवानों को सफेद कपड़े पहनाकर बैंड बजवा दिया। अफसरों ने मुख्यमंत्री के निर्देश की खानापूर्ति तो कर दी, लेकिन पुलिस बैंड में भर्ती का कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में पुलिस बैंड की संख्या 5 है, जिसे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बढ़ाकर 55 करना है। मगर इसे हकीकत में तब्दील करना इतना आसान नहीं है। पुलिस बैंड को ग्रेड-ए, ग्रेड-बी और ग्रेड-सी के तहत तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहले में 36 म्यूजिशियन (संगीतकार या वादक) होंगे और वे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में तैनात होंगे। 26 म्यूजिशियन वाले ग्रेड-बी पुलिस रेंजों में तैनात किए जाएंगे, जबकि बाकी जिलों को 16 म्यूजिशियन वाले ग्रेड-सी बैंड मिलेंगे। ये बैंड विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के तहत रखे जाते हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने बैंड के लिए अतिरिक्त 800 जवानों की भर्ती की अनुमति मांगी है। लेकिन अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था पर जोर देने की बजाय सरकार बैंड-बाजे पर अधिक ध्यान क्यों दे रही है।

वनरक्षकों से वसूला जाएगा 165 करोड़

करे कोई और भरे कोई की तर्ज पर वन और वित्त विभाग के अधिकारियों की गलती और लापरवाही का खामियाजा प्रदेश के 6592 वनरक्षकों को उठाना पड़ेगा। यानी प्रदेश में कार्यरत 6592 वनरक्षकों से 165 करोड़ वसूला जाएगा। दरअसल, वनरक्षकों के वेतन बैंड में सुधार का प्रस्ताव 5 अक्टूबर 2023 की कैबिनेट में लाया गया था। जिसमें वनरक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की दिनांक से मूल वेतन स्वीकृत करने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया जाना था, पर इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव कार्यालय में ही रोक दिया गया और वन अधिकारियों से कहा गया कि इसे वित्त विभाग के ध्यानार्थ ले जाएं।

दरअसल, वन विभाग में वेतन गणना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिससे सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। वन विभाग ने वनरक्षकों को 5680 रुपए के मूल वेतन का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जबकि नियमों के अनुसार 5200 रुपए का मूल वेतन ही दिया जाना चाहिए था। इस गड़बड़ी के चलते 6592 वनरक्षकों को पिछले कई सालों से अतिरिक्त वेतन दिया गया। वित्त विभाग के परीक्षण में यह गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद सरकार ने अतिरिक्त दिए गए वेतन की वसूली के आदेश जारी किए हैं। वेतन की गलत गणना के चलते 2006 से काम कर रहे वनरक्षकों से 5 लाख रुपए और 2013 से काम कर रहे वनरक्षकों से 1.5 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। इसमें 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी जोड़ा जाएगा। वित्त विभाग ने वेतन बैंड में सुधार के लिए भी कहा है, जिससे भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों से बचा जा सके।

वित्त विभाग के पत्र के अनुसार वेतन की गलत गणना की जिम्मेदारी वन विभाग और कोषालय दोनों की है। वेतन का गलत निर्धारण होने के बावजूद, कोषालय द्वारा इसे बढ़ा हुआ वेतन जारी किया गया। 2006 में लागू छठे वेतनमान के बाद, वनरक्षकों का वेतन बैंड 5680 रुपए और ग्रेड-पे 1900 रुपए कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। सरकार के इस आदेश से वनरक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। कई कर्मचारियों के लिए यह आर्थिक झटका है, क्योंकि वे पिछले कई सालों से इस बढ़े हुए वेतन पर निर्भर थे। अब उन्हें अतिरिक्त भुगतान के साथ-साथ 12 प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा।

प्रदेश के 6592 वनरक्षकों के वेतन निर्धारण में गलती के लिए वन एवं वित्त विभाग के अधिकारी बराबर के जिम्मेदार हैं। जहां वन विभाग ने वेतन निर्धारण और वित्त विभाग से उसके अनुमोदन में 9 साल लगा दिए, तो वहीं साल 2009 से 2011 तक वनरक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं के परीक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारियों ने इसी वेतन निर्धारण को सही ठहराया है और अब वही गलत हो गया। सबसे पहला मामला तब सामने आया जब वर्ष 2017 में सातवें वेतनमान का निर्धारण हुआ और 2018 में दोबारा सेवा पुस्तिकाएं कोषालय पहुंचीं। तब भोपाल और नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के जिला कोषालय अधिकारियों ने इस वेतन निर्धारण पर आपत्ति ली। बता दें कि 6592 वनरक्षकों को जनवरी 2006 से 2014 के बीच 5200 के स्थान पर 5680 वेतन बैंड दिया गया। यानी हर माह 480 रुपए अधिक और अब उनसे 165 करोड़ रुपए की वसूली करने की तैयारी है।

वन और वित्त विभाग की एक गलती से वनरक्षकों को 8 साल तक बढ़ा वेतन दिया जाता रहा। दरअसल, ये स्थिति वनरक्षकों के मूल वेतन (पे बैंड) के गलत गणना से बनी है। भर्ती नियम के मुताबिक पे बैंड 5200 देना था, लेकिन दिए गए 5680 रुपए। ये गड़बड़ी 1 जनवरी 2006 से 8 सितंबर 2014 के बीच भर्ती हुए वनरक्षकों की सैलरी में हुई है। जिनसे अब वसूली की जाएगी। वित्त विभाग की कड़ी आपत्ति के बाद वन विभाग ने इसी महीने से पे बैंड में सुधार के निर्देश दिए हैं। वसूली के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। इस राशि पर वन विभाग ब्याज भी लेगा। वन विभाग ने पहले तो सैलरी में 165 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, अब 6 हजार 592 फॉरेस्ट गार्ड्स से इसकी वसूली की जाएगी। यानी हर वनरक्षक को औसतन ढाई लाख रुपए सरकारी खजाने में वापस जमा कराने होंगे। प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से 6वां वेतनमान लागू हुआ है। जिसमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित वनरक्षकों का वेतनमान एक (5200+1800) कर दिया गया। 28 फरवरी 2009 को वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखा कि विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार संवर्गवार वेतनमान का निर्धारण कर लें।

● **प्रवीण सक्सेना**

छत्तीसगढ़ ने सुलझाया मामला

मप्र से वर्ष 2000 में अलग हुए छत्तीसगढ़ राज्य में भी यही गड़बड़ी वनरक्षकों के वेतनमान में हुई थी। जिसे पिछले साल हल कर लिया गया। 6 जुलाई 2023 की कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लाया गया और कैबिनेट ने विभागीय सेटअप स्वीकृति दिनांक 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त सभी वनरक्षकों का वेतनमान एक समान मान्य कर लिया। जिसके आदेश 20 जुलाई 2023 को जारी कर दिए गए। मप्र का मामला निपटाने के लिए एक ही विकल्प है। डॉ. मोहन कैबिनेट छत्तीसगढ़ सरकार की तरह निर्णय लेते हुए इस वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से लागू कर दे। इससे भोपाल और नर्मदापुरम वनवृत्त में पहले और बाद की भर्ती के बीच वेतन की विसंगति भी दूर होगी। 2014 के बाद भर्ती वनरक्षकों को 5680 और उससे पहले वालों को 5200 वेतन बैंड दिया जा रहा है। यानी बाद में नौकरी में आए वनरक्षक वेतन के मामले में पुराने वनरक्षकों से सीनियर हो गए। वनरक्षकों से डेढ़ से 5 लाख रुपए तक की वसूली की जाएगी। साल 2006 से 5680 वेतन बैंड ले रहे वनरक्षकों को 5 लाख रुपए तक सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे, जबकि साल 2013 से लाभ लेने वाले वनरक्षकों को डेढ़ लाख रुपए देने होंगे। हर कर्मचारी ने हर महीने वेतन बैंड में 480 रुपए ज्यादा लिए हैं। इस राशि पर 12 प्रतिशत की दर से उन्हें ब्याज भी देना होगा। वनरक्षक जिला कैडर का पद है। इसमें सर्विस से जुड़े रिकॉर्ड्स वन मंडल कार्यालय में रहते हैं। इसलिए हर वन मंडल में रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। जिससे पता चलेगा कि किस वनरक्षक को कितनी अतिरिक्त राशि दी गई है।

अधर में स्लीमनाबाद टनल प्रोजेक्ट

मैहर, रीवा और सतना के करोड़ों लोगों को फायदा

यदि यह नहर पूरी हो जाती है तो यह भारत की सबसे लंबी वाटर टनल होगी। जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण में अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी भी लगभग 200 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। वहीं इस वाटर टनल के बन जाने के बाद मप्र के एक बहुत बड़े भूभाग की सदियों पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल सतना, रीवा, मैहर, नागौद और कटनी के इस पूरे इलाके में पानी की विकट समस्या है। इस इलाके के लोग पीने तक के पानी के लिए मोहताज हैं और पीने का पानी नहीं होने की वजह से कई बार लोगों को पलायन तक करना पड़ता है। इसलिए जब यह वाटर टनल बन जाएगी तो बरगी बांध का पानी इस इलाके में पहुंचाया जा सकेगा। इसलिए इलाके की 184000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई शुरू हो जाएगी। जो केवल इन इलाकों की तस्वीर ही नहीं बदलेगा, बल्कि आधे मप्र की आर्थिक दशा सुधार देगा।

13 साल पहले जिस टनल प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था, वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसके चलते शासन के करोड़ों रुपए तो खर्च हुए ही, साथ ही प्रोजेक्ट भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्लीमनाबाद टनल प्रोजेक्ट में लापरवाही पर स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। दरअसल, तीन वर्ष में पूरी होने वाली टनल 13 वर्ष बाद भी नहीं बन पाई है। इसके लिए 800 करोड़ का मद निर्धारित था किंतु अब तक करीब 1450 करोड़ खर्च होने के बाद भी निर्माण अधूरा है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को प्रोजेक्ट पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कटनी निवासी दिव्यांशु मिश्रा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया कि नर्मदा विकास प्राधिकरण को स्लीमनाबाद टनल प्रोजेक्ट के माध्यम से बरगी बांध का पानी विंध्य तक पहुंचाना है, जिसमें 1450 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। 2008 में स्लीमनाबाद टनल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था।

सिहोरा से 11 हजार 953 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य का टेंडर साल 2008 में हुआ था। 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी योजना अधर में है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। अब तक इस योजना का एक बूंद पानी विंध्य तक नहीं पहुंच पाया। टनल से संबंधित अन्य दूसरे कार्य भी इसी टेंडर की प्रक्रिया के तहत होने थे, लेकिन उन कार्यों के लिए नर्मदा विकास प्राधिकरण ने अलग से टेंडर जारी कर एक मोटी रकम जारी कर दी। बताया गया कि विधानसभा में भी जब यह सवाल उठा था तो राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में यह बात सामने आई है कि अब तक इस योजना के लिए तकरीबन 1450 करोड़ का पेमेंट सरकार द्वारा कर दिया गया है। जो भी निर्माण कार्य टेंडर का हिस्सा थे, उन निर्माण कार्यों में कई कामों का नए सिरे से टेंडर जारी किया गया और आर्थिक रूप से जानबूझकर पैसों की होली खेली जा रही है। जिसके तहत बार-बार टेंडर में दिया गया एक्सटेंशन और इसकी विस्तृत जानकारी भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

जबलपुर के बरगी बांध से लेकर रीवा तक मां नर्मदा का जल पहुंचाने के लिए चल रही नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की योजना पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। देश की सबसे लंबी टनल परियोजना भी इसी परियोजना का हिस्सा है जो 13 साल देरी से चल रही है, यही कारण है कि ये अब हाईकोर्ट के कटघरे में है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर के सिहोरा से 11953 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य का टेंडर साल 2008 में हुआ था जिसे 40 महीने में पूरा हो जाना था। लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी ये योजना अधर में है। इस मामले में विधानसभा में सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में यह बात भी सामने आई है कि अब तक इस योजना के लिए तकरीबन 1450 करोड़ रुपए का पेमेंट सरकार द्वारा कर दिया गया है। इतना ही नहीं जो भी निर्माण कार्य टेंडर का हिस्सा थे उन निर्माण कार्यों में कई का नए सिरे से टेंडर जारी किया गया और आर्थिक रूप से जानबूझकर पैसों की होली खेली जा रही है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मप्र सरकार से इस परियोजना की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत बार-बार टेंडर में दिया गया एक्सटेंशन और इसकी विस्तृत जानकारी भी तलब की है।

स्लीमनाबाद खुद एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने एक योजना बनाई कि स्लीमनाबाद को बिना उजाड़े इस पहाड़ी के नीचे से एक वाटर टनल बनाई जाए। यह एक बड़ा महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसमें 12 किलोमीटर लंबी वायर टनल बनाई जानी थी। यदि टनल ना बनाई जाती, तो इस पूरे इलाके में लगभग 100 फीट गहरी खुदाई करनी पड़ती और 100 फीट गहरी खाई को बनाए रखने के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती। इसलिए यहां से वाटर टनल बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया और इसका काम शुरू किया गया। इस वाटर टनल को खोदने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया और लगातार इसे बनाए जाने की कोशिश जारी है। हालांकि इन गुफाओं के अंदर खुदाई करना सरल था, लेकिन इनमें पानी भरा हुआ था और यह पानी पूरी मशीन को ही बर्बाद कर देता था। वहीं कुछ जगहों पर मार्बल सामने आ गया, लेकिन इस मार्बल को काटना मशीन के लिए बड़ा कठिन था। अंदर कई बड़े सिंक होल बन गए, जब इन सिंक होल को बंद किया गया, तब काम आगे जारी किया जा सका। कुल मिलाकर 12 किलोमीटर लंबे इस पहाड़ को खोदना किसी चुनौती से कम नहीं रहा।

● **जितेंद्र तिवारी**

अब झुग्गीमुक्त होगा भोपाल!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने अब तक के कार्यकाल में यह दिखा दिया है कि वे जो कहते हैं, उसे जरूर करते हैं। अब मुख्यमंत्री का सपना यह है कि राजधानी भोपाल को झुग्गीमुक्त बनाया जाए। इसके लिए शहर में 1800 एकड़ में बसी झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों का विस्थापन पक्के मकानों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झुग्गियों को हटाने के लिए विस्तृत प्लान बनाने को कहा है। इसे लेकर गत दिनों उन्होंने मंत्री, विधायक समेत अफसरों के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने कहा, पहले भवन तैयार करें। फिर झुग्गियों को खाली कराएं। ताकि, लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने बड़ा तालाब पर एलिवेटेड कॉरिडोर का प्लान बनाने को भी कहा।

गौरतलब है कि भोपाल में चाहे राजभवन से सटे इलाके में 17 एकड़ में फैली रोशनपुरा बस्ती हो या बाणगंगा, भीमनगर, विश्वकर्मा नगर जैसी टॉप 8 झुग्गी बस्तियां। ये सभी शहर के बीच प्राइम लोकेशंस पर करीब 300 एकड़ में फैली हैं। इनके अलावा राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर, पंचशील, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, बापू नगर, शबरी नगर, ओम नगर, दामखेड़ा, उड़िया बस्ती, नई बस्ती, मीरा नगर जैसी कुल 388 बस्तियां शहर में हैं। इन सबकी जमीन का हिसाब लगाएं तो यह करीब 1800 एकड़ के आसपास बैठती हैं। इनमें से ज्यादातर पॉश इलाकों में ही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भोपाल को झुग्गीमुक्त करने के लिए समाधान निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कलेक्टर से झुग्गी मुक्त करने की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो, फिर झुग्गियों को खाली कराया जाए। ताकि लोगों को परेशानी न हो। जनप्रतिनिधियों से समन्वय हो। जिले के राज्य स्तर पर लंबित कार्यों का निराकरण कराना बैठक का मुख्य उद्देश्य है। झुग्गीमुक्त करने के लिए अक्टूबर तक निविदा पूरी कर कार्य शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में कहा कि भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के उद्देश्य से अगले 25 साल के प्लान को ध्यान में रखकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे हों। भोपाल मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत रायसेन, मंडीदीप, सलामतपुर क्षेत्र, सांची तक का क्षेत्र, राजगढ़ और पीलूखेड़ी पुरवार क्षेत्र, बैरसिया और सूखी सेवनिया क्षेत्र के विकास के लिए कार्ययोजना बेहतर ढंग से तैयार की जाए।

शहर को झुग्गीमुक्त करने के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर निजी बिल्डरों को जमीन दी जाएगी। बिल्डर यहां 1 बीएचके फ्लैट बनाकर देंगे। इसके बदले में बिल्डर को सड़क किनारे की जमीन कमर्शियल उपयोग करने के लिए दी जाएगी। जहां भी काम शुरू होगा, दो साल के अंदर बिल्डर को फ्लैट बनाकर देना होगा। यह निर्माण झुग्गी वाली साइट पर ही करना होगा। इस दौरान बिल्डर लोगों को किराए से रहने के लिए किराया भी देगा।

सरकार के प्लान के मुताबिक अगले 5 साल में करीब 30 हजार फ्लैट की जरूरत होगी। हालांकि अभी पूरी संख्या सर्वे के बाद ही सामने आ पाएगी। यह जमीन बिल्डर को कलेक्टर गाइडलाइन और प्रोजेक्ट कॉस्ट के आंकलन पर दी जाएगी। इसमें सरकार का एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, बल्कि इससे उसे कमाई होगी। शहर की तीन बस्तियों को उदाहरण के लिए चुना गया है। पूरे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी तैयार कर लिया गया है। इसके लिए इंदौर के इंजीनियर ने प्रोजेक्ट बनाकर दिया है। दरअसल, यह झुग्गी इलाके रोशनपुरा, एमपी नगर जैसे इलाकों में होने से लोग जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। वल्लभ भवन के आसपास अरेरा हिल्स तक 8 झुग्गी बस्तियां हैं। भीमनगर और वल्लभ नगर तो ठीक मंत्रालय के सामने ही हैं। यहां 10 एकड़ से अधिक जमीन पर 15 हजार झुग्गियां तनी हुई हैं। शहर की सभी झुग्गियों को जोड़ें तो 30 हजार से अधिक झुग्गियां हैं। अनुमानत: रोज 20-25 झुग्गी शहर के किसी ने किसी कोने में बढ़ जाती है। वर्तमान में भी 100 से अधिक झुग्गी निर्माणाधीन हैं।

नगर निगम भोपाल के कमिश्नर हरेंद्र नारायण का कहना है कि शहर में अधिकांश प्राइम लोकेशन पर झुग्गियां हैं। पहले फेज में मांडवा बस्ती, ओम नगर और राजीव नगर को चिह्नित किया गया है। यहां पर कितने लोगों के मकान हैं, उनके लिए कितने फ्लैट की जरूरत होगी, कितनी जमीन शेष रहेगी? प्रोजेक्ट के अनुसार टेंडर निकाले जाएंगे। ये पीपीपी मोड पर होगा। शासन की ओर तैयार प्रोजेक्ट में बिल्डर बदलाव नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शहर को झुग्गीमुक्त करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। एक साथ सभी का प्लान बनाया जाएगा। अलग-अलग झुग्गियों की जगह वहां रहने वालों को उसी जगह पर बिल्डर के माध्यम से फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे। गरीबों के मकान बनने के बाद शेष जगह या दूसरी जगह प्राइम लोकेशन, खासकर सड़क किनारे की जमीन बिल्डर को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दी जाएगी।

● **सुनील सिंह**

हाउसिंग फॉर ऑल में नगर निगम की तैयारी

टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी एरिया में पहली बार बहुमंजिला इमारतों में निजी मकानों का निर्माण किया जाएगा। दुकानें भी बनाई जाएंगी। नीचे दुकान और ऊपर फ्लैट रहेंगे। नगर निगम ने हाउसिंग फॉर ऑल योजना में इसकी तैयारी की है। स्मार्ट सिटी के प्लॉट नंबर 47 व 49 पर मिस डेवलपमेंट किया जाएगा। यानि आवासीय के साथ व्यवसायिक निर्माण होगा। पहले भोपाल स्मार्ट सिटी यह प्रोजेक्ट कर रहा था। शुरुआती योजना के मुताबिक प्लॉट नंबर 47 पर 96 फ्लैट और 76 दुकानें बनाई जाएंगी। वहीं प्लॉट नं 49 पर 144 मकान और 112 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इस तरह दोनों प्लॉट पर कुल 240 फ्लैट और 188 दुकानें बनाई जाएंगी। मकान 1074 से 1300 वर्गफीट तक के हो सकते हैं। अब नगर निगम एचएफए में यह प्रोजेट करने जा रहा है। इस पर 110 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। चयनित एजेंसी को दो साल में निर्माण पूरा करना होगा। प्रदेश में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत 406 नगरीय निकायों की 1927 परियोजनाओं में 784913 ईडब्ल्यूएस मकान स्वीकृत किए गए हैं। वहीं क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक में 6 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

मप्र में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत से भाजपा सरकार कॉन्फिडेंस में है। पार्टी का अभी से 2028-29 के चुनाव पर फोकस है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजन डॉक्यूमेंट 2028 तैयार करने के निर्देश दिए है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की गाइडलाइन कलेक्टरों तक पहुंची है। विजन डॉक्यूमेंट 2028 विधानसभा वार तैयार किया जाएगा। वहीं वोट बैंक बढ़ाने पर भी फोकस है। इसके लिए महिलाओं के रुझान से अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही भाजपा मप्र में अब बूथ स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस कर रही है।

मिशन 2028-29 की तैयारी...

पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव को लेकर सारे अनुमान तब ध्वस्त हो गए थे, जब परिणाम एकतरफा भाजपा के पक्ष में आए। इसकी बड़ी वजह महिलाओं का बड़ा समर्थन मिलना माना गया। इसमें केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक की कई योजनाओं के साथ बड़ी भूमिका लाड़ली बहना योजना की भी मानी गई। ऐसे में पार्टी ने संगठन पर्व के तहत जारी सदस्यता अभियान का रुख भी महिलाओं को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने पर मोड़ दिया है। लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने और महिलाओं को आरक्षण संबंधी कानून बनने के बाद उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि अब तक किसी राजनीतिक दल ने 15 प्रतिशत टिकट भी महिलाओं को नहीं दिया। ऐसे में भाजपा का जोर अधिक से अधिक महिला सदस्य बनाने पर है।

भाजपा हर बूथ पर 30 प्रतिशत से अधिक सदस्य बनाएगी। पार्टी के रणनीतिकार संभागीय स्तर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ हो सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक महिला सदस्य बनाकर महिला नेतृत्व को मजबूत करना है। मप्र में इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। भाजपा ने मप्र में पिछली बार 98 लाख सदस्य तो बनाए लेकिन उसमें महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। इस वर्ष भाजपा डेढ़ करोड़ सदस्यों में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी रखेगी। हर जिले में महिला मोर्चा से कहा गया है कि वे कम से कम एक लाख सदस्य अपने जिले से बनाएं। प्रदेश में बीते 15 वर्ष में गठित तीन विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या का विश्लेषण करें, तो वर्ष 2013 में गठित 14वीं विधानसभा ही ऐसी थी, जिसमें कुल 230 सदस्यों में महिला विधायकों की संख्या 32 यानी लगभग 14 प्रतिशत थी। यह संख्या 15वीं विधानसभा (वर्ष 2018) में घटकर नौ प्रतिशत यानी महिला विधायकों की संख्या घटकर 21 हो गई थी। 2008 में 24 महिला विधायक थीं। यह 2024 में बढ़कर 27 यानी 12 प्रतिशत हो गई। मप्र में स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। पंचायत और नगरीय निकाय जैसी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया है, लेकिन यहां 60 प्रतिशत महिलाएं चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यही स्थिति नगर निगमों की है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में 9 महिला महापौर हैं। मप्र भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि भाजपा ने महिलाओं को आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर सशक्त किया है। संगठन पर्व पर भाजपा महिला लाभार्थी, स्टूडेंट गृहिणियों, प्रोफेशनल्स सभी से संपर्क कर उनको सदस्य बनाएगी।

वहीं भाजपा ने अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर जो तारीखें सामने आ रही हैं, उसके अनुसार नवंबर माह में पार्टी को मंडल अध्यक्ष मिल जाएंगे। तब तक पुराने अध्यक्ष ही कार्य करते रहेंगे। संगठन चुनाव

100 सदस्य बनाना अनिवार्य

भाजपा ने पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने के लिए हर कार्यकर्ता को 100 सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद ही वह सक्रिय सदस्य बन पाएगा। गौरतलब है कि बूथ से लेकर मंडल, जिला पदाधिकारी बनने के लिए पार्टी का सक्रिय सदस्य होना जरूरी होता है। सक्रिय सदस्य ही संगठन का चुनाव लड़ सकता है। पार्टी ने 25 सितंबर को प्रदेश के सभी 64,871 बूथों पर कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें पार्टी 15 लाख से अधिक सदस्य बना सकी। इसमें से 15 हजार बूथ वह भी शामिल हैं जिन पर पार्टी को पिछले चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा था। हालांकि पार्टी का फोकस इन बूथों पर ज्यादा था, फिर भी यहां उतनी संख्या में सदस्य नहीं बन सके। भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी ने जो लक्ष्य दिया था हम उसके करीब हैं।

को लेकर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति में न दबाव चलेगा और न ही सिफारिश। मंडल अध्यक्ष हो या जिलाध्यक्ष उनकी नियुक्ति परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। इसके लिए पहले रायशुमारी बनाई जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। संगठन पर्व के साथ बूथ अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। बूथ अध्यक्ष का चयन और मंडल प्रतिनिधि चुनने के बाद बूथ अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधि ही मंडल अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके बाद जिलाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। पार्टी ने सभी 64,871 बूथों पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मप्र भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशन में समयावधि तय होती है। उसी आधार पर सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और फिर निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। यह सब केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है।

गौरतलब है कि भाजपा हर तीन साल में अपने संगठन और अध्यक्ष में बदलाव करती है। यह बदलाव चुनाव या फिर रायशुमारी के आधार पर होते हैं और कहीं-कहीं सर्वसम्मति भी बन जाती है। फिलहाल चुनाव की जो तारीखें आई हैं, उसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है और इसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर तक जिलाध्यक्षों के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे। दिसंबर माह में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा और जनवरी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को मिल जाएगा। हालांकि अभी इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मप्र में भाजपा साढ़े चार साल बाद मंडल अध्यक्ष के चुनाव कराने जा रही है। पार्टी की तैयारी नवंबर में मंडल अध्यक्षों का चुनाव कराने की है। इसके बाद जिलाध्यक्षों का चुनाव होगा। पहले रायशुमारी से अध्यक्ष चुने जाने की मंशा है। सहमति न बनने पर ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। यह अवश्य ध्यान में रखा जाएगा कि किसी विधायक या मंत्री के दबाव में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति न होने पाए। दरअसल, पहले कोरोना संक्रमण फिर, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा संगठन के चुनाव पिछले साढ़े चार साल से नहीं हो पाए थे। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव कराने की समय सीमा तय कर दी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की परफार्मेंस भी मंडल और जिलाध्यक्ष के चयन का आधार होगी। संगठन पर्व के दौरान अधिक से अधिक सदस्य बनाने वालों के नामों की अनुशंसा की जा सकती है।

इस समय भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। दिल्ली में हुई बैठक में भी पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि मप्र के कार्यकर्ता बेहद ऊर्जावान हैं, यदि उन्होंने डेढ़ करोड़ का लक्ष्य रखा है तो वे दो करोड़ सदस्य बना लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है कि सदस्यता की ताकत ही चुनावों में जीत की राह को आसान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को देश के एक करोड़ युवाओं को राजनीति में आने का आव्हान किया है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए युवा, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करें। संगठन शक्ति, बूथ स्तर कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के साथ शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में लहार विधानसभा और छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव जीते हैं।

डेढ़ करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट लेकर चल रही मप्र भाजपा ने सदस्यता अभियान में पहले चरण में एक करोड़ से अधिक सदस्य बना लिए हैं। अब पार्टी का फोकस 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान के दूसरे चरण पर है। दूसरा चरण शुरू होने से पहले पार्टी के कमजोर परफॉर्मेंस वाले जिलों के सदस्यता प्रभारियों को बदला जाएगा। उनके स्थान पर नए सदस्यता प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक सदस्य बनाए जाएं। गौरतलब है कि 24 दिन चले सदस्यता अभियान के प्रथम चरण के 25 सितंबर को समाप्त होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाए जाने का दावा किया है। भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में जिन एक दर्जन जिलों में सदस्यता अभियान कमजोर रहा है वहां के सदस्यता प्रभारियों को बदला जाएगा और नए प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने नए नेताओं का चयन किया है जिन्हें समीक्षा बैठक के बाद जवाबदारी सौंपी जाएगी। 29 को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान भी सदस्यता का क्रम जारी रखा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अभी तीन दिन का समय इन जिलों के प्रभारियों के पास है वह कितनी सख्या बढ़ा सकते हैं यह देखा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वरिष्ठ नेतृत्व का मानना है कि बारिश के चलते और किसी क्षेत्र में विधायक एवं सांसद के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों के अन्य काम में व्यस्त होने के कारण सदस्यता कम हुई है। उन्हें आगामी तीन दिनों में इसे पूरा करने को कहा जाएगा, उसके बाद दूसरे चरण की तैयारी की जाएगी।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

अब शुरू होगी प्रदेश कांग्रेस की सर्जरी

कांग्रेस ने अपने प्रदेश संगठन में बदलाव की पूरी तैयारी कर ली है। इसका असर नवरात्रि से दिवाली के बीच देखने को भी मिलेगा। पहले चरण में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित की जाएगी और उसके बाद करीब एक दर्जन जिलों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। इसका असर कांग्रेस के आनुषांगिक संगठनों पर भी आएगा और कई जिलों के मोर्चा-संगठन अध्यक्ष बदले जाएंगे। कांग्रेस के उच्च सूत्रों के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी की सूची तैयार हो गई है और सभी बड़े नेताओं की सहमति के बाद अब उसमें बदलाव की गुंजाइश बिलकुल कम है। सूची को लेकर प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी में चल रही अनबन भी समाप्त होती नजर आ रही है। दोनों नेताओं ने दिल्ली में आलाकमान के समक्ष सूची जारी करने पर हामी भर दी है। अगर नेताओं पर विश्वास किया जाए तो नवरात्रि में किसी भी दिन प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। कार्यकारिणी में कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं तो वरिष्ठ नेताओं को भी तवज्जो दी गई है। हालांकि कार्यकारिणी का स्वरूप छोटा ही रहेगा। जीतू पटवारी का दावा है कि कार्यकारिणी में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है, जो कांग्रेस में कुछ करना चाहते हैं और सक्रिय रहना चाहते हैं।

मप्र में तेजी से कम हो रहा कुपोषण...

मप्र में कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों और नवाचारों का असर है कि प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग में पिछले 20 वर्षों में लगातार सफलता मिल रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 वर्ष 2005-06 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 वर्ष 2019-21 के जारी आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य में बच्चों में कुपोषण के मामलों में गिरावट आई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि कुपोषण के विरूद्ध युद्ध में मप्र मिशन मोड पर सक्रिय है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप मप्र में कुपोषण के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आई है। मप्र में 2005-06 में जहां 60 प्रतिशत बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले थे वहीं वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा घटकर 33 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में 45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मप्र देशभर में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2005-06 में दुबलेपन की दर 35 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में घटकर 18.9 प्रतिशत हो गई। इसमें भी 16.1 अंक यानी 45.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। गंभीर दुबलेपन के मामलों में 12.6 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत यानी 6.1 अंक (48.7 प्रतिशत) की गिरावट आई, जिससे मप्र इस श्रेणी में भी देश में दूसरे स्थान पर है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले 20 वर्षों में राज्य में कुपोषण की समस्या न केवल रुकी है, बल्कि इसमें लगातार गिरावट भी दर्ज की गई है। खासकर कम वजन और दुबलेपन जैसे खतरनाक श्रेणियों में मप्र का प्रदर्शन देश में दूसरे स्थान पर है।

मप्र में कुपोषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों से मप्र के कुपोषण में एक सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली हैं। इस ऐप के जरिए पिछले एक वर्ष में बच्चों की कुपोषण स्थिति में निरंतर सुधार परिलक्षित हो रहा है। ट्रेकर ऐप के आंकड़ो के मुताबिक अप्रैल 2023 में राज्य में 30 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले थे, जो जुलाई 2024 तक घटकर 27 प्रतिशत रह गए हैं। अप्रैल 2023 में दुबलापन 8 प्रतिशत था, जो जुलाई 2024 में घटकर 7 प्रतिशत हो गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में बच्चों के पोषण स्तर में पिछले एक वर्ष में ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मप्र में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें प्रमुख हैं- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका। राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषित बच्चों की पहचान और उनके परिवारों को पोषण संबंधी सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कार्यकर्ताओं के प्रयासों से कुपोषण में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के तहत राज्य सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से कुपोषण निवारण के लिए योजनाएं बनाई हैं। इस योजना में हर जिले की आवश्यकता के अनुसार कार्य योजना बनाकर कुपोषण निवारण के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समुदाय की सहभागिता, समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों के तहत गभर्वती महिलाओं, धात्री माताओं, और 6 माह से 24 माह के बच्चों को लक्षित किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से मंगल दिवस मनाया जाता है, जिसमें पोषण से संबंधित जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में एम्स के सहयोग से गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन किया जाता है। इसमें 5 दिन की चिकित्सा और 6 माह का फॉलोअप किया जाता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य सुधार हो सके। सहयोगिनी मातृ सक्षम समिति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में मप्र में सहयोगिनी मातृ सक्षम समिति का गठन किया गया है, जो सामुदायिक निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। ऑनलाइन मॉनीटरिंग आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को सुचारू और समय पर सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉनीटरिंग मॉड्यूल विकसित किया गया है। मप्र सरकार ने कुपोषण उन्मूलन के लिए विजन 2047 के तहत कुछ प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मप्र सरकार ने 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन 33 प्रतिशत से कम, वजन 25 प्रतिशत से कम, दुबलापन 8 प्रतिशत से कम और गंभीर दुबलापन 5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2047 तक सभी प्रकार के कुपोषण का पूरी तरह से उन्मूलन करने का दीर्घकालिक लक्ष्य तय किया गया है।

● कुमार राजेंद्र

1 साल में बच्चों में दुबलापन 10 से घटकर 7 प्रतिशत हुआ

दरअसल मप्र वर्ष 2016 के पहले तक कुपोषण में नंबर 1 था, लेकिन 2005-06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-3 और 2020-21 के सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि मप्र 15 साल में कुपोषण में गिरावट दर्ज करने वाला राष्ट्रीय रैंक में दूसरा राज्य बन गया है। वहीं एक साल में बच्चों में दुबलापन 10 से घटकर 7 प्रतिशत पर आ गया है। श्योपुर को कभी भारत का इथोपिया कहा जाता था लेकिन यह कलंक इस जिले से मिट गया है। जनवरी 2024 की स्थिति में यहां अति कुपोषित सिर्फ 202 बच्चे चिन्हित हुए थे। इसके अलावा अशोकनगर, कटनी, सतना, दतिया, अलीराजपुर, बुरहानपुर में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। कुपोषण के मामले में अब धार जिला 2411 अतिकुपोषित के साथ सबसे आगे है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ओपी पांडे का कहना है कि जिला स्तर पर यहां तीन हजार से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इसलिए संख्या ज्यादा होगी। यहां बच्चों की मॉनीटरिंग हो रही है। वहीं कई जिलों में इसमें लापरवाही बरती जा रही है। प्रदेश सरकार अभी अति कम वजन बच्चों के प्रतिदिन के पोषण आहार पर मात्र 12 रुपए खर्च कर रही है। वहीं, अन्य कुपोषित बच्चों को आठ रुपए और गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को साढ़े नौ रुपए रोज का आहार दिया जाता है। इसमें आधी राशि केंद्र व आधी राशि राज्य सरकार देती है।

डॉ. मोहन का मुरीद हुआ संघ

मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद डॉ. मोहन यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपने 9 माह के शासनकाल में मुख्यमंत्री ने जिस तरह सुशासन के लिए प्रयास किए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। वहीं प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जिस तरह औद्योगिक विस्तार खासकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी प्रभावित है। सूत्रों का कहना है कि अब संघ मप्र सरकार के एक्शन और नीतियों का आंकलन करने में जुटा हुआ है। इसके पीछे संघ की मंशा है कि मप्र सरकार की नीतियां दूसरे राज्यों में भी क्रियान्वित की जाएं।

गौरतलब है कि 2023 में भाजपा ने तीन राज्यों में अपने नई पीढ़ी को सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी, जिसकी सबसे पहली अग्निपरीक्षा लोकसभा चुनाव थी। इस चुनावी परीक्षा में मोहन यादव डिस्टिंग्सन के साथ पास हुए हैं। इससे सबसे अधिक संघ प्रभावित हुआ है। दरअसल सत्ता संभालने के बाद मोहन यादव ने अब तक जिस अंदाज में काम किया उससे यह साफ था कि वह भाजपा और संघ के विजन पर काम कर रहे हैं। मोहन सरकार के अब तक के फैसलों को देखा जाए तो भाजपा की कोर लाइन हिंदुत्व से लेकर ब्यूरोक्रेसी, ट्राइबल, ओबीसी और गरीब वर्ग पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। मोहन यादव खुद संघ से जुड़े हैं, ऐसे में हिंदुत्व उनके भी एजेंडे में रहा है। जबकि कलेक्टरों को हटाने से लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत देने के मामले में वह ब्यूरोक्रेसी को भी साफ संकेत दे चुके हैं कि निजाम अब बदल चुका है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों युवाओं के लिए स्वरोजगार और स्वावलंबन जैसे विषयों पर बेहद गंभीर है। मोहन सरकार के नौ महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद संघ ने इसका रोडमैप तैयार करने पर गत दिनों बातचीत की। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारी-भरकम जीत के बाद संघ और सरकार के बीच हुई पहली समन्वय बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे लव जिहाद, आतंकवाद और कानून व्यवस्था के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव, नई शिक्षा नीति में प्रगति, मदरसों में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कर अलग-अलग समूह गठित किए गए हैं। ये समूह अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस समन्वय बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक स्वपनिल कुलकर्णी और राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख दीपक विस्पुते, मध्य क्षेत्र से यशवंत इंदापुरकर, सहित सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री हितानंद, सह प्रदेश प्रभारी सतीश उपाध्याय सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक संघ और सरकार के बीच हुई इस हाईलेवल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी चिंता जताई गई। खासतौर से लव जिहाद, आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कई जिलों में दंगे जैसे हालात बनने के दौरान प्रशासन की कार्रवाई पर भी चर्चा की गई।

सूत्रों का कहना है कि सत्ता, संगठन और संघ की समन्वय बैठक में स्वावलंबन और स्वरोजगार के मुद्दे पर संघ ने सुझाव दिया कि अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर तैयार कर युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए विभागीय मंत्री, संघ के आनुषांगिक संगठन के प्रतिनिधि के साथ एक समूह का गठन कर अगले चार वर्ष के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाए। स्वदेशी जागरण मंच की अगुवाई में संघ परिवार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी स्वावलंबी भारत अभियान की प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई। अन्य राज्य में अब तक लाखों युवाओं को इससे जोड़ा जा चुका है। उन्हें अभियान के तहत स्वरोजगार लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसी तरह भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, लघु उद्योग भारती, ग्राहक पंचायत, सेवा भारती, भारतीय किसान संघ समेत 11 आनुषांगिक संगठनों की अलग- अलग समस्या और मुद्दों पर भी सरकार के साथ साझा रणनीति तय की गई।

● **लोकेश शर्मा**

जनता ही असली शासक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मप्र ने पिछले 9 माह के सुशासन के प्रयासों से यह जाहिर कर दिया है कि प्रदेश की जनता ही असली शासक है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि अगर किसी अफसर ने आमजन के सामने अपनी अफसरी दिखाने की कोशिश की तो उसे कुर्सी से उतारने में तनिक भी देरी नहीं की गई। वहीं माफिया, अपराधियों ने अगर कानून-व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की तो सरकारी बुल्डोजर ने इसका जवाब दिया। ऐसे में प्रदेश की करीब साढ़े आठ करोड़ जनता को इस बात का अहसास हो रहा है जैसे प्रदेश में उसी का शासन चल रहा है। संवेदनशील मुखिया का ऐसा भरोसा जनता में भी नई आशा को जगाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वभाव ऐसा है कि वह जनता की समस्याओं के प्रति हर पल बेहद संवेदनशील रहते हैं। जनता की सेवा के लिए वह देर रात में भी औचक निरीक्षण करने से भी परहेज नहीं करते। जनता को किसी भी तरह का कष्ट न हो, इसके लिए उनकी मुस्तैदी देखते ही बनती है। वह खुद गरीबी में पले हैं और जनता के कष्टों को अपना कष्ट समझते हैं। साथ ही उनकी संवेदना इसमें जुड़ जाती है। साथ ही सामाजिक सहभागिता के अवसर भी जुटाते हैं। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने अपने एक माह के कार्यकाल में कई साहसिक फैसलों के द्वारा जनता के दिल में विशेष छाप छोड़ने में सफलता पाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की है।

मप्र में 19 सितंबर को सीएम हाउस में सरकार-संगठन के मुख्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें से एक मुद्दा भाजपा नेताओं के बीच बढ़ते विवाद और आंतरिक गुटबाजी दूर करने का स्थायी समाधान निकालना भी था। दरअसल, मप्र में इन दिनों भाजपा नेता एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में टीकमगढ़, रायसेन और रीवा में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जो सरकार और संगठन दोनों को असहज कर रही हैं। हालांकि, संगठन ने इनको सुलझाने की कोशिश की है, मगर पूरी तरह से मामला शांत नहीं हुआ है।

कुलीनों के कुनबे में पड़ रही गांठ

कुलीनों के कुनबे के रूप में ख्यात भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी मानी जाती है। मप्र में भाजपा का संगठन देशभर में सबसे सुशासित और संगठित माना जाता है। लेकिन भाजपा में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के बढ़ते महत्व से मूल भाजपाई हताश हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कुलीनों के कुनबे में गांठ पड़ रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये सारे विवाद इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि भाजपा मूल कैडर की उपेक्षा कर रही है। जो आने वाले दिनों में खतरे की घंटी साबित हो सकता है। भाजपा के वो नेता, जो संगठन के कामकाज को लेकर अक्सर मुखर रहते हैं, कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी की कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेताओं को आयातित करने की रणनीति भारी पड़ रही है। जो गांठ पड़ चुकी है, वो खुलनी मुश्किल है। इधर, पार्टी नेतृत्व का कहना है कि जो भी गिले शिकवे हैं, वो दूर कर लिए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री व टीकमगढ़ सांसद डॉ. वीरेंद्र खटीक के खिलाफ प्रतिनिधियों की नियुक्ति को लेकर विधायकों की लामबंदी का विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत उनके पिछले कार्यकाल के दौरान 28 मई 2021 को हुई थी। कलेक्ट्रेट में बुलाई गई कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में डॉ. खटीक और टीकमगढ़ के तत्कालीन विधायक राकेश गिरी के बीच विवाद हो गया था। बैठक में नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी के कामों को लेकर सांसद ने विधायक पर कई आरोप लगाए थे। इस दौरान राकेश गिरी और सांसद खटीक के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद सांसद ने इन्हीं तीनों विभागों में अपने समर्थक भाजपा पदाधिकारियों को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री जितेंद्र सेन जीतू को पीडब्ल्यूडी, भाजपा महामंत्री अभिषेक खरे को नगर पालिका परिषद जबकि भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज देवलिया को स्वास्थ्य विभाग का सांसद प्रतिनिधि बनाया था।

राकेश गिरि से पिछली बार हुए विवाद के बाद मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि इस बार जब डॉ. खटीक एक बार फिर सांसद बने तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि बना दिए। पूर्व मंत्री और छतरपुर की महाराजपुर विधानसभा से मौजूदा विधायक कामाख्या प्रताप सिंह के पिता मानवेंद्र सिंह ने सबसे पहले मोर्चा खोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। छतरपुर की मौजूदा विधायक ललिता यादव ने उनका समर्थन किया। ये भी कहा कि जो भी सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं, वे विधायकों के कामों में दखल दे रहे हैं। टीकमगढ़ में पूर्व विधायक राकेश गिरि और खरगापुर से पूर्व विधायक राहुल लोधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो संगठन सक्रिय हुआ। 18 सितंबर को मानवेंद्र सिंह और ललिता यादव को भोपाल तलब कर सार्वजनिक बयानबाजी न करने की हिदायत दी गई।

छतरपुर से भाजपा विधायक ललिता यादव का कहना है कि सांसद ने ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाया है। जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोध में काम किया और पोलिंग बूथ पर बतौर कांग्रेसी एजेंट मौजूद रहे। ललिता यादव ने यह भी कहा कि सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार का अपनी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी विधायक के साथ सामंजस्य नहीं है। जिस कारण से सभी विधायक उनसे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. वीरेंद्र कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव में विजय दिलाने के लिए सभी विधायकों ने जी जान से मेहनत की है। ऐसे में उनका पार्टी विरोधी लोगों को प्रतिनिधि बनाना न्यायसंगत नहीं है। दरअसल, 14 सितंबर को छतरपुर में पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भवर राजा और भाजपा

मूल कैडर की उपेक्षा भाजपा के लिए खतरे की घंटी

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस से आकर पदाधिकारी बने नेताओं से भाजपा के पुराने नेताओं का समन्वय नहीं बन पा रहा है। इसी की वजह से विवाद सामने आ रहे हैं। टीकमगढ़ और छतरपुर के विधायकों ने आरोप भी लगाए हैं कि कांग्रेस से आए कार्यकर्ताओं को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है। विधायक सिद्धार्थ तिवारी भी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं। ये मसला नया नहीं है। साल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक भाजपा में शामिल हुए थे, तभी से पार्टी में समन्वय की कमी नजर आ रही है। इसी के चलते विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी। इनमें रुस्तम सिंह, भंवर सिंह शेखावत, वीरेंद्र रघुवंशी, दीपक जोशी जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। वे कहते हैं कि दूसरे दलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में लेने का भाजपा को राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन सत्ता में बंटवारे में मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने से गुटबाजी अंदर ही अंदर पनप रही है। यह केवल मप्र में ही नहीं, उप्र जैसे बाकी राज्यों में भी देखा जा रहा है।

अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री लाल दीवान अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जो व्यक्ति अपराधी है। जिस पर मर्डर जैसे केस हैं, कई अपराध दर्ज हैं। इन्होंने शासकीय जमीन में मकान बना रखा हैं, बूथ कैपचरिंग और खनन के आरोप हैं, ऐसे युवक लोकेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक ने अपना प्रतिनिधि बना रखा है। ऐसे अपराधियों को अगर केंद्रीय मंत्री संरक्षण देंगे तो क्षेत्र में अपराध बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री भवर राजा ने कहा था कि शिकायतकर्ता (लाल दीवान अहिरवार) ने मुझे अपनी व्यथा बताई है और ऊपर भी शिकायत भेजी है। मेरे पास आए थे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। यह व्यक्ति शासकीय योजनाओं में दखलअंदाजी देता है। यह व्यक्ति क्षेत्रीय विधायक के काम में दखलअंदाजी देता है। शिकायतकर्ता ने जो कहा है वह सही है। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए चाहे वह किसी भी पार्टी का हो।

रीवा में 15 सितंबर को ओवर ब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा और विधायक सिद्धार्थ तिवारी आमने-सामने आ गए थे। सांसद मिश्रा ने अपने भाषण के दौरान सिद्धार्थ तिवारी के दादा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि यहां की सड़कें पहले बहुत खराब थीं, तब श्रीनिवास तिवारी नेता हुआ करते थे। वे अपने जीवन में एक गड्ढा तक भरवा नहीं पाए, फिर भी उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, लूट, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। ये सारी बातें उन्हीं की बगल में बैठे और श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी को नागवार गुजरीं। अपने भाषण में पोते ने बताया कि उनके दादा ने क्षेत्र के लिए क्या किया था।

रायसेन में शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को अभिनव गरिमा विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। स्कूल प्रबंधन ने कार्यक्रम में होशंगाबाद के सांसद दर्शन सिंह चौधरी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्यमंत्री और स्थानीय विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल को बतौर मुख्य

अतिथि आमंत्रित किया था। जो कार्ड छपा था, उसमें सांसद दर्शन सिंह का नाम पहले और मंत्री का नाम बाद में था। पटेल ने इस पर आपत्ति दर्ज की। जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए स्कूल प्रबंधन को 12 सितंबर को नोटिस थमा दिया और तीन दिन में जवाब मांगा। मामले का खुलासा तब हुआ, जब नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये विवाद लोकसभा चुनाव से पहले 7 मार्च 2024 को सामने आया था। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सीहोर से भाजपा विधायक सुदेश राय पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया था। सीहोर के खजुरिया कलां में शराब दुकान का ताला तोड़कर प्रज्ञा ठाकुर ने बोतलें तोड़ते हुए कहा था- मुझे शर्म आ रही है कि ये दुकान हमारे विधायक सुदेश राय की है। बाद में जब खुलासा हुआ कि दुकान विधायक की नहीं, बल्कि किसी महेश गौर की है तो सांसद ने मामले से दूरी बना ली थी। सुदेश राय ने इसकी शिकायत संगठन से कर दी थी।

ये मामला विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ पूर्व विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था। दरअसल, भाजपा ने विधानसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र के 4 सीटिंग एमएलए खंडवा से देवेंद्र वर्मा, पंधाना से राम दांगोरे, नेपानगर से सुमित्रा कास्डेकर और बागली से पहाड़ सिंह का टिकट काट दिया था। इन नेताओं ने आरोप लगाया था कि सांसद के इशारे पर पार्टी ने उनके टिकट काटे। इनकी जगह कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं को टिकट दिए गए। विधायकों ने लोकसभा चुनाव से पहले पाटिल के विरोध में मुहिम छेड़ दी थी। संगठन ने जैसे-तैसे इन नेताओं की नाराजगी को दूर किया। लोकसभा चुनाव से पहले 6 अप्रैल 2024 को भाजपा का स्थापना दिवस था। इस दिन प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और भाजपा की न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया था कि पिछले तीन माह में 2.58 लाख से अधिक लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें से 1.26 लाख से अधिक लोग एक ही दिन में भाजपा में शामिल हुए। इनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता, जिनमें मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा महापौर शामिल थे। डॉ. मिश्रा ने यह दावा भी किया था कि पार्टी में शामिल होने वालों में से 90 प्रतिशत से अधिक नेता-कार्यकर्ता कांग्रेसी हैं।

एक्सपर्ट का कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में एक खास रणनीति के तहत काम कर रही थी। इसके जरिए वह मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस को कमजोर करने के साथ लोकसभा चुनाव में रेड जोन वाली पांच लोकसभा सीटें- मंडला, छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड और ग्वालियर में जीत पक्की करना चाहती थी। दरअसल, विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसका असर लोकसभा चुनाव पर न पड़े, इस वजह से भाजपा ने इन पांचों संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया था। इन्हें जिला और प्रदेश स्तर में संगठन के पदों पर एडजस्ट किया गया।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

गांठ तो पड़ ही गई है, अब कोई गुंजाइश नहीं...

भाजपा में कैडर की उपेक्षा का मसला पूर्व मंत्री और जबलपुर के पाटन से विधायक अजय विश्नोई समय-समय पर उठाते रहे हैं। अब सामने आए ताजा विवादों को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस और भाजपा दो विपरीत विचारधाराओं की पार्टी हैं। ऐसे में गांठ तो पड़ ही गई है। नेताओं के बीच समन्वय होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती। लोकसभा चुनाव से पहले बिना जांच-परख किए, जिसे चाहे उसे पार्टी में शामिल कर लिया। इससे भाजपा को फायदा हुआ या नुकसान, इसे लेकर वे जबलपुर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भाजपा ने जबलपुर लोकसभा सीट का चुनाव 4 लाख 86 हजार वोटों से जीता लेकिन विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा में कम वोट मिले। लोकसभा चुनाव से पहले सिहोरा विधानसभा में कांग्रेस की दावेदार एकता ठाकुर को भाजपा में शामिल किया गया था। यहां भाजपा को विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में 5 हजार वोट कम मिले। इसी तरह पाटन से दावेदार नीलेश अवस्थी को भाजपा में लाया गया, यहां भाजपा के 2 हजार वोट कम हो गए। बरगी से जिला पंचायत सदस्य संध्या ठाकुर आईं तो यहां 7 हजार वोट कम हो गए।

संकट में हैं घड़ियाल-डॉल्फिन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) से चंबल के किनारे मौजूद उद्योगों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट के निर्देशानुसार रिपोर्ट में इस बात का ब्यौरा शामिल होना चाहिए कि क्या कोई उद्योग पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रहा है और क्या नदी में दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही 18 सितंबर, 2024 को दिए इस आदेश में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी इन मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 22 अक्टूबर तक ट्रिब्यूनल के समक्ष उनके द्वारा की गई कार्रवाईयों के बारे में अपडेट प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है कि संयुक्त समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में चंबल में हो रहे अनियंत्रित रेत खनन और बहुत ज्यादा मात्रा में होते मछलियों के शिकार को लेकर सजग किया था। इसकी वजह से संकट ग्रस्त घड़ियाल और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। कोटा में हर दिन 31.2 करोड़ लीटर गंदा पानी पैदा हो रहा है, लेकिन उसमें से केवल 5 करोड़ लीटर ही यहां मौजूद दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से साफ हो पा रहा है। ऐसे में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण अधिनियम के तहत कोटा नगर निगम को नोटिस जारी कर चंबल में दूषित सीवेज छोड़ने से रोकने को कहा है। हालांकि, अधिकारियों ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में एनजीटी की सेंट्रल बेंच ने कोटा नगर निगम को इस मुद्दे पर जवाब देने का आदेश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल बेंच ने 18 सितंबर, 2024 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से दो सदस्यीय आंतरिक समिति गठित करने को कहा है। यह समिति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2 जनवरी, 2024 को जारी अधिसूचना की समीक्षा करेगी। समिति को इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि क्या यह अधिसूचना सीपीसीबी या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है। साथ ही समिति को इस बात की भी जांच करनी है कि क्या पिछले आदेश, जिसमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना से छूट दी गई है, उसे संशोधित किया जा सकता है। यह मामला राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2 जनवरी, 2024 को दिए आदेश से जुड़ा है, जिसमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति माफ करने के लिए कुछ प्रावधानों में छूट दी गई है। आरोप है कि यह आदेश पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करता है। इसमें मुख्य मुद्दा धारा डी है, जिसमें कहा गया है, उस पिछली अवधि के लिए कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नहीं ली जाएगी, जिसके दौरान परिचालन की सहमति को नियमित किया गया है। यह भी आरोप है कि सीपीसीबी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया है कि औद्योगिक इकाइयों को सीपीसीबी द्वारा वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार सहमति प्राप्त करनी होगी, और एसपीसीबी ने यह जानकारी संबंधित अधिकारियों और इकाइयों को दे दी है।

न्यायाधिकरण के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। यह तर्क दिया गया कि आरएसपीसीबी द्वारा जारी अधिसूचना, जिसमें पिछले उल्लंघनों को छूट दी गई है, अप्रत्यक्ष रूप से इकाइयों को बिना सहमति के संचालन और पर्यावरण संबंधी मुआवजे के भुगतान से बचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अधिसूचना पर्यावरण मुआवजे की गणना के लिए पूरे देश में लागू होने वाले कानून और कानून के शासन की समानता का उल्लंघन करती है। आगरा जिले के बाह क्षेत्र में चंबल सेंचुरी में घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन के तेंदुए प्राकृतिक प्रहरी बन गए हैं। चंबल में तेंदुओं की संख्या बढ़ने से घड़ियाल, डॉल्फिन के बच्चों और अंडों के शिकार की घटनाओं में कमी आई है। बाह रेंज में तेंदुओं की संख्या 30 तक हो गई है। वन विभाग के अफसर चंबल में तेंदुओं की आबादी को घड़ियाल संरक्षण के लिए अच्छा मान रहे हैं। उनका कहना है कि तेंदुओं की आबादी बढ़ने से जलीय जीवों के शिकार का खतरा कम हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चंबल नदी के किनारे घड़ियाल, मगरमच्छ के प्रजनन के दौरान ग्रामीणों, शिकारियों के आने से अंडों, बच्चों को नुकसान होता था। अब ग्रामीणों ने उन जगहों पर जाना छोड़ दिया है, जहां तेंदुए नजर आए हैं। इससे घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन को नुकसान कम हो रहा है। इन क्षेत्रों में पिछले दो साल से शिकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। विलायती बबूल (जूली फ्लोरा) के कांटे गद्दीदार पैरों में चुभने से चंबल के बीहड़ से वन्यजीव तेंदुआ, लकड़बग्घा, सांभर, लोमड़ी, बारहसिंगा की आबादी खतरे में पड़ गई थी। 5 साल पहले दो-चार तेंदुए बीहड़ में दिखते थे। बाद में क्षेत्र में झाड़ियां कम होने और बड़े पत्ते वाले छायादार पेड़ लगाने के कारण वन्यजीवों का कुनबा बढ़ गया है। बबूलों की संख्या कम होने से तेंदुओं की आबादी बढ़ी। अब इनकी संख्या तीस के करीब है।

● **बृजेश साहू**

चंबल नदी में मगरमच्छों की संख्या में इजाफा

राजस्थान, मप्र और उप्र की सीमा से बहने वाली चंबल नदी में मगरमच्छों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि चंबल में सबसे ज्यादा घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुए पाए जाते हैं। चंबल नदी में वर्तमान समय में 2 हजार 108 घड़ियालों के साथ 878 मगरमच्छ और 96 डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जीव हैं। साल 1975 से 1977 तक विश्वव्यापी नदियों के सर्वे के दौरान 200 घड़ियाल पाए गए थे। जिनमें 46 घड़ियाल चंबल नदी के प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद विचरण करते हुए मिले थे। चंबल नदी के 960 किलोमीटर एरिया को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। तभी से देवरी घड़ियाल केंद्र पर कृत्रिम वातावरण में नदी से प्रतिवर्ष 200 अंडे निकालकर उनका लालन-पालन किया जाता है और 3 वर्ष बाद उन्हें चंबल में छोड़ दिया जाता है। चंबल नदी का सबसे अधिक एरिया 435 किमी मप्र की सीमा में आता है। चंबल नदी में जलीय जीवों की गणना का काम पहले मप्र के मुरैना जिले के चंबल अभ्यारण के अधिकारी करते थे।

नक्सली अमरकंटक को बना रहे हेड क्वार्टर

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों की सक्रियता से ठिठके नक्सलियों ने नया रेड कॉरीडोर बनाना शुरू कर दिया है। बस्तर को लालगढ़ में तब्दील करने के बाद नक्सलियों ने लाल आतंक के कॉरिडोर का विस्तार करने के लिए अमरकंटक की पहाड़ियों का सहारा लिया है। अमरकंटक को नक्सली अपना विस्तार हेड क्वार्टर बनाना चाहते हैं। इसके लिए, नक्सली मप्र के सतपुड़ा रेंज में आने वाले मैकाल की पहाड़ियों से लगे इलाकों को अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं। इन पहाड़ियों की ओर कवर्धा और बालाघाट, मंडला जिलों की सीमा आती हैं। इस इलाके में नक्सलियों की आमदरफ्त बढ़ रही है और वे छोटी-बड़ी वारदातें भी कर रहे हैं। नक्सलियों के स्ट्रैटिजिक प्लान में दुर्गम पहाड़ी और घने जंगल से मदद मिल सकती है। अमरकंटक का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, जिससे प्रदेश बदलने में आसानी होगी। अमरकंटक के घने जंगल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अब भी आवागमन सुलभ नहीं है। अंबिकापुर, सूरजपुर व बालाघाट से महाराष्ट्र के बीच कॉरिडोर का अहम क्षेत्र है।

इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के अनुसार, प्रदेश में प्रभावी नक्सल ऑपरेशन के बाद नक्सली नए ठिकाने की तलाश में हैं। बालाघाट जिले में पिछले 1-2 साल में बड़े नक्सल विरोधी अभियान ने मप्र में नक्सलियों की जमीन हिला दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 13 से अधिक हार्डकोर नक्सलियों को 8 ऑपरेशन के दौरान पकड़ा जा चुका है। ये वे नक्सली थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आतंक मचाने के बाद मप्र के बालाघाट जिले में ठिकाना बना रखा था। अब मप्र **पुलिस के एक्शन** के बाद नक्सली नए छत की तलाश में हैं। अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियां उनके लिए एक पसंदीदा क्षेत्र साबित हो सकता है। यहां के घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियां उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मां नर्मदा का उद्गम स्थल नक्सल समस्या से घिर जाएगा। पूर्व में भी कई बार अमरकंटक से होकर नक्सलियों के कॉरिडोर की चर्चा रही है। नक्सली अपनी मूवमेंट के लिए दुर्गम रास्तों का इस्तेमाल करते रहे हैं।

नक्सली मप्र में सुरक्षित स्थान को अपना विस्तार हेड क्वार्टर बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अमरकंटक को चुना है। दरअसल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ हाल ही में बड़ी कार्रवाई की है। इसीलिए नक्सली वहां से भागकर अमरकंटक से ऑपरेशन ऑपरेट करना चाहते हैं। इंटेलिजेंस को मिले इनपुट के बाद नक्सल प्रभावित जिलों में लगे फोर्स की नजर अमरकंटक पर टिक गई है। नक्सलियों ने साल 2016-2017 से अमरकंटक में विस्तार हेड क्वार्टर खोलने के लिए सर्वे शुरू किया था। इसके बाद चोरी-छिपे वहां उनका मूवमेंट शुरू हुआ। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का हेड ऑफिस बस्तर अंचल के अबूझमाड़ में है। अबूझमाड़ का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ आंध्रप्रदेश में पढ़ता है। विगत वर्षों में बालाघाट में हुए एनकाउंटर में पुलिस को नक्सलियों से दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद खुलासा हुआ कि उनकी योजना अमरकंटक में विस्तार हेड क्वार्टर खोलने की है। यदि वे अमरकंटक में विस्तार हेड क्वार्टर खोलने में सफल नहीं हुए तो संभवत: बालाघाट में हेड क्वार्टर खोला जाएगा।

प्रदेश की प्रमुख नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के साथ ही अमरकंटक का धार्मिक महत्व भी है। यहां ऊंची पहाड़ियों के साथ ही घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियों के अलावा सबसे जरूरी छत्तीसगढ़ से सीधा जुड़ाव है। अमरकंटक की आधी पहाड़ियां मप्र में हैं तो शेष छत्तीसगढ़ में। नक्सली ऐसे क्षेत्र को पसंद करते हैं जहां से वारदात के बाद आसानी से दूसरे प्रदेश तक पहुंचा जा सके। महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ की सीमा पर प्रदेश के बालाघाट जिले का लोकेशन नक्सलियों के लिए बेहद अहम रहा है। पुलिस की जांच में कई बार स्पष्ट हुआ है कि समीपी प्रदेशों में वारदात के बाद नक्सलियों ने बालाघाट के जंगलों में शरण ली है। बालाघाट में पुलिस ने बीते 5 साल में 20 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। इन नक्सलियों पर मप्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ से ज्यादा का ईनाम था। पांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का ईनाम घोषित था। इस बीच पिछले दो साल में प्रदेश के विशेष दस्ते ने 8 बार नक्सल क्षेत्रों में दबिश देकर उनके प्लान नाकाम भी किए। यहां 13 नक्सलियों को भी पुलिस ने ढेर किया है। बालाघाट में उनके गुप्त ठीहों पर बढ़ती मूवमेंट के बाद नक्सली नए ठिकाने की तलाश में लगे हैं। आईजी एंटी नक्सल ऑपरेशन अंशुमन सिंह का कहना है कि पुलिस लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। घने जंगलों का फायदा नक्सली उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों की कार्रवाई के चलते नक्सलियों के नेटवर्क को पुलिस ने कमजोर किया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ मिलकर इन इलाकों में ज्वाइंट कैंप और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

मप्र में फ्लॉप हुआ नक्सलियों का प्लान

पुलिस अफसरों के अनुसार बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में नक्सली गतिविधियां चलती हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जब घेराबंदी बढ़ती है। तभी नक्सलियों ने अमरकंटक होते हुए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आए को अपना ठिकाना बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस की सक्रियता बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी योजना स्थगित कर दी है। इस तरह मप्र में नक्सलियों पर नियंत्रण किया गया है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने बताया कि अब उनकी संख्या 75 के आसपास है। आपको बता दें कि मंडला और डिंडोरी में भी नक्सली गतिविधियां चलती हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया के 5 वर्ष पहले प्रदेश के नक्सल प्रभावित तीनों जिलों में पुलिस के 20 कैंप थे, अब 43 हैं। इनमें अकेले बालाघाट में ही 18 कैंप संचालित हो रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से पुलिस नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित कर रही है।

वन नेशन-वन इलेक्शन क्या होगा साकार...?

एक देश-एक चुनाव के लिए देश में नहीं है पर्याप्त सुविधा और संसाधन

विपक्षी पार्टियों को इसके लिए तैयार करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में 2029 तक इससे जुड़ी तैयारियों को पूरा करने का सुझाव दिया है। ऐसे में यदि इस पर अमल हुआ तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। यह तब संभव होगा जब इससे जुड़ा विधेयक अगले साल के मई तक पारित हो जाए।

● राजेंद्र आगाल

देश में वन नेशन-वन इलेक्शन का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट की ओर से सर्वसम्मति से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने वन नेशन-वन इलेक्शन को हरी झंडी दी है। इसके बाद संसद, संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के साथ सरकार आगे इस दिशा में रास्ता तय करेगी। लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वन-नेशन वन इलेक्शन का सपना साकार होगा। दरअसल, एक देश-एक चुनाव के लिए सरकार, चुनाव आयोग, सुरक्षा एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। वर्तमान समय में देश एक साथ सभी चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। शायद यही वजह है कि एक तरफ मोदी सरकार वन नेशन-वन इलेक्शन की बात कर रही है, वहीं **दूसरी तरफ** राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं।

भारत में एक देश-एक चुनाव (वन नेशन-वन इलेक्शन) पर चर्चा चल उठी है। हालांकि हमारे देश में एक देश-एक चुनाव कोई नई बात नहीं है, बल्कि आजादी के बाद शुरुआती कई सालों तक भारत में **एक देश-एक चुनाव** ही होता था। यानी कि सभी राज्यों के विधानसभा और केंद्र सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई, जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा। भारत जैसे बड़े देश में हर कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, पूरे देश का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है, राजनीति तेज होती है, चुनाव आयोग हरकत में आता है, सुरक्षा सहित तमाम सरकारी इंतजाम करने होते हैं, आचार संहिता लागू होती हैं और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जनता के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों का क्रम बार-बार बाधित होता है। एक देश-एक चुनाव की धारणा में राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ होंगे ताकि आने वाले कई सालों तक निर्बाध रूप से सरकारें कार्य कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इसके समर्थक रहे हैं और कई बार इसका उल्लेख भी करते रहे हैं। एक देश-एक चुनाव का विचार कम से कम **1983 से ही चला** आ रहा है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इस पर विचार किया था। हालांकि, 1967 तक, भारत में एक साथ चुनाव कराना एक आदर्श नियम था।

गौरतलब है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किया गया था। यह प्रथा 1957, 1962 और 1967 में हुए तीन आम चुनावों में भी जारी रही। हालांकि, 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया। 1970 में, लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में नए चुनाव कराए गए। इस प्रकार, पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।

एक साथ चुनाव कराने के फायदे

साल 1950 में गणतंत्र होने के बाद, 1951 से लेकर 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। देश में मतदाताओं ने साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान किया। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968-69 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एक देश-एक चुनाव कराने से केंद्र के राजकोष की बचत होगी। क्योंकि, हर 5 साल में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनावों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं, देश में हर साल अलग-अलग समय पर विधासनभा चुनाव होते हैं। इसकी जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। एक ही समय पर चुनाव होने पर राजकोष की बचत होगी। चुनाव के समय राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाती है और यह परिणाम जारी होने तक लागू रहती है। ऐसे में इससे विकास परियोजनाओं में देरी होती है। एक देश-एक चुनाव में ऐसा नहीं होगा। चुनाव के दौरान अक्सर जांच एजेंसियों द्वारा कालेधन के उपयोग को लेकर आरोप लगते हैं। ऐसे में एक देश-एक चुनाव होने पर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। चुनाव के समय देशभर में फोर्स से लेकर विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। इससे उनके सरकारी काम में भी व्यवधान होता है। ऐसे में साल में एक ही बार में इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। यदि एक ही चुनाव होता है, तो इससे वोटिंग पैटर्न का मुद्दा बदलेगा और इससे स्थानीय पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत में कई छोटी पार्टियां हैं, जो कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में एक देश-एक चुनाव में छोटी पार्टियों के अस्तित्व पर खतरा है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों को इससे फायदा होगा। यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं, तो इसमें एक साथ अधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर एक बार में अधिक फोर्स व ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सरकार को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा।

लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के समय से पहले विघटन और कार्यकाल विस्तार के परिणाम स्वरूप, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव हुए हैं, और एक साथ चुनाव कराने का चक्र बाधित हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1970 में लोकसभा भंग करवा दी थी और तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में आम चुनाव करवा दिए थे। इंदिरा अल्पमत सरकार चला रही थीं और पूर्ण सत्ता चाहती थीं। उनके इस फैसले ने राज्य विधानसभा चुनावों को आम चुनाव से अलग कर दिया था।

एक देश एक चुनाव क्यों?

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सबसे बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया।

गौरतलब है कि देश में इनके अलावा पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव भी होते हैं किंतु एक देश-एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। आपको बता दें कि एक देश-एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। यह देश के लिए कितना सही होगा और कितना गलत, इस पर कभी खत्म न होने वाली बहस की जा सकती है। लेकिन इस विचार को धरातल पर लाने के लिए इसकी विशेषताओं की जानकारी होना जरूरी है। एक देश-एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा

आयोग को जुटानी होंगी 25 लाख ईवीएम

कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिशों में निर्वाचन आयोग को भी समय रहते जरूरी तैयारियों को जुटाने का सुझाव दिया है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए, तो आयोग को 25 लाख और अतिरिक्त ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा समय में आयोग के पास करीब 25 लाख ईवीएम मशीनें हैं, जो लोकसभा के साथ ही अभी सिर्फ पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए ही पर्याप्त हैं। इसके लिए कम से कम तीन साल का समय और 8 हजार करोड़ से अधिक रुपए की भी जरूरत होगी। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव कराने की राह में अधिक दिक्कत नहीं है। सिर्फ ईवीएम की और जरूरत होगी। मौजूदा समय में ईवीएम तैयार करने वाली सरकारी कंपनियों की क्षमता साल में अधिकतम 10 लाख मशीनें तैयार करने की ही है। ऐसे में 25 लाख अतिरिक्त मशीनों को तैयार करने में समय लगेगा। उन्होंने बताया कि एक साथ चुनाव के लिए मैनपावर पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अभी कुल 12 लाख मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए 70 लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। एक साथ चुनाव कराने पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पोलिंग ऑफिसर की और तैनाती देनी होगी। यानी 12 लाख कर्मचारियों की और जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा बलों की भी कुछ ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन इसे ज्यादा चरणों में चुनाव कराकर स्थिर रखा जा सकता है।

और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है।

एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है। इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किंतु इन सबसे इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा।

यह विकासोन्मुखी विचार

एक देश-एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया की मनाही रहती है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सके। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो **आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी,** और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा।

एक देश-एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे बार-बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक देश-एक चुनाव के पक्ष में दिए जाने वाले तीसरे तर्क में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में किए जाने वाले खर्च

कई देशों में एक देश-एक चुनाव

विश्व के कई देशों ने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक देश-एक चुनाव के मॉडल की विविधताओं को अपनाया है। अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के लिए चुनाव हर चार साल में एक निश्चित तारीख पर होते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि देश में सर्वोच्च कार्यालयों का चुनाव एक साथ कराया जा सके, जिससे एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। फ्रांस भी चुनाव कराने के लिए कुछ इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाता है। यहां हर 5 साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली (संसद के निचले सदन) के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यहां मतदाता एक ही मतदान प्रक्रिया के तहत राज्य के प्रमुख और उनके प्रतिनिधियों दोनों का चुनाव करते हैं। फ्रांस में एक देश, एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के लिए एक निश्चित कार्यकाल तय करना है। फ्रांस में राष्ट्रपति और विधायी चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं। जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करने वाले दल से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जिसे दो-चरणीय प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए उम्मीदवार पहले दौर में बहुमत हासिल करने की कोशिश करता है। यदि इस प्रक्रिया में कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाता है, तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर की प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। फ्रांस में नेशनल असेंबली के सदस्यों को एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है। साथ ही इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। स्वीडन में चुनाव के जिस मॉडल को अपनाता है उसके तहत संसद और स्थानीय सरकार के लिए आम चुनाव हर 4 साल में एक साथ आयोजित कराए जाते हैं। वहीं नगरपालिका और काउंटी परिषद चुनाव, राष्ट्रीय चुनावों के साथ होने से मतदाताओं को एक ही दिन में कई चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका देती है। इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय और स्थानीय विधायिकाओं के कार्यकाल को सिंक्रोनाइज किया जाता है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के विभिन्न स्तरों के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। स्वीडन में इस चुनावी प्रक्रिया के चलते चुनावी दक्षता और मतदाताओं की सक्रियता दोनों को ही बढ़ावा मिलता है। साथ ही इस प्रक्रिया से अलग-अलग चुनाव कराने का प्रशासनिक बोझ भी कम होता है। वहीं, कनाडा एक देश, एक चुनाव प्रणाली का सख्ती से पालन नहीं करता है। यहां हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव हर 4 साल में कराए जाते हैं। जो कि देश को राष्ट्रीय स्तर पर एक सुसंगत चुनावी ढांचा देता है। इसके अलावा देश के कुछ प्रांत स्थानीय स्तर के चुनावों को संघीय चुनावों के साथ कराते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए संघीय चुनाव हर 4 साल में होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री निश्चित कार्यकाल के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर चुनाव का आह्वान करते हैं।

की सीमा निर्धारित की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को **सामाजिक समरसता भंग करने का** मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती हैं। एक साथ चुनाव कराए जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इसके पक्ष में चौथा तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही और वे अपने कर्त्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। आपको बता दें कि हमारे यहां चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, निर्बाध चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा बार-बार होने वाले चुनावों से आम जन-जीवन भी प्रभावित होता है।

संविधान में प्रावधान नहीं

एक देश-एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएं पांच वर्षों के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद-2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद-3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है, जहां अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2)(ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को पांच वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद-356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहां फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी परिस्थितियां एक देश-एक चुनाव के नितांत विपरीत हैं।

एक देश-एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढांचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। भारत का संघीय ढांचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनावों की बारंबारता एक अकाट्य सच्चाई है। एक देश-एक चुनाव के विरोध में तीसरा तर्क यह है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएं या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। दरअसल लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव जहां राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए होते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार का गठन करने के लिए होते हैं। इसलिए लोकसभा में जहां राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे आगे रहते हैं। इसके विरोध में चौथा तर्क यह है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा

क्या होंगी चुनौतियां?

लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश-एक चुनाव संभव नहीं होगा। लोकसभा की तरह ठीक विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भी 5 साल से पहले भंग हो सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने चुनौती होगी कि एक देश-एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखा जाए। एक देश-एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस पर सभी पार्टियों के अलग-अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि एक देश-एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यानी कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग होते हैं, जिस वजह से ईवीएम और वीवीपैट की सीमित संख्या हैं, लेकिन अगर एक देश-एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक साथ इन मशीनों की अधिक मांग होगी, जिसकी पूर्ति करना बड़ी चुनौती होगी। अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षाबलों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। मौजूदा समय में भाजपा का एक दर्जन से अधिक राज्यों पर कब्जा है। किंतु हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, झारंखड, बिहार और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों की भूमिका अहम होगी। कोविंद कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद-83 और 172 में संशोधन की सिफारिश की है। अनुच्छेद-83 लोकसभा और अनुच्छेद-172 राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को नियंत्रित करता है। इनमें संशोधन के बाद ही एक साथ चुनाव का रास्ता साफ होगा। वन नेशन-वन इलेक्शन पर आम सहमति बनाने का एक रास्ता यह भी है कि सरकार संशोधन विधेयकों को संसदीय समिति में भेज दे। इन समितियों में विपक्षी सदस्य भी होते हैं। समिति में चर्चा के बाद इस मुद्दे पर आम सहमति बनाई जा सकती है। सरकार को पूरे देश में चुनाव एक साथ कराने की खातिर काफी मंथन करना होगा, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग साल में होते हैं। ऐसे में कुछ राज्यों में समय से पहले और कुछ में देरी से चुनाव कराने होंगे। कोविंद कमेटी की सिफारिशों को आगे बढ़ाने की खातिर एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। वहीं देशभर में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। वन नेशन-वन इलेक्शन को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे।

जाता है। देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी। एक देश एक चुनाव के विरोध में पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना तार्किक प्रतीत नहीं होता।

आगे की राह

एक देश-एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, किंतु राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य में लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है। चुनावों के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधार, कालेधन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यदि देश में एक देश-एक कर यानी जीएसटी लागू हो सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करें ताकि इसे अमलीजामा पहनाया जा सके। कैबिनेट से एक

देश-एक चुनाव पर लगी मुहर के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में यह कब से लागू होगा। रामनाथ कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिशों में 2029 तक इससे जुड़ी तैयारियों को पूरा करने का सुझाव दिया है। ऐसे में यदि इस पर अमल हुआ तो 2029 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते है। यह तब संभव होगा जब इससे जुड़ा विधेयक अगले साल के मई तक पारित हो जाए। उसके बाद ही एक साथ चुनाव की एक तारीख भी निर्धारित करनी होगी। कमेटी को दिए अपने सुझाव में विशेषज्ञों ने इसके अमल को लेकर जो रोडमैप तैयार किया है, उसके तहत जैसे ही एक साथ चुनाव की तारीख निर्धारित हो जाएगी तो उसके बाद राज्यों के जो चुनाव होंगे वह उस तारीख को ध्यान में रखते हुए बची अवधि के लिए होंगे।

उदाहरण के लिए यदि एक साथ चुनाव की तारीख अप्रैल 2029 में होना तय हो जाता है तो 2027 में होने वाले उप्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव अगले दो सालों के लिए होंगे। विशेषज्ञों की मानें तो वैसे तो इन राज्यों के कार्यकाल संविधान संशोधन के जरिए बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होने पर विपक्षी दल सवाल खड़ा करेंगे। ऐसे में बची अवधि के लिए चुनाव कराना सही विकल्प होगा। यह बात अलग है कि यदि निर्धारित तारीख से किसी राज्य का कार्यकाल छह महीने या फिर उससे कम ही बचता है तो फिर चुनाव की जगह उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जानकारों की मानें तो इससे जुड़ी सारी स्पष्टता सरकार की ओर से लाए जाने वाले विधेयकों में साफ होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2028 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनको विधानसभा कार्यकाल के आधार पर निर्धारित किया गया है। इनमें 2024 में अभी महाराष्ट्र का चुनाव होना है, जबकि 2025 में झारखंड, दिल्ली व बिहार के चुनाव होंगे। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव है। वर्ष 2027 में उप्र, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, और मणिपुर के विधानसभा चुनाव हैं, जबकि वर्ष 2028 में दस राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मप्र, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं।

18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। किंतु इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की राह इतनी भी आसान नहीं है। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है। यानी संविधान में संशोधन करने की खातिर केंद्र सरकार को संसद में विधेयक लाना होगा। यही केंद्र सरकार की अग्निपरीक्षा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अधिकांश संशोधनों में राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा समय में एनडीए को 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 व राज्यसभा में 119 सदस्यों का समर्थन है। मगर संविधान संशोधन के पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ ही सदन में मौजूद व मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर मतदान वाले दिन लोकसभा के सभी 543 सदस्य सदन में मौजूद रहते हैं तो केंद्र सरकार को 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए। विपक्षी इंडी गठबंधन के लोकसभा में 234 सांसद हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के 113 सदस्य हैं और छह नामित सदस्यों का भी समर्थन मिलना तय है। वहीं इंडी गठबंधन के उच्च सदन में 85 सदस्य हैं। मतदान वाले दिन यदि सदन में सभी सदस्य मौजूद होते हैं तो दो-तिहाई 164 होगा। यानी इतने सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। छह राष्ट्रीय पार्टियों में से सिर्फ भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी एक साथ चुनावों के पक्ष में हैं। कांग्रेस, आप, बसपा और माकपा समेत 15 दलों ने इसका विरोध किया है। जिन पार्टियों ने कोविंद समिति के समक्ष एक साथ चुनाव का समर्थन किया था, लोकसभा में उनकी संख्या 271 है। वहीं विरोध करने वाले 15 दलों की संख्या लोकसभा में 205 है। लोकसभा में भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर उसे अपने सहयोगी और विपक्षी दलों को भी साधना पड़ सकता है। वहीं कुछ संवैधानिक संशोधनों को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार के सामने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक मतदाता सूची और एक मतदाता पहचान पत्र से जुड़े संशोधनों का देश के आधे राज्यों की विधानसभा से अनुमोदन मिलना जरूरी है। केंद्र सरकार को इसमें राज्यों को भी शामिल करना होगा। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े संशोधन पर भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी है।

धरती के स्वर्ग पर होगा किसका राज!

जीत की रणनीति के साथ मैदान में भाजपा

5 अगस्त 2019 के दिन केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद एक दशक बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 90 सीटों की विधानसभा के लिए 3 चरणों में जम्मू-कश्मीर में मतदान किया जा रहा है। सीटों का पुनर्सीमांकन होने के बाद जम्मू-कश्मीर में सीटों की संख्या 90 हो गई है जिसमें जम्मू में 43 तथा श्रीनगर में 47 सीटें हैं। याद रहे कि 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां 65.52 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान हुआ था। तब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस दौरान भाजपा को 23 सीटें मिली थीं जबकि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें तो कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं। इसके बाद केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के साथ ही अनुच्छेद 370 खत्म करने की नीति लागू की गई थी। जिसका असर इन चुनावों में देखने को मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर में अगर क्षेत्र-वार पार्टियों की स्थिति को देखें तो कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं। यहां भाजपा के लिए कश्मीर में सबसे कठिन स्थिति बताई जा रही है। पार्टी के अतीत को देखें तो पार्टी ने घाटी में कभी एक भी सीट नहीं जीती है। सियासी जानकारों की मानें तो पार्टी का गढ़ या थोड़ी मजबूत सीटें जम्मू में हैं। हालांकि जम्मू में 11 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर भाजपा को पिछले तीन चुनावों में जीत नहीं मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अधिकांश मुश्किल सीटें जम्मू क्षेत्र में हैं। जानकारी के अनुसार उसकी सभी मजबूत सीटें कश्मीर घाटी में हैं। हालांकि कश्मीर में 17 सीटें ऐसी हैं जिन पर वह पिछले तीन चुनावों में जीत नहीं पाई है। पीडीपी की बात करें तो उसके लिए अधिकांश कठिन सीटें 51 में से 33 जम्मू में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह इसकी मजबूत सीटें कश्मीर में हैं। हालांकि कश्मीर में 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर उसे पिछले तीन चुनावों में जीत नहीं मिली है।

अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की जिसके लिए अधिकांश कठिन सीटें 52 में से 38 कश्मीर में हैं। इसकी थोड़ी मजबूत सीटें जम्मू में हैं। वैसे कांग्रेस जम्मू की 13 सीटों पर पिछले तीन चुनावों में जीत हासिल करने में विफल रही है। जम्मू-कश्मीर में हुए नए परिसीमन के अनुसार जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं जबकि कश्मीर घाटी में सिर्फ एक सीट बढ़ी है जो सीट पहले 46 थी वह बढ़कर 47 हो गई हैं। फिलहाल नए परिसीमन से जम्मू-कश्मीर में 90 सीटें हो गई हैं। यहां बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। इसके चलते भाजपा भले ही जम्मू में जीत हासिल कर ले, लेकिन वह अपने दम पर आधे के आंकड़े तक पहुंच जाए तो गनीमत है। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने पहले चरण की 24 सीटों में से आठ पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा कश्मीर घाटी में अभी भी बहुत कमजोर है। जम्मू की बात करें तो वहां इसकी 11 कमजोर सीटें हैं जिससे बहुमत पाना उसके लिए टेढ़ी खीर है। वैसे पार्टी कश्मीर में कुछ सीटें जीतने के लिए सज्जाद लोन की पार्टी, दलबदलुओं और निर्दलीय जैसे छोटे दलों पर भरोसा कर रही है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन की रणनीति पर असर पड़ सकता है। हालांकि पार्टी को यह भी उम्मीद है कि पीडीपी घाटी में अपना प्रदर्शन काफी बेहतर करेगी। पीडीपी का आंकलन करें तो पता चलता है कि 2019 और 2024 के आम चुनावों में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 फीसदी से कम वोट मिले थे। भाजपा को उम्मीद है कि घाटी की सीटें एनसी, पीडीपी और निर्दलीय, छोटी पार्टियों के बीच विभाजित हो जाएंगी। ऐसे में वह जम्मू क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। पिछले चुनावों की बात करें तो 1987 के चुनाव में 76 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने 29 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से दो को सफलता मिली थी। उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ने के बावजूद पार्टी ने 1996 में 53, 2002 में 58, 2008 में 64 और 2014 में 75 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। 2014 में भाजपा को उस समय सफलता मिली थी जब उसने पहली बार सत्ता में आकर पीडीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। वह सरकार 2018 में गिर गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सीधे शासन लागू किया और अनुच्छेद 370 व 35ए को हटा दिया।

● **रजनीकांत पारे**

गत लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने घाटी की तीन सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस फैसले पर खेद जताया था और विधानसभा चुनाव के दौरान सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा किया था। इसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि भले ही भाजपा को कश्मीर में जीत नहीं मिलती है लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और देश को संदेश देने के लिए पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। मगर पार्टी ने अपना इरादा बदल दिया। भाजपा ने दक्षिण कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों से आठ तो मध्य कश्मीर की 15 सीटों से छह और उत्तर कश्मीर की 16 सीटों से पांच पर ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा की घाटी में इतनी ताकत नहीं बढ़ी है जितना प्रचारित किया जा रहा है। कश्मीरी जनता भाजपा को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि जम्मू क्षेत्र में पार्टी का जनाधार मजबूत है। चिनाब वैली और पीर पंजाल क्षेत्रों में पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी रणनीति के तहत, पार्टी को सत्ता में आने के लिए जम्मू क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लेकिन ऐसा होगा इसमें राजनीतिक पंडितों को संदेह है। पिछले कुछ वर्षों की सियासी हवा को देखें तो इस दौरान महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की राजनीतिक जमीन बहुत कमजोर हुई है। पीडीपी के ज्यादातर पहली और दूसरी लाइन के नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उसमें से अल्ताफ बुखारी इंजीनियर की पार्टी के साथ जुड़ गए हैं तो कुछ सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े दिख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के लिए इधर कुआं, उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। 2014 के जम्मू- कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 22.7 प्रतिशत वोट मिले थे। पार्टी के बैनर पर 28 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, तब महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

हरियाणा की कास्ट पॉलिटिक्स

हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में इन दिनों 36 बिरादरी शब्द खूब चर्चा में है। एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा 36 बिरादरी की दुहाई दे रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियां बिरादरियों के समर्थन को लेकर अलग-अलग दावे भी कर रही हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के जरिए सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने का दांव चल रही है तो कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर एक रैली में बस यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है। भाजपा नेता भी 36 बिरादरियों के हितों की दुहाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं गांव की सामाजिक पंचायत और खाप की बैठकों में भी 36 बिरादरी का जिक्र सुना जा सकता है।

हरियाणा में कास्ट पॉलिटिक्स में राजनीतिक दलों द्वारा भले जाट बनाम गैर-जाट का दांव खेला जा रहा हो, लेकिन बात 36 बिरादरियों के हितों और प्रतिनिधित्व की हो रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार उतारे हैं तो भाजपा ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी को टिकट दिया है। इस तरह भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों का सिलेक्शन सीट के सियासी मिजाज के लिहाज से किया है, लेकिन दुहाई 36 बिरादरियों को लेकर चलने की दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा में आखिर में 36 बिरादरी क्या है और उनका सियासी महत्व कितना है?

बिरादरी का शब्द बरादर से आया है, जो एक कबीले या समान वंश वाली जनजाति के भाईचारे के लिए फारसी शब्द है। अंग्रेजी शब्द ब्रदर इसी से बना है, जिसे भारत में जाति और कौम से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग एक-दूसरे से उसकी जाति के बारे में जानने के लिए पूछ लेते हैं कि किस बिरादरी से हो। जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक कुमार भी मानते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में बिरादरी शब्द का प्रयोग जाति के लिए किया जाता है। इसी तरह हरियाणा में 36 बिरादरी का इस्तेमाल सर्व समाज के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां पर 36 से ज्यादा जातियां है।

हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग में आते हैं जबकि उप्र और राजस्थान जैसे राज्य में ओबीसी में हैं। जाट जाति की आबादी हरियाणा में करीब 25 से 27 फीसदी है। इसके बाद 21 फीसदी दलित समुदाय के लोग हैं, जो रविदासी और वाल्मिकी सहित अलग-अलग उप जातियों में बंटे हुए हैं। ओबीसी की आबादी 30 से 32 फीसदी है, जिसमें गुर्जर, यादव, सैनी, प्रजापति, कम्बोज, कुम्हार, सुनार (सोनार), लोहार सहित करीब 32 उपजातियां हैं। सवर्ण समुदाय में पंजाबी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य (बनिया) जैसी जातियां हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय भी अलग-अलग जातियों में बटा हुआ है।

विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच जब कोई प्रत्याशी किसी गांव में प्रचार के लिए जाता है तो गांव के लोग और समर्थक उसका स्वागत करते हैं। ऐसे में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि उनका स्वागत 36 बिरादरियों के द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पश्चिमी उप्र और राजस्थान में भी 36 बिरादरियों की बात सुनी जा सकती है। जाट से लेकर गुर्जर और मुसलमानों तक में यह बात कही जाती है कि 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन है। छह बार के पूर्व विधायक और पूर्व वित्तमंत्री संपत सिंह का कहना है कि 36 बिरादरी की बात सिर्फ मुहावरा है, क्योंकि हरियाणा में 36 से अधिक जातियां हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में मैंने सभी जातियों के बीच भाईचारे को मजबूत करने के लिए हिसार में अपने घर पर एक कार्यक्रम बुलाया और इसमें लगभग 85 जातियों के सदस्यों ने शिरकत की थी। हरियाणा के भाईचारा के लिए प्रचलन में 36 बारादरी का शब्द आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करते हैं, उसका मतलब जातियों की संख्या से नहीं है।

प्रोफेसर एसके चहल की माने तो अजमेर-मेरवाड़ा गजेटियर (1951) में 37 जातियों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता, लेकिन 36 का नहीं। मध्ययुगीन फारसी लेखक अपनी यात्रा वृत्तांत में उत्तर भारत में 36 बिरादरियों (कुलों या राज्यों) के अस्तित्व का उल्लेख करते हैं। 36 राजवंशों का उल्लेख राजपूतों के इतिहास में मिलता है। यह उसी तरह से है, जैसे 84 खाप का। इसका मतलब 84 गांवों की खाप पंचायत है, लेकिन सभी खापों का योग 84 गांव नहीं होता। इसी तरह 36 बिरादरी का प्रयोग सिर्फ एक मुहावरे की तरह है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न समुदायों को संदर्भित करने के लिए

ब्राह्मण वोटरों पर फोकस

हरियाणा में ब्राह्मण वोटर 8 से 9 फीसदी के बीच हैं। भाजपा ने इस बार के चुनाव में ब्राह्मणों को कांग्रेस से ज्यादा तवज्जो दी है। भाजपा ने 11 ब्राह्मणों पर दांव खेला है तो कांग्रेस ने 6 कैंडिडेट उतारे हैं। ब्राह्मण समुदाय एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन फिलहाल भाजपा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसी तरह हरियाणा में 9 फीसदी के करीब पंजाबी वोटर हैं, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने 10 उम्मीदवार उतार रखे हैं तो कांग्रेस ने 8 टिकट पंजाबी समुदाय के लोगों को दिए हैं। हरियाणा में जाट और गैर-जाट वोट की सियासी बिसात बिछाकर दो बार सत्ता अपने नाम करने वाली भाजपा इस बार अलग सोशल इंजीनियरिंग के साथ उतरी है और जाट वोटों को भी जोड़ने का दांव चल रही है। हरियाणा की आबादी में जाट 25 से 24 फीसदी हैं। माना जाता है कि जाट वोट बैंक भाजपा के साथ नहीं जाता है। हरियाणा में जाट ओबीसी का दर्जा हासिल करने के लिए कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन भाजपा इस मांग को पूरा नहीं कर सकी। किसान आंदोलन में भी जाटों की अच्छी खासी भागीदारी थी और पहलवानों के आंदोलन में भी यह समुदाय साथ खड़ा था। ऐसे में कांग्रेस जाट और दलित के साथ ओबीसी को भी साधने की कवायद में है। देखना है कि जाति की सियासी बिसात पर कौन हरियणा की बाजी अपने नाम करता है?

कांग्रेस ने जाट समुदाय पर किया फोकस

हरियाणा में जाट समुदाय सबसे बड़ा वोटबैंक है, जिसके हाथों में लंबे समय तक सत्ता की चाबी रही है। जाट समदुाय की आबादी 25 फीसदी से ज्यादा है। इसके बाद दलित समुदाय दूसरे नंबर पर आता है, जो करीब 20 से 22 फीसदी के बीच है। ओबीसी की आबादी भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन वो अलग-अलग जातियों में बंटे हुए हैं। 30 से 35 फीसदी के बीच ओबीसी मतदाता हरियाणा में है। इस तरह इन तीनों ही जातियों का वोट मिलाकर 70 से 75 फीसदी होता है। इसके बाद पंजाबी और ब्राह्मण 8-8 फीसदी, मुस्लिम 7 फीसदी, वैश्य 4 फीसदी और राजपूत दो फीसदी के करीब है। कांग्रेस और भाजपा ने उम्मीदवारों के सेलेक्शन में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। कांग्रेस ने जाट समुदाय पर फोकस किया है तो भाजपा ने ओबीसी समाज पर अपना दांव चला है। कांग्रेस ने 35 जाट, 20 ओबीसी, 17 दलित, 4 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 6 पंजाबी, दो वैश्य और एक राजपूत समुदाय से प्रत्याशी उतारा है। ऐसे ही भाजपा ने 16 जाट समुदाय को टिकट दिया है तो 24 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, दो मुस्लिम, 10 पंजाबी, 6 वैश्य और तीन राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं।

किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तव में 36 समुदाय हैं। माना जाता है कि हरियाणा चुनाव में नेताओं द्वारा 36 बिरादरियों के समर्थन की बात करके अपनी छवि को सर्व समाज के नेता के तौर पर दर्शाने की कोशिश की जाती है। सियासत में देखा गया है कि कई लोग एक खास वोटबैंक तक पहुंचने के लिए अपने जाति समूहों के हितों को ध्यान में रखना पसंद करते हैं। ऐसे में सर्व समाज का समर्थन हासिल करने के लिए 36 बिरादरी के सामाजिक हित की बात करते हैं।

2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते कांग्रेस को जाटों की पार्टी के तौर पर स्थापित करके गैर-जाट वोटों को साधने का दांव चला। ऐसे में माना जाता है कि हरियाणा में जाट वोट बैंक भाजपा के साथ नहीं जाता है। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जाट परस्त छवि को तोड़ने के लिए ही 36 बिरादरी के समर्थन की बात करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में जाट से लेकर दलित, ओबीसी, पंजाबी, ब्राह्मण और मुस्लिम को टिकट देकर 36 बिरादरी का समर्थन हासिल करने का दांव चला है। हरियाणा में जाट वोटों की सियासी ताकत और अहमियत को देखते हुए भाजपा भी जाट विरोधी छवि से बाहर निकलने की कोशिश में है। लोकसभा के चुनाव में जाट समुदाय ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था, जिसके चलते भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार के चुनाव में भाजपा ने 17 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी ही नहीं दो मुस्लिम को भी टिकट देकर 36 बिरादरी का संदेश देने की कवायद की है।

हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक बनता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपने-अपने राजनीतिक दांव चल दिए हैं। हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति के मुद्दे पर सिमटता जा रहा है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रही है तो कुमारी सैलजा के बहाने भाजपा ने कांग्रेस को दलित विरोधी कठघरे में खड़ा करने का दांव चला है। ऐसे में हरियाणा का चुनाव जातीय और आरक्षण के मुद्दे पर सिमटता जा रहा है। हरियाणा की जातीय सियासत का असर अतीत में हुए चुनाव में देखने को मिलता रहा है। जाट बनाम गैर-जाट वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। कांग्रेस के दांव से ही भाजपा ने उसे मात देने की स्ट्रैटेजी बना रखी है। सूबे की सत्ता की दशा और दिशा जाट, ओबीसी और दलित समुदाय तय करते हैं। इन्हीं तीनों जातियों के इर्द-गिर्द भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने दांव खेले हैं। ऐसे में देखना है कि किसका समीकरण सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का काम करता है।

भाजपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों ने हरियाणा चुनाव में जाति के बिसात पर अपने-अपने सियासी मोहरे सेट किए हैं। भाजपा और कांग्रेस 89-89 सीट पर चुनाव लड़ रही। कांग्रेस ने एक सीट सीपीआई-एम के लिए छोड़ी है जबकि भाजपा के एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया है।

हरियाणा के सियासी मिजाज को समझते हुए कांग्रेस और भाजपा ने अपनी-अपनी सियासी बिसात बिछाने की कवायद की है। भाजपा गैर-जाट वाली सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लगातार दो बार हरियाणा की जंग फतह कर चुकी है और अब सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए उतरी है। भाजपा ने ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी के साथ जाटों पर भी भरोसा जताया है। इसके अलावा दलित समुदाय के लिए सुरक्षित 17 सीट पर कैंडिडेट उतारे है। भाजपा की सियासत अभी तक गैर-जाट वोटों को हासिल करने पर रही है, लेकिन इस बार उसकी कोशिश जाटों को भी साथ लेकर चलने की है। भाजपा इस बात को समझ रही हैं कि वो जाट वोटों के बिना सत्ता की जंग फतह नहीं कर सकती है।

भाजपा दलित वोटों को साधने के लिए कुमारी सैलजा के मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ सियासी हथियार बनाने में जुटी है। राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए आरक्षण वाले बयान को भाजपा नेता अपनी हर रैली में उठा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक ने आरक्षण और सैलजा के बहाने दलितों को अपने पाले में लाने की कवायद की है। भाजपा की कोशिश जाट, ओबीसी, दलित के साथ ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के वोटबैंक को साधने की है। इसीलिए पार्टी ने पूरा दांव इन्हीं पर बिछा रखा है। हरियाणा में ओबीसी वोटर 30 से 35 फीसदी है। भाजपा ने ओबीसी वोटों के अपने पाले में रखने के लिए 24 प्रत्याशी उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस ने 20 सीटों पर टिकट देकर सियासी संदेश देने का दांव चला है। भाजपा ने ओबीसी चेहरे से आने वाले नायब सिंह सैनी को आगे कर रखा है तो गुर्जर और यादव समाज पर भी बड़ा भरोसा जताया है। कांग्रेस की नजर ओबीसी वोटों को अपने पाले में रखने ही है, लेकिन जाट और दलित वोटों को खास अहमियत दी है। ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जाट-दलित समीकरण के साथ ओबीसी, पंजाबी और मुस्लिम को भी साधकर रखने की है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही 36 बिरादरी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन 30 से 35 फीसदी ओबीसी को सिर्फ 20 टिकट दिए हैं तो जाट समुदाय से 35 प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे ही भाजपा ने मेवात बेल्ट में मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को देखते हुए दो प्रत्याशी उतारे हैं तो कांग्रेस ने पांच मुस्लिमों को टिकट दिया है। सात फीसदी के करीब मुस्लिम वोटर कांग्रेस का कोर वोटबैंक माना जाता है, लेकिन इनेलो और जेजेपी जैसे दलों ने भी उस पर दांव खेला है।

● **विपिन कंधारी**

कंगना रनौत की पॉलिटिकल लॉन्चिंग अब भाजपा के लिए भारी पड़ती दिख रही है। पिछले एक महीने में कंगना अपने 2 बयानों से भाजपा को बैकफुट पर धकेल चुकी हैं। हालांकि, कंगना पहली महिला नेता नहीं हैं, जिनकी सियासी एंट्री भाजपा के लिए आफत बन गई हो। फेहरिस्त में और भी चर्चित चेहरे हैं।

नेत्रियों के बिगड़े बोल...

बॉलीवुड से राजनीति में आई कंगना रनौत की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। किसान को लेकर कंगना के एक पुराने बयान का बवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि मंडी से भाजपा सांसद ने दूसरा बयान दे दिया है। वो भी ऐसा बयान, जो भाजपा के लिए सियासी वज्रपात साबित हो रहा है। हालांकि, कंगना पहली महिला राजनेता नहीं हैं, जिनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग भाजपा के लिए सियासी आफत बन गई हो। कंगना से पहले उप्र की स्वाति सिंह और मप्र की प्रज्ञा ठाकुर भी देश की सबसे बड़ी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा चुकी हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कंगना रनौत की भाजपा में एंट्री हुई। भाजपा में आते ही कंगना ने जमकर माहौल बनाया। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कंगना खूब बोली। स्टार एक्ट्रेस होने की वजह से मीडिया ने भी कंगना को खूब तवज्जो दी। चुनाव की जब घोषणा हुई, तो भाजपा ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से उम्मीदवार बना दिया। इस सीट से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद थीं। कांग्रेस ने उनके बेटे विक्रमादित्य को यहां से मैदान में उतारा, लेकिन कंगना चुनाव जीतने में सफल रहीं। सांसद बनने के बाद कंगना ने विवादित बयान देना शुरू किया। पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के वक्त लोगों के साथ रेप हुए। कंगना का यह बयान भाजपा के लिए सियासी वज्रपता जैसा था। वजह हरियाणा का चुनाव। पार्टी ने तुरंत बयान जारी कर कंगना को नसीहत दी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अब कंगना का एक और वीडियो मीडिया में आ गया। कंगना इस वीडियो में कह रही हैं कि फिर से 3 रद्द किए गए कृषि कानून लाने पर विचार हो। कंगना के इस बयान से पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। हरियाणा में सत्ता की चाभी किसानों के पास ही है। किसानों को साधने के लिए भाजपा हरियाणा में लगातार कई बड़ी घोषणाएं कर रही है। हरियाणा सरकार से जुड़ी एक एजेंसी के मुताबिक राज्य में जोत किसानों की संख्या करीब 16 लाख है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कंगना का यह बयान भाजपा की टेंशन बढ़ा सकता है।

हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने मांग करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को फिर से लाना चाहिए जिन्हें भारी विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। ये तीनों कानून किसानों के हित में थे और उन्हें खुद इसे वापस लाने की मांग करनी चाहिए। हालांकि खुद कंगना रनौत ने कहा, हो सकता है कि उनकी इस बात पर विवाद हो, लेकिन इसे लागू करना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने भी कंगना के बयान पर अपनी नाराजगी जताई है। केसी त्यागी ने कहा, भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर हरियाणा में तीनों कृषि कानून मुद्दा बने हुए हैं। इस तरह की बयानबाजी करके कंगना आखिर किसकी मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा, आज हरियाणा में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुरुपयोग करने के लिए कर रही हैं। इस तरह के बयानों से भाजपा और एनडीए की छवि खराब होती है। इसके लिए भाजपा या प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को दोष देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री ने पहले ही स्थिति साफ कर चुके है। सरकार लगातार किसानों के संपर्क में भी है। करीब 24 फसलों की एमएसपी पहले से बढ़ा दी गई है।

क्या इस बार गलत हो गई टाइमिंग

सांसद बनने के बाद कंगना ने कई बार अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पर उनको सलाह भी दे चुके हैं। इस बीच, कंगना का एक और बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में निरस्त कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। कंगना ने ये बयान ऐसे समय दिया है जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राज्य में किसान किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में अहम होते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि किसान भारत के स्तंभ हैं और उन्हें अपनी समृद्धि के लिए कृषि कानूनों की मांग करनी चाहिए। कंगना के इस बयान से कांग्रेस को भाजपा पर हमलावर होने मौका मिल गया। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कंगना कह रही हैं कि कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह विवादास्पद हो सकता है, पर ये किसानों के हित में हैं।

हालांकि बयान देने के बाद विवाद बढ़ने पर कंगना ने अपना बयान वापस ले लिया। बयान वापस लेते हुए सांसद ने कहा, किसान कानून से संबंधित कुछ सवालों पर मैंने सुझाव दिया कि किसानों को किसान कानून वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करना चाहिए। लेकिन इस बात से बहुत से लोग निराश हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने बड़े संवेदनशीलता से कृषि कानूनों को वापस लिया था। मैं मानती हूं कि मेरे विचार अपने नहीं होने चाहिए, मेरी पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। अगर मैंने अपनी सोच से किसी को निराश किया है तो मुझे इसका खेद है। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। कांग्रेस इस बयान पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार को घोर अपराध का अहसास नहीं हुआ। इन तीनों काले कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की बात की जा रही है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, मैं चुनौती देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन तीनों काले कृषि कानूनों को फिर से लागू करवा सके। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार ने दिसंबर 2021 में तीनों कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, कहीं चूक हुई है।

2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव विस्फोट में आरोपी रहीं प्रज्ञा ठाकुर को मुख्यधारा की राजनीति में लाने का फैसला किया। साध्वी के नाम से मशहूर प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने 2019 के चुनाव में भोपाल से लड़ाने का फैसला किया। इस सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। जिन पर भाजपा अक्सर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। प्रज्ञा के जरिए भाजपा ने हिंदुत्व और तुष्टिकरण की राजनीति को साधने की कोशिश की। शुरुआत में प्रज्ञा हिंदुत्व और उससे जुड़े मुद्दों पर जमकर बोल रही थीं। प्रज्ञा की एंट्री से भाजपा को फायदा भी हुआ और पार्टी भोपाल की सीट बड़ी मार्जिन से जीत गई थी। प्रज्ञा ने इसके बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ानी शुरू की। प्रज्ञा ने पहले महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने गोडसे को सही ठहराते हुए गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया। मामले में जब पार्टी की किरकिरी हुई तो खुद प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना पड़ा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं प्रज्ञा को कभी माफ नहीं करूंगा। कहा जाता है कि भाजपा ने प्रज्ञा को इसके बाद साइडलाइन करना शुरू किया। यह विवाद थमा नहीं था कि प्रज्ञा ठाकुर ने महाराष्ट्र पुलिस के शहीद अधिकारी हेमंत करकरे पर विवादित टिप्पणी कर दी। हेमंत मुंबई हमले के दौरान आतंकियों के गोली से शहीद हुए थे। प्रज्ञा के इस बयान की पूरे देश में आलोचना हुई। महाराष्ट्र में भाजपा बैकफुट पर आ गई, जिसके बाद उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को इस पर सफाई देनी पड़ी। हालांकि, प्रज्ञा का विवादों से नाता नहीं टूटा। आखिर में 2024 के चुनाव में भाजपा ने प्रज्ञा का टिकट काट दिया। प्रज्ञा तब से राजनीतिक नेपथ्य में हैं। प्रज्ञा का न तो अब कोई विवादित बयान आ रहा है और न ही प्रज्ञा अब मीडिया की सुर्खियों में हैं।

हरियाणा में अहम हैं किसान मतदाता

कंगना ने बयान ऐसे समय दिया है जब हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। उनके इस बयान से भाजपा को नुकसान होता है या नहीं, ये नतीजे आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि सूबे में किसान मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है और वो किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में अहम होते हैं। चुनाव के बीच किसान के कुछ यूनियन भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वे किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेर रहे हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत हुई थी, जिसमें उन्होंने राज्य में भाजपा को सबक सिखाने और 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेल ट्रैक जाम करने की घोषणा की। हरियाणा में किसानों के समर्थन के बिना चुनाव जीतना नामुकिन है। यही वजह है कि भाजपा ने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने किसानों के घर-घर जाकर उन्हें केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हितों में उठाए गए फैसलों के बारे में जानकारी देने का फैसला किया है।

2017 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजना था। इसी बीच भाजपा के कद्दावर नेता दयाशंकर सिंह ने मायावती पर विवादित टिप्पणी कर दी। दयाशंकर के बयान को बीएसपी ने दलित विरोधी बयान बताया। बैकफुट पर आई भाजपा ने दयाशंकर सिंह को आनन-फानन में पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इसी बीच बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता दयाशंकर की पत्नी और बेटी पर विवादित टिप्पणी कर गए। राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखने वाली दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह ने इस टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वाति के मैदान में आने से भाजपा फ्रंटफुट पर आ गई। पूरे चुनाव में भाजपा ने स्वाति को खूब प्रमोट किया। 2017 में जब उप्र में भाजपा की सरकार बनी तो स्वाति को मंत्री बनाया गया। स्वाति पूरे 5 साल तक मंत्री रहीं। हालांकि, इस दौरान उनकी वजह से कई मौकों पर सरकार मुश्किलों में फंसती नजर आई। मंत्री रहते स्वाति एक बीयर शॉप का उद्घाटन करने पहुंच गई। मीडिया में जब खबर छपी तो पार्टी ने किनारा कर लिया। इसी तरह स्वाति का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वे एक महिला सीओ को धमकाती नजर आ रही थीं। इस मसले पर उप्र के डीजीपी को बयान देना पड़ा। चुनाव से एक महीना पहले स्वाति का एक और ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कथित तौर पर अपने पति दयाशंकर पर गंभीर आरोप लगा रही थीं। इन सब मामलों में सरकार की ही भद पिटी। आखिर में भाजपा ने 2022 के चुनाव में स्वाति का टिकट काट दिया। स्वाति अब राजनीति में हाशिए पर हैं।

ऐसे ही नूपुर शर्मा भाजपा प्रवक्ता के तौर पर एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थीं, तभी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक हदीस का जिक्र कर दिया। उस वक्त काशी-मथुरा के विवाद पर चर्चा चल रही थी। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद पर चर्चा के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी कर दी। उनकी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर शेयर किया और मुसलमान भड़क गए। मुसलमानों की तरफ से नूपुर शर्मा के कत्ल का ऐलान होने लगा। तब भाजपा ने उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निलंबित कर दिया था। यह घटनाक्रम जून 2022 का है। तब से अभी तक नूपुर शर्मा लाइमलाइट और मीडिया से दूर हैं।

● इन्द्र कुमार

छग में वंशजों का वर्चस्व

छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेताओं के वंशजों पर जनता की शुरू से नजर रही है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे आज राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कई दिग्गजों के बेटे आज राजनीति में सफल हैं तो कईयों ने सियासी मैदान से अपनी दूरी बना ली है। पीढ़ी परिवर्तन की ये प्रक्रिया करीब दो दशकों से जारी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिन बेटों ने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया उसमें कई नाम शामिल हैं। भाजपा हो या फिर कांग्रेस दोनों ही दलों में दिग्गज नेताओं के बेटे आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना अहम स्थान रखते हैं। बात चाहे रमन सिंह के बेटे की हो या फिर नंदकुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल की। ज्यादातर नेताओं के बेटे आज सियासत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। कुछ नाम ऐसे भी रहे जिन्होंने सिसायत के क्षेत्र से अपनी दूरी बना ली।

कांग्रेस में एक समय दो बड़े नाम होते थे मोतीलाल वोरा और पंडित श्यामाचरण शुक्ल। मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा, उन्होंने एक अच्छी लंबी पारी तो खेली लेकिन उनकी खुशकिस्मती देखिए की तीन बार लगातार चुनाव हारने के बाद भी उन्हें चौथी बार टिकट दिया गया। चौथी बार में वो चुनाव जीते। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए। वहीं अमितेश शुक्ल पंडित श्यामा चरण शुक्ल के बाद कि विरासत को वो बढ़ाते हुए नजर आए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव लेकिन वो राजिम से हार गए। अब वहां से अमितेश शुक्ल के बेटे भवानी शुक्ल का नाम राजनीति में आने लगा और अब वो सियासत के मैदान में स्थापित हो गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह चर्चा थी कि भवानी शुक्ला को महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। पर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया।

नंदकुमार पटेल कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। झीरम कांड में उनकी हत्या हो गई। पिता की विरासत को दीपक पटेल संभालते लेकिन उनकी भी मौत झीरम हमले में हो गई। पिता और भाई की मौत के बाद उमेश पटेल ने परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। साल 2013, 2018, 2023 का चुनाव जीते। सदन से लेकर पार्टी स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत है। उमेश पटेल राजनीति में अभी लंबी पारी खेलने को तैयार हैं। विजय कुमार गुरु के बेटे रूद्र गुरु की बात की जाए तो उनके पिता विजय कुमार गुरु अविभाजित मप्र के समय विधायक थे। रूद्र गुरु 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते और मंत्री भी बने। अब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें सामने आई हैं। आगे की उनकी राजनीतिक पारी कैसी रहेगी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है। वो युवा हैं और उनमें असीम संभावनाएं हैं। अजीत जोगी के बेटे में अमित जोगी की बात की जाए तो उनकी अपनी एक राजनीतिक शैली है, लेकिन वह कांग्रेस में जब तक थे, तब तक अपना महत्व था, उन्होंने अलग पार्टी बनाई पिता के साथ तब भी हलचल थी, लेकिन वर्तमान की बात की जाए, तो वह शांत नजर आ रहे हैं।

सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा की बात की जाए, तो वे अपने पिता की छाया बनकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जनता के बीच जाकर वो काम करते रहे हैं। कहा जाता है कि पंकज शर्मा में एक अच्छे नेता के जो गुण होने चाहिए वो नजर आते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में रायपुर ग्रामीण सीट से पंकज शर्मा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट मोतीलाल साहू से हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह हैं। रमन सिंह ने अपनी विरासत अपने पुत्र अभिषेक सिंह को दी है, जो की पूर्व में सांसद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने अभिषेक को राजनांदगांव से लड़वाना उचित नहीं समझा, जबकि वह उस दौरान सांसद थे। माना जाता है कि अभिषेक सिंह के पास राजनीति करने का लंबा वक्त है। लोकसभा में भी पांच साल बोल चुके हैं। उनका सियासी और बौद्धिक स्तर भी बढ़िया है। भाजपा के दिग्गज और अजेय नेता बृजमोहन अग्रवाल आठ बार के विधायक रहे। हाल ही में उन्होंने रायपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की टिकट से जीत हासिल की और सांसद बन गए। ऐसे में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हो गई। संभावना जताई जा रही है कि इस पर विजय अग्रवाल जो की बृजमोहन अग्रवाल के भाई हैं उनको टिकट दिया जा सकता है।

● रायपुर से टीपी सिंह

निगम और मंडल में किन नेताओं की होगी नियुक्ति

छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच प्राधिकरणों के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए कई सीनियर नेताओं को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद अब माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही निगम और मंडल की सूचियां भी जारी कर सकती है। राज्य में इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, इसके साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में विष्णुदेव साय की सरकार बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा से पहले सरकार निगम और मंडल में नियुक्तियां कर सकती है। इसके लिए कुछ नाम फाइनल भी कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, लिस्ट में भाजपा के कुछ सीनियर नेता, प्रवक्ताओं के साथ संगठन में काम कर चुके लोग भी शामिल हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेता भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि निगम और मंडल में उन नेताओं को भी जगह मिल सकती है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। संगठन से जुड़े लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि फाइनल लिस्ट कब जारी होगी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में संघ के पदाधिकारियों ने बैठक की थी। इस बैठक में राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत चार मंत्री भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि बैठक में निकाय चुनाव से पहले निगम और मंडल में नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनी थी। बैठक के बाद विजय शर्मा ने कहा था कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। जिस तरह अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है, उसी तरह महायुति में भी इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान आ रहे हैं। इसी क्रम में पुणे में अजित पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए अगले मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया कि महायुति की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आप भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं? तो इस सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता! एनसीपी अजित गुट के प्रमुख ने इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर भी अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की ओर से महायुति की सीट बंटवारे को लेकर बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की पहली प्राथमिकता महाराष्ट्र में सरकार बनाना है। महायुति के सभी दल इस मुद्दे पर एक साथ हैं। सीट तय होते ही हम इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन चर्चा है कि अजित गुट 80 से 90 सीटें मांग सकता है।

अजित पवार फिलहाल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पुणे में दगडूसेठ गणपति की पूजा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में स्थिरता और खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अजित पवार ने कहा कि हर पार्टी में सभी सदस्य मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे लेकिन इसके लिए आंकड़े भी होने चाहिए। उधर एनसीपी अजित गुट की महिला क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने अजित पवार के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनें। उन्होंने कहा कि गणपति से यही आशीर्वाद मांगा है। उधर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने महायुति और अजित पवार गुट पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि महायुति में सीट बंटवारे के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा है। उनका दावा है कि भाजपा दोनों दलों को कम सीटें देना चाहती है। संजय राउत का दावा है कि भाजपा अजित गुट और शिंदे गुट दोनों 40-40 सीटें देना चाहती हैं। संजय राउत का ये भी दावा है कि 288 सीटों की महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा खुद 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो अजित गुट और शिंदे गुट 60 से 70 सीटें मांग सकते हैं।

महाराष्ट्र की 240 सीटों पर भाजपा का अपना सियासी आधार है, लेकिन विपक्षी एकता के चलते कारगार साबित नहीं होती। इसलिए भाजपा को गठबंधन के लिए मजबूर होना पड़ता है। भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ सरकार चला रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 संसदीय सीटों में से भाजपा ने 28, शिवसेना ने 15, एनसीपी ने 4 और राष्ट्रीय समाज पक्ष ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। इस फॉर्मूले पर तीनों के बीच सीट शेयरिंग हुई थी। माना जा रहा है इस आधार पर विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारा हो सकता है, लेकिन अजित पवार और शिंदे की पार्टी तैयार नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच, महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने मुंबई की 36 सीटों में से 18 सीटों की मांग की है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद पैदा होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मुंबई की 36 सीटों में से 18 सीटों की मांग की है। इसमें मालाबार हिल जैसे विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र और धारावी जैसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती शामिल हैं। दूसरी ओर, शिवसेना ठाकरे समूह ने मुंबई में 20 सीटों की मांग की है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट ने 7 सीटों पर दावा किया है।

कांग्रेस ने मुंबई में 18 सीटों की मांग की है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने धारावी, चांदीवली, मुंबादेवी, मलाड वेस्ट, सायन कोलीवाड़ा, कोलाबा, कांदिवली ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, बांद्रा वेस्ट, घाटकोपर वेस्ट, कुर्ला, बायकुला, जोगेश्वरी ईस्ट, मालाबार हिल, माहिम, बोरीवली और चारकोप में चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना 20 सीटों पर अड़ी है। यह भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 7 सीटों पर दावा किया है। 2019 में ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई की 36 में से 19 सीटें जीती थी। भाजपा ने 11 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 28 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि एनसीपी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी।

राज्य में 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें जीती थी तो शिवसेना को 56 सीटें, एनसीपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। अब यह उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है कि विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट आवंटन का फॉर्मूला क्या होगा। गणेशोत्सव के बाद सीट आवंटन का फॉर्मूला तय करने के लिए मैराथन बैठक होगी। इसके मुताबिक, कांग्रेस 105 सीटों, शिवसेना ठाकरे गुट 100 सीटों और शरद पवार गुट ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसके मुताबिक कांग्रेस ने 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। शरद पवार गुट 85 से 90 तक की लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही ठाकरे ग्रुप ने 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

● **बिन्दु माथुर**

पिछले विधानसभा चुनाव का पैटर्न

पिछले तीन विधानसभा चुनाव में भाजपा के लड़ने का पैटर्न देखें तो 2014 से पहले और उसके बाद की स्थिति काफी बदल गई है। 2014 से पहले भाजपा महाराष्ट्र में छोटे भाई की भूमिका में थी लेकिन अब बड़े भाई के रोल में है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 2009 में भाजपा 119 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और शिवसेना ने 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इससे पहले 2004 में भाजपा 111 सीट पर तो शिवसेना 163 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस तरह भाजपा कम सीट पर तो शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्थिति बदल गई। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था और दोनों ही दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। भाजपा ने अकेले जब चुनाव लड़ा तो उसे अपनी सियासी ताकत का एहसास हुआ। 2014 में भाजपा ने 260 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 122 सीट पर उसको जीत मिली। भाजपा ने पहली बार महाराष्ट्र में 100 सीटें जीतने का आंकड़ा क्रॉस किया और पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने में भी सफल रही।

पावरफुल नेता पावरलेस

राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। यहां पर उन नेताओं के समर्थकों में मायूसी देखी जा रही है जो पिछले 30 सालों से यहां सिस्टम में थे। समर्थकों की तरह ही उनके नेता भी अपनी नई भूमिका के इंतजार में हैं। जबकि, वो कभी यहां पर खुद भूमिका तय किया करते थे। राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति में उनका हमेशा बड़ा कद रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद उनके कद में फर्क पड़ा। अब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद मुसीबत और बढ़ गई है। संगठन में भी होने वाले बदलाव पर अभी कुछ साफ नहीं है। राजस्थान के वो तीन नेता जो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन तीनों नेताओं का राजस्थान में अच्छा प्रभाव माना जाता है। लेकिन, अब उन्हें खुद नई भूमिका का इंतजार है। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

अशोक गहलोत राजस्थान के तीन बार के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब वो यहां सत्ता से दूर होते थे तो उन्हें केंद्र में मजबूत भूमिका मिल जाती थी। अभी तक उन्हें कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई है। कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि अब राजस्थान से युवा नेताओं को केंद्र में जगह दी जाएगी। इसी को लेकर सचिन पायलट की तरफ भी इंतजार है। क्योंकि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और पार्टी को जीत मिली थी। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में रखा गया है। लेकिन उनकी तरफ भी इंतजार है। राजस्थान की राजनीति में कुछ सालों तक वसुंधरा ही भाजपा की सर्वेसर्वा थी। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं हैं। हालांकि 2023 के बाद से उनके पास राजस्थान में कोई पद नहीं है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो क्या उन्हें संगठन में मजबूती दी जाएगी या यूं ही छोड़ दिया जाएगा। राजे को लेकर उनके समर्थक कुछ कह नहीं पा रहे हैं।

राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं का बड़ा नाम है। उनका बयान सत्ता के गलियारे में मायने रखता है। लेकिन वर्ष 2024 की शुरुआत से इन नेताओं की चर्चा बंद हो गई है। अब उनके समर्थकों में अटकलों का दौर चल पड़ा है। उनके पास संगठन में न महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और न ही सरकार में कोई बड़ा पद है। दिलचस्प बात है कि उनमें से ज्यादातर विधायक रह गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से इन नेताओं का बयान बहुत कम सुनने को मिलता है। अलबत्ता, एक-दो नेता समय-समय पर राजनीतिक तंज जरूर कसते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान सुर्खियों में आ गया था।

अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए अलग-अलग राज्यों में काम करते रहे हैं। कई राज्यों का प्रभार भी उन्होंने संभाला है। इस बार कांग्रेस की सरकार जाने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। अशोक गहलोत को लोकसभा में भी ज्यादा देखा नहीं गया। इसलिए अब उनके समर्थक मायूस हैं। अशोक गहलोत विधायक बनकर रह गए हैं। वसुंधरा राजे पिछले 25 सालों से संगठन और सरकार का मजबूत चेहरा रही हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आईं। राजे अभी सिर्फ विधायक हैं। प्रदेश के संगठन में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके समर्थक भी अब मायूस दिख रहे हैं। सचिन पायलट केंद्र के अलावा राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की लंबे समय तक बागडोर भी संभाली है। लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट एक्टिव रहे। उनके पास छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार भी है। मगर, पावर जोन से बाहर हैं। उनके समर्थकों को उम्मीद है कि सचिन पायलट फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। पायलट भी सिर्फ विधायक हैं।

किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल खुद की राजनीति करते हैं। बेनीवाल चार बार विधायक और दो बार सांसद बने। लेकिन उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि, बेनीवाल का बयान जरूर सुर्खियां बटोरता है। किरोड़ी लाल मीणा भी मंत्री बने जरूर लेकिन उनका इस्तीफा हो चुका है। उनके समर्थक भी असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें भी साफ और सटीक राह नहीं दिख रही है। राजस्थान में पिछले ढाई दशक यानी 25 साल से अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होते आए हैं। हालांकि, इस बार राज्य में बड़ा बदलाव हुआ है। एक ओर कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में अशोक गहलोत की हिस्सेदारी नहीं है। वहीं, भाजपा ने वसुंधरा राजे को भी कोई प्रमुख जिम्मेदारी नहीं दी है। यहां के सियासी हालात के हिसाब से यह लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी के मायने

राजस्थान के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के बाग अब दोनों नेताओं को हरियाणा इलेक्शन से पहले बड़ा जिम्मा दिया गया है। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाया है। वहीं, भाजपा ने वसुंधरा राजे को स्टार प्रचारक बनाया है। ये दोनों नेता इस बार लोकसभा के चुनाव में राजस्थान की एक से दो सीटों पर सिमटे रहे। राजस्थान की अन्य सीटों पर इन्हें न तो पार्टी ने भेजा और न ही ये दिखे, जबकि बीते 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी चुनाव में इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका न रही हो। दरअसल, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से अशोक गहलोत का खेमा कमजोर होने लगा था। फिर, लोकसभा चुनाव में जालोर सीट से वैभव गहलोत की हार हुई और अशोक गहलोत गुट खुद ही कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूर दिखने लगे। अशोक गहलोत बेड रेस्ट पर चले गए। लगभग 100 दिन के बाद अब अशोक गहलोत सक्रिय हुए हैं। वह राजस्थान से महाराष्ट्र गए और अब उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है।

मठ, माफिया और मठाधीश

मठ, माफिया और मठाधीश उप्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से इन तीन शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। वजह इन तीन शब्दों के घेरे में दो बड़े चेहरे का होना है। पहला चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है तो दूसरा चेहरा अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव एक तरफ मठ और मठाधीश के जरिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं पलटवार में योगी आदित्यनाथ उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश पर माफिया राज चलाने का आरोप लगा रहे हैं। दिलचस्प बात है कि दोनों बड़े नेताओं की यह लड़ाई तब शुरू हुई है, जब उप्र में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं।

4 सितंबर 2024 को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सपा कार्यालय में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का आंख-कान नहीं होता है। सरकार बदलने में बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भी मुड़ सकता है। इस पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और जिगरा चाहिए। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। 12 सितंबर को अयोध्या जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए अखिलेश ने कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता है। 18 सितंबर को अयोध्या के मिल्कीपुर में एक रैली के दौरान योगी ने जमकर अखिलेश पर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा की सरकार माफिया चलाते थे। बबुआ माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, इसलिए उन्हें माफिया और संतों में फर्क मालूम नहीं पड़ रहा है। 19 सितंबर को सपा कार्यालय में पत्रकारों ने जब इसको लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी और मुख्यमंत्री की तस्वीर साथ रख लीजिए और बताइए कि कौन माफिया लग रहा है? अखिलेश ने 20 सितंबर को एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भाषा से पहचानिए संत, साधु वेश में धूर्त अनंत।

अखिलेश योगी पर मुखर हैं, इसका पहला कारण विधानसभा का प्रस्तावित उपचुनाव- लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है। सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने उप्र की 80 में से 43 सीटें जीत ली हैं। भाजपा के लिए इसे एक झटका माना गया। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरने के लिए भाजपा ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। योगी आदित्यनाथ के पास पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी है। 2 हॉट सीट मिल्कीपुर और कटेहरी के तो योगी खुद प्रभारी भी हैं।

कौन-सा समीकरण सेट कर रहे योगी

माफिया पर बोलकर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली छवि को दुरुस्त कर रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी के रडार में माफिया हैं। इस दौरान कई माफिया सरकारी चंगुल में फंसकर नेस्तनाबूत हो चुके हैं तो कई खुद से ही सरेंडर मोड में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में शुरू हुई जुबानी जंग के फिलहाल रुकने की संभावनाएं कम हैं। उप्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह की स्थिति अभी है, वैसी ही स्थिति उपचुनाव के बाद रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव तक दोनों के बीच जुबानी जंग जारी रह सकती है। उप्र की जिन सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उनमें मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, करहल, खैर, मीरापुर, फूलपुर, गाजियाबाद, सीसाम और मझवां की सीट शामिल हैं। 2022 में इन 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 पर भाजपा और एक-एक पर आरएलडी-निषाद पार्टी को जीत मिली थी।

लोकसभा के बाद अगर विधानसभा के उपचुनाव में सपा को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिलती है तो पार्टी के मिशन-2027 पर सवाल उठेगा, इसलिए अखिलेश यादव के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जब भाजपा ने मुख्यमंत्री घोषित किया, तब कहा गया कि भाजपा हिंदुत्व की रणनीति को साधना चाहती है। 2019 और 2022 में यह रणनीति सफल भी रही, लेकिन 2024 में भाजपा को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। भाजपा अयोध्या की फैजाबाद सीट भी हार गई। इस चुनाव परिणाम से गदगद अखिलेश अब योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की छवि को तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश योगी को एक समुदाय के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि अखिलेश मठ, माफिया और ठाकुर पॉलिटिक्स के जरिए योगी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश ने हाल ही में उप्र की स्पेशल टास्क फोर्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इस फोर्स में सिर्फ 10 प्रतिशत पीडीए के लोग हैं। बाकी के 90 प्रतिशत अधिकारी सवर्ण समुदाय के हैं।

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लंबे वक्त से ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहता है, लेकिन लोकसभा के बाद अखिलेश इसे हवा देकर उनकी हिंदुत्व की छवि को तोड़ने की कवायद में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर हैं। इसके पहले गुरु गोरखनाथजी नाथ संप्रदाय के थे। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह के मुताबिक योगी आदित्यनाथ गोरक्षापीठ से आते हैं और वे मठ के प्रमुख हैं, इसलिए सपा मुखिया ने उन्हें मठाधीश कहा है। अखिलेश ने भी सपा कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिसे गुस्सा आता हो, जो लोगों का दुख नहीं समझ पाता हो, वो कैसे संत और महंत हो सकता है? विपक्ष की तरफ से लंबे वक्त से योगी आदित्यनाथ पर उनके संप्रदाय के जरिए घेरने की कोशिश होती रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में योगी के शामिल होने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक लेख लिखा था। लालू के मुताबिक नाथ संप्रदाय के जो महात्मा रहे हैं, वो किसी भी मूर्ति और ब्राह्मणवाद को नहीं मानते थे, लेकिन योगी ऐसा करने से परहेज नहीं कर रहे हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

नई दबंग जातीय व्यवस्था उजागर

जब खबर आई कि बिहार में दबंगों ने दलितों की बस्ती में आग लगा दी। देश के बड़े नेताओं की तरह दिल्ली में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों तक को भी यही भान था कि बिहार में दबंगों का मतलब ठाकुर या भूमिहारों ने यह काम किया होगा। देशभर के राजनेता बिहार के नवादा की घटना को लेकर नीतीश सरकार पर टूट पड़े। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से लेकर, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि के दलित उत्पीड़न वाले बयानों की झड़ी लग गई। पर जैसे-जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं- बिहार की राजनीति या बिहार में राजनीति करने वाले अब चुप्पी साध लेंगे। अब इस मुद्दे पर बड़े लेवल पर चर्चा भी नहीं होगी। नवादा कांड के आरोपी दलित समुदाय से आने वाले पासवान हैं। यानी, लड़ाई महादलित और दलित के बीच हुई। इस घटना से यह भी साबित हुआ कि जहां पर जो ताकत में है, वो दबंग है। जो शोषित है, वो दलित है। अब आप दबंग को सवर्ण मानें, ये आपकी मर्जी। लेकिन, यह सवर्ण कोई दबंगई करने वाला दलित या महादलित भी हो सकता है।

नवादा कांड की असल में जिस कारण से चर्चा होनी चाहिए थी उस कारण से नहीं हो रही है। जिस वजह से नवादा में मुसहरों और पासवानों में संघर्ष हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार में इस हिंसा के पीछे जातिगत नफरत नहीं बल्कि बिना पूरी तैयारी के हो रहा भूमि सर्वे है। बिहार सरकार प्रदेश में भूमि सर्वे करा रही है। इस सर्वे का मतलब यह नहीं कि किस जाति के पास कितनी जमीन है। क्योंकि बिहार में हर सर्वे को जाति से जोड़ दिया जाता है। यह सर्वे मूलत: जमीन विवाद खत्म करने के लिए भूमि के मालिकाना हक का प्रॉपर कागज तैयार कराना है। सरकार की सोच तो बड़ी अच्छी है पर उसके क्रियान्यवन का तरीका बेहद लचर है। जाहिर है कि बवाल तो होना ही है। अभी तो यह झलकी है। चिंगारी फूटनी शुरू हो गई है। आए दिन बिहार में अखबारों के पन्ने भूमि पर कब्जे और कागजात के लिए होने वाली मारपीट से भरे जा रहे हैं। बिहार में करीब 50 हजार एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध लोगों का अवैध कब्जा है। नवादा में नदी किनारे करीब 15 एकड़ भूमि जमीन के कुछ भाग पर मुसहर (मांझी) और रविदास समाज के लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और बाकी जमीन पर खेती कर रहे हैं। इस जमीन पर 1995 से टाइटल सूट (22/1995) नवादा व्यवहार न्यायालय में चल रहा है। यानी, जमीन पर हक की लड़ाई कोर्ट में है। एक रिपोर्ट के अनुसार नए सर्वे में यह जमीन खतियान पर रमजान मियां के नाम पर दर्ज नजर आई। रमजान मियां के परिजनों से कृष्णा नगर के ही पासवान समाज, लोहानी बिगहा के यादव समाज और प्राण बिगहा के चौहान समाज (बेलदार जाति) के अलावा नालंदा जिला के रहुई थाना के रघुनाथपुर के चौहान समाज (बेलदार जाति) के लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली। मतलब, जमीन रमजान मियां से इन लोगों ने खरीद ली। कागज पर तो यह हो गया, लेकिन म्युटेशन न होने के चलते रजिस्टर पर जमीन पहले जैसी स्थिति में ही रही। मुसहर और रविदास समाज के लोग जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। जमीन खरीदने वाले भू-सर्वे की प्रक्रिया के समय ही उस कब्जे को हटाने पर आमादा हुए।

दबंग यादवों ने सारा खेल खेला

जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वहां वर्षों से मुसहर और चमार जाति के लोग रहते आ रहे हैं। दुसाध जाति के कुछ लोगों को आगे कर दबंग यादवों ने सारा खेल खेला। जीतनराम मांझी के बयान पर आरजेडी भड़क गई। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जीतनराम मांझी ने अपना होश खो दिया है। वहीं मीसा भारती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को समाज के एक वर्ग पर ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। जबकि चिराग पासवान ने सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। दूसरी तरफ बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने नवादा की घटना को महागठबंधन की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार जिस तरह विकास कर रहा है, उसे और अस्थिर करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। महागठबंधन का चाल-चरित्र बिहार के लोग जानते हैं। जनक राम ने कहा, जिस तरह तेजस्वी यादव के माता-पिता के शासनकाल में समाज के अंदर नफरत फैलाई गई, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई की गई। एक बार फिर उसी को हवा देने की कोशिश हो रही है। दलितों को निशाना बनाया जा रहा है।

जमीन सर्वे के चलते देशभर में रोजी-रोटी के लिए गए हुए लोग अपने दादा-परदादा से मिले खेतों को बचाने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। इनमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आधे-अधूरे कागजात हैं। कुल लोग बरसों ऐसी जमीन पर काबिज हैं जिसकी रजिस्ट्री कई लोगों को हुई है। बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जहां प्रॉपर्टी डीलरों और दबंगों ने कई लोगों को जमीन बेची हुई है। कब्जे पर कोई और है। बहुत लोगों के पास कैथी लिपि में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। जिन्हें आज की तारीख में पढ़ने वाले ही नहीं बचे हैं। बिहार में हुई इस घटना पर पूरे देश का ध्यान क्यों गया? इसलिए नहीं कि इस कांड में दलितों पर अत्याचार हुआ। इस कांड की चर्चा इसलिए देशव्यापी हो गई क्योंकि दबंगों का अर्थ नेताओं ने यह समझ लिया कि शायद सवर्ण हों। यह भी हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा फैलाया गया हो। क्योंकि आजकल मीडिया में इस तरह बढ़त लेने के लिए पार्टियों में होड़ लगी होती है। देश के बड़े से बड़े नेता अपना एजेंडा सेट करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं। शायद यही इस बात पर भी हुआ है। अगर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने क्लीयर नहीं किया होता पूरा इंडिया गठबंधन अभी भी हवा में तलवार चला रहा होता। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बयान आने के बाद असली मामला समझ में आया कि यह सवर्ण और दलित के बीच झगड़ा नहीं है। यह केवल सवर्णों और दलितों के बीच नफरत फैलाने के लिए कुछ लोगों की साजिश है। जीतनराम मांझी ने कहा कि जमीन कारोबार से जुड़े यादव जाति के लोग दलितों को निशाना बना रहे हैं। नवादा की घटना में भी पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है वह यादव जाति के ही लोग हैं।

● **विनोद बक्सरी**

क्या इजरायल से जीत पाएगा लेबनान?

पेजर और वॉकी-टॉकी ब्लास्ट्स के बाद हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका लगा। उसके लड़ाकों के मन में डर बैठ गया। तब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरूल्लाह ने इजरायल को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी। हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को दागने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन ठीक उससे पहले इजरायल का घातक रिएक्शन आया। इजरायली एयरफोर्स ने एयरस्ट्राइक शुरू की। जैसे को तैसा वाली कंडिशन लेबनान और इजरायल में रोज है। लेकिन पिछले 11 महीने से चल रही जंग में ये इजरायल का सबसे घातक हवाई हमला था। एक साथ 70 से ज्यादा जगहों पर फाइटर जेट्स से हमला किया गया। हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइलें और बम गिराए गए। नसरूल्लाह ने कहा था कि इजरायल ने बेहद खतरनाक और दर्द भरा दिन दिखाया है। उसने जंग के सारे नियम तोड़े हैं। अब इजरायल की बारी है।

नसरूल्लाह ने धमकी दी थी कि न मैं समय बताऊंगा, न तरीका न ही जगह। इजरायल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों से हिजबुल्लाह के लड़ाके डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इसके बाद इजरायल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फाइटर जेट्स को सक्रैंबल किया और लेबनान की धरती पर आग बरसा दी। अगर ये दोनों देश आमने-सामने की सीधी जंग में शामिल हों तो क्या होगा? इजरायल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। इजरायल का उत्तरी इलाका और लेबनान का दक्षिणी। इस सीमा को ब्लू लाइन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर में शामिल 145 देशों की सूची में लेबनान किसी भी तरह से इजरायल के टक्कर में नहीं है। 145 देशों में इजरायल की रैंकिंग 18वीं है, जबकि लेबनान की 111वीं। लेबनान के पास एक्टिव सैन्यकर्मी मात्र 80 हजार हैं। इजरायल के 1.73 लाख। यानी दोगुने से ज्यादा। इजरायल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है, जबकि लेबनान के पास है ही नहीं। इजरायल के पास 8000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स है। जबकि लेबनान के पास सिर्फ 25 हजार जवानों वाली पैरामिलिट्री फोर्स है।

इजरायल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं। जबकि लेबनान के पास सिर्फ 78। इजरायल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजरायल के पास 32 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, वहीं, लेबनान के पास सिर्फ 9 हैं। ईरान के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86 हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजरायल के पास ट्रेनिंग देने वाले फाइटर जेट्स 153 हैं, जबकि लेबनान के पास मात्र 9। स्पेशल मिशन पूरा करने के लिए इजरायल के पास 23 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं हैं। लेबनान के पास 60 हेलिकॉप्टर्स हैं। जबकि इजरायल के पास 126 हेलिकॉप्टर्स हैं। इजरायल के पास इनमें से 48 अटैक हेलिकॉप्टर हैं। लेबनान के पास एक भी नहीं है।

टैंक्स की बात करें तो लेबनान के पास 361 टैंक्स हैं। जबकि, इजरायल के पास इससे 7 गुना ज्यादा। इजरायल के पास 2200 टैंक्स हैं। लेबनान के पास 9864 बख्तरबंद वाहन हैं, वहीं इजरायल के पास 56,290 आर्मर्ड व्हीकल। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में लेबनान की तुलना में इजरायल बहुत आगे है। उसके पास 650 आर्टिलरी है। जबकि लेबनान के पास मात्र 84 ही हैं। लेबनान खींचकर ले जाने वाली आर्टिलरी के मामले में इजरायल से आगे हैं। उसके पास 374 टोड आर्टिलरी है। जबकि इजरायल के पास 74 कम। इजरायल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। लेबनान के पास सिर्फ 30। नौसेना में जहाजों और युद्धपोतों के मामले में लेबनान इजरायल से आगे है। इजरायल के पास 67 जहाज हैं, जबकि लेबनान के पास इससे 19 ज्यादा यानी 86 जंगी जहाजों का बेड़ा है। दोनों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हैं।

इजरायल के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजरायल और लेबनान दोनों देशों के पास डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स नहीं है। इजरायल के पास 7 कॉर्वेट युद्धपोत हैं। जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजरायल के पास 45 पेट्रोलिंग वेसल हैं, जबकि लेबनान के पास 22 पेट्रोलिंग वेसल हैं। इजरायल के पास 48 एयरपोर्ट्स हैं। जबकि लेबनान के पास 8 ही हैं। इजरायल के पास 5 बंदरगाह हैं। जबकि लेबनान के पास सिर्फ दो। इजरायल के पास 19,555 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जबकि लेबनान इस मामले में आगे है। उसके पास 21,705 किलोमीटर लंबी सड़कें। इन सड़कों और एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल युद्ध के समय इमरजेंसी में कर सकते हैं। लेबनान क्षेत्रफल के मामले में इजरायल से आधा है। इजरायल 20,770 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जबकि लेबनान का इलाका सिर्फ 10,400 वर्ग किलोमीटर का है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके

इजराइल ने कई सप्ताह पहले सीमा पार से रॉकेट हमले बंद करने की कसम खाई थी, तथा वरिष्ठ इजराइली अधिकारियों ने हाल ही में कहा था कि उनका मानना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैन्य बल ही एकमात्र रास्ता है। देश की सुरक्षा कैबिनेट ने पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षामंत्री योआव गैलेंट को यह तय करने के लिए अधिकृत कर दिया था कि 27 जुलाई को इजरायल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर हुए घातक रॉकेट हमले का जवाब कैसे और कब दिया जाए, जिसमें कम से कम 12 युवा मारे गए थे। इजरायल और अमेरिकी अधिकारियों ने हमले के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया। हालांकि समूह ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से एक दुर्लभ, स्पष्ट इनकार जारी किया। हालांकि हिजबुल्लाह के पास कोई मान्यता प्राप्त सेना नहीं है, लेकिन इसके शीर्ष नेता हसन नसरूल्लाह ने पिछले वर्ष कहा था कि समूह के पास लगभग 1,00,000 लड़ाके हैं, और माना जाता है कि यह लेबनान की वास्तविक राजकीय सेना की तुलना में अधिक सुसज्जित और बड़ी लड़ाकू सेना है। अपने बहुत छोटे ईरान समर्थित सहयोगी हमास की तरह, हिजबुल्लाह को भी लगभग दो दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तथा नसरूल्लाह सहित इसके कई नेताओं को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है।

रूस-यूक्रेन में नहीं थमेगी जंग

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जल्द रुकने के कोई आसार नहीं हैं, यूक्रेन सर्दियों में खुद को युद्ध लड़ने के लिए सक्षम बनाने के प्रयास में जुटा है। इसके लिए उसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने की जरूरत है क्योंकि रूस के हमलों में उसके ज्यादातर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन (यूरोपियन यूनियन) ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया है। यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन गत दिनों कीव दौरे पर थी। उन्होंने यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन को 180 मिलियन डॉलर (करीब 1503 करोड़ रुपए) का ताजा एनर्जी फंड मुहैया कराने का भी वादा किया।

यूरोपीय संघ का अनुमान है कि उसने फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को कम से कम 2.24 बिलियन डॉलर (187 अरब रुपए) की ऊर्जा सहायता दी है। यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि इसमें से 112 मिलियन डॉलर (935 करोड़ रुपए) यूरोपियन यूनियन में रखी रूसी संपत्तियों से मिलेगी क्योंकि वह फरवरी 2022 से यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेहतर होगा कि रूस ही इसकी कीमत चुकाए क्योंकि इस सारी बर्बादी की वजह वही है। यूरोपियन यूनियन ने अनुमान लगाया है कि यूक्रेन का करीब 50 फीसदी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ऐसे में घरों, अस्पतालों और स्कूलों को गर्म रखना काफी मुश्किल चुनौती होगी क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान तेजी से गिरेगा और यूक्रेन को युद्ध के बीच लगातार तीसरे साल की सर्दियों का सामना करना होगा। वॉन डेर लेयेन ने कहा कि रूस अच्छी तरह जानता है कि ऊर्जा स्टेशन पर बमबारी कर यूक्रेन को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। अगर लोग ठंड से ठिठुरते रहे तो उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता में गिरावट आएगी।

यूरोपियन यूनियन चीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में कई ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे इस नुकसान की भरपाई की जा सके। उदाहरण के लिए लिथुआनिया एक थर्मल पावर प्लांट को डिस्मेंटल कर जहाज के जरिए यूक्रेन भेज रहा है, उसके पार्ट्स को यूक्रेन में दोबारा जोड़ा जाएगा।

यूरोपियन यूनियन देश भी यूक्रेन को बिजली निर्यात करना जारी रखेंगे। इससे आने वाले कुछ महीनों में यूक्रेन की जरूरत का लगभग एक चौथाई हिस्सा पूरा होगा। यूरोपीय संघ यूक्रेन में सौर पैनलों और अन्य नई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे रूसी हमलों के लिए ऊर्जा ग्रिड पर सीधा प्रभाव डालना अधिक कठिन हो सके। उन्होंने कहा कि इससे यूक्रेन को ग्रीन इकोनॉमी बनने में भी मदद मिलेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेड फातिह बिरोल ने कहा है कि हमें इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लोग ठंड से बचाव के लिए रास्ता तलाशेंगे और ऐसी जगहों पर विस्थापित होंगे जहां उन्हें गर्माहट और शरण मिल सके। इस बयान का जिक्र करते हुए यूरोपियन यूनियन चीफ ने कहा है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय मदद करना और जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का दोस्त और सहयोगी होने के नाते हमें वह सारे प्रयास करने होंगे जिससे हम सर्दियों में बिजली आपूर्ति जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन के बहादुर लोगों को गर्म रखने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है।

उधर, रूस और यूक्रेन ने भारत पर विश्वास जताया है कि अगर वह चाहेगा तो दोनों देशों में शांति समझौता हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें शांति समझौते को लेकर भारत की मध्यस्थता मंजूर है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद कहा था कि अगली शांति वार्ता भारत में आयोजित होनी चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा है कि अगर भारत शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है तो यह युद्ध रुक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि वह शांति के पक्ष में खड़ा है। यह संदेश न केवल रूस-यूक्रेन के लिए था बल्कि यह पूरी दुनिया को यह बताने के लिए है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका क्या होगी? रूस-यूक्रेन के अलावा अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को भी रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से बड़ी उम्मीदें हैं।

● **कुमार विनोद**

एक कॉरिडोर को लेकर रूस और ईरान की दोस्ती में आई दरार!

रूस और ईरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद करीब आ रहे थे। एक तरफ ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल मुहैया कराने की खबरें आईं तो दूसरी तरफ रूस की ओर से ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम। यानी रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब एक कॉरिडोर ने रूस और ईरान की दोस्ती में दरार पैदा कर दी है। दरअसल रूस और ईरान के बीच ताजा तनाव की वजह है जंगेजुर कॉरिडोर, जिसे ईरान की सीमा पर स्थित क्षेत्र में अजरबैजान विकसित करना चाहता है। कुछ दिनों पहले रूस ने इस कॉरिडोर को लेकर अजरबैजान का समर्थन किया था जिसके बाद से ईरान भड़का हुआ है। जंगेजुर कॉरिडोर बनने से ईरान की आर्मेनिया और फिर यूरोप तक पहुंच बाधित हो सकती है, यही वजह है कि ईरान इसका विरोध कर रहा है। ईरान जंगेजुर कॉरिडोर का विरोध भू-राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही वजहों से कर रहा है। आर्मेनिया के साथ करीब 50 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाले ईरान को चिंता है कि यह कॉरिडोर आर्मेनिया और जॉर्जिया के ज़रिए यूरोप तक उसकी पहुंच को काट देगा। इससे न केवल ईरान के पड़ोसियों की संख्या 15 से घटकर 14 रह जाएगी, बल्कि व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता भी बंद हो जाएगा।

शक्ति पूजा का पर्व नवरात्रि

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्ति भूते सनातनि।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥

नवरात्रि पर्व, मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति पूजा के दिन माने जाते हैं। नवरात्रों में देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग शक्ति स्वरूप - क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा होती है। नवरात्रि वर्ष में दो बार आती है- विक्रम संवत के पहले दिन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमीं तक चैत्र नवरात्रि और छह महीने बाद, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमीं तक शारदीय नवरात्रि आती हैं। इन रात्रियों में ग्रहों के अद्भुत योग के कारण ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जाओं से भर जाता है। इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में अनुभव करने के लिए, नवरात्रि में यज्ञ, भजन, पूजन, मंत्र जप, ध्यान, त्राटक आदि साधनाएं की जाती है। संयमित जीवन जीकर उपवास रखा जाता है, केवल सात्विक आहार लेते हैं, जिससे शरीर शुद्ध रहता है। दिनभर भगवती भाव का शुद्ध विचार रखते हैं।

आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति, नमो नमो
सरब शक्ति, सरब शक्ति, सरब शक्ति, नमो नमो
प्रीतम भगवती, प्रीतम भगवती, प्रीतम भगवती, नमो नमो
कुण्डलिनी माता शक्ति, माता शक्ति, नमो नमो।।

नवरात्रि के पहले दिन सुबह संकल्प रूपी कलश स्थापना की जाती है। यह कलश सुख-समृद्धि और मगंल कामनाओं का प्रतीक है। कलश के साथ ही बालू की वेदी बनाकर या किसी पात्र में जौ बोए जाते हैं। जौ बोने से धन-धान्य की वृद्धि होती है, जौ को सृष्टि की पहली फसल के रूप में भी माना जाता है। साथ ही मां दुर्गा की मूर्ति को स्थापित कर उसको सजाकर अखंड दीप जलाया जाता है और अंतिम दिन नौ कन्याओं को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है।

असलियत में मन की एकाग्रता के लिए रात की साधना का बड़ा महत्व है, क्योंकि रात को प्रकृति शांत हो जाती है। इसी कारण दीवार पर टंगी घड़ी में सेकंड की सुई की आवाज सुनाई देने लगती है। दिन में सूर्य की किरणें और अन्य कोलाहल होने के कारण ब्रह्मांडीय तरंगों में रुकावट बनी रहती है, जिस कारण ध्यान नहीं लग पाता है। इसी कारण शिवरात्रि, नवरात्रि, होली, दीपावली आदि पर्वों की रात में साधना की जाती है।

साधक कमर-गर्दन सीधा कर, आंख बंदकर बैठ जाते हैं, रीढ़ को सीधा करके बैठने से हमारी तरफ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षित होती हैं। अब साधक शक्ति मंत्रों का जप करता है, जिससे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्जा के अलग-लैह अनुभव होने लगते हैं, जिसको कुण्डलिनी जागरण कहते हैं। हर रात यह शक्ति ऊपर के चक्र को जगाने लगती है और अंतिम रात्रि को शक्ति पूरी तरह जागकर व्यक्ति को मुक्त भाव में ले आती है। कुण्डलिनी जागरण ही हमारे भीतर देवी जागरण कहलाता है।

ऋतु संधिकाल यानी बदलते मौसम में रोगाणु के शरीर पर आक्रमण बढ़ जाता है। इस मौसम में वात, पित्त और कफ तीनों दोष असंतुलित होने से इम्मून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। जिससे शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नवरात्रि में नौ दिन जप, उपवास, साफ-सफाई, और भाव शुद्धि और ध्यान कर बीमारियों से रक्षा करते हैं। हवन करने से वातावरण में फैले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। नए कार्यों के आरंभ के लिए ये दिन बड़े शुभ माने जाते हैं।

धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार, शारदीय नवरात्रि भगवती दुर्गाजी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन मां के अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ठ रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग-अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है।

शास्त्रों में नवरात्रि पर्व मनाए जाने की दो पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्माजी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्माजी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य मार ना पाए। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी-देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच नौ दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और दसवें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है।

दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान श्रीराम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी मां भगवतीजी की आराधना की थी। रामेश्वरम में उन्होंने नौ दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने श्रीराम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। दसवें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है।

● **ओम**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

साथ

तानी बचपन से ही और बच्चों से अलग थी। नकारात्मक बातों का प्रभाव उस पर अधिक होता सकारात्मक बातें उसे प्रभावित नहीं करती।

देखने में बहुत प्यारी चंचल, मोहक मुस्कान मां की लाड़ली पापा की खुशी थी।

पिता ने तो उसे प्यार दुलार के नाम पर बिगाड़ने की मानो दीक्षा ले रखी थी।

स्कूल में भी वह बेकार बच्चों का साथ ढूंढ ही लेती थी।

मां बेचारी दिन-रात तानी के लिए सोंचती और प्रयास करती पर बेटी को मां की कहानियां और बातें रास नहीं आती।

समय बीतता गया तानी 11 साल की हो गई। कक्षा में पिछड़े रहने के कारण उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं था, पर किताबों का साथ अब भी उसे अच्छा नहीं लगता था। मां अथक परिश्रम करती पर सफलता हाथ नहीं लग रही थी।

बेटी की चिंता क्या होती है यह एक बेटी की मां ही समझ सकती है।

करत-करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान।।

वह बड़बड़ाती हुई काम करती

जाती है कि यह तथ्य मिथ्या तो नहीं हो सकता। एक दिन मेरा परिश्रम सफल जरूर होगा

फिर विश्वास और आस के दीपक का साथ लेकर निरंतर वह अपने कर्म पथ पर चलती बढ़ती रही।

अंततोगत्वा तानी को समझ आ जाता है कि मां क्यों उसे डाटती है, क्यों समझाती है।

वह अपनी हर बुरी आदत को छोड़ देती है। अच्छी संगत का महत्व वह जान चुकी थी।

उसमें दिन-ब-दिन सकारात्मक बदलाव आते जा रहे थे।

मानो कुंदन तप कर सोना बन गया था।

पुस्तकों के साथ ने न केवल उसे ज्ञान, सम्मान और अच्छी नौकरी दी बल्कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ भी दिया।

अच्छा साथ ही अच्छा विकास देता है।

- मंजूषा श्रीवास्तव 'मृदुल'

केवल मेरा मन ही जाने

कई रिक्तियां शेष रह गईं,
कहां भला कुछ कर पाया मैं?
जब निकले तुम अंतिम पथ पर,
मात्र आह ही भर पाया मैं।
क्या सोचा था, और क्या हुआ?
केवल मेरा मन ही जाने।
तुम बिन भ्राता! जग के मेले
लगते हैं मुझको वीराने।
चले गए तुम सम्बल मेरे,
खुद को बहुत लचर पाया मैं।
कई रिक्तियां....
खड़े रहे हम बिल्कुल बेबस,
और प्राण उड़ गए आपके।
हमसे टूटे बंध, प्रभु से,
नेह बंध जुड़ गए आपके।
हाथ छुड़ाकर चले गए तुम,
कहां आपको धर पाया मैं?
कई रिक्तियां....
सूना-सूना है मन उपवन,
हर एक कोना शोकाकुल है।
किसी से नहीं कह सकता मैं,
लेकिन मन अतिशय व्याकुल है।
खुलकर कहां विलाप कर सका,
सिर्फ अश्रुजल भर पाया मैं।
कई रिक्तियां....

- डॉ. दिवाकर दत्त त्रिपाठी

भूख...

रास्ते पर चल रही महिला की सोने की चेन खींचकर भाग रहे एक हट्टे-कट्टे बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस कांस्टेबल ने उसका पीछा किया। वह बदमाश सड़क पार करके तंग गली में घुस गया। लगातार उसका पीछा करते-करते कांस्टेबल थक गया, पर बदमाश उसके हाथ नहीं आया। वह पसीने से लथपथ हो गया। इतने में गली के नुक्कड़ पर झुग्गी से एक आदमी निकला। नुक्कड़ पर उसने लगड़ी मारी। बदमाश नीचे गिर गया। गिरते ही उस बदमाश

को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सबको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक दुबले-पतले इंसान ने हट्टे-कट्टे बदमाश को पकड़ लिया, जिसे पुलिस नहीं पकड़ सकी। सब तालियां बजाने लगे। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। जब वह अपनी झुग्गी में पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, आपको डर नहीं लगता?

उसने अपनी झुग्गी में औंधे पड़े बर्तनों को देखकर उत्तर दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता सिवाय एक चीज के-भूख।

- डॉ. अनीता पंडा 'अन्वी'

आकर्षण का केंद्र बनेगा टेस्ट क्रिकेट!

क्रिकेट की जननी कही जाने वाली टेस्ट क्रिकेट से दर्शक और खिलाड़ी दूरी बनाने लगे हैं। ऐसे में इनकी दिलचस्पी जगाने के लिए जहां पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को बोनस सहित मैच फीस में इजाफा किया, वहीं अब आईसीसी और दुनियाभर के क्रिकेट बोर्ड टेस्ट क्रिकेट के भविय को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नया फंड जारी करने की पहल की है। मुख्य रूप से इसकी पहल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की थी, जिसका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी समर्थन किया है।

आईसीसी की इस पहल का उद्देश्य यह भी है कि इससे अलग-अलग बोर्ड के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी मैच फीस देने के लिए सेंट्रल फंड बनाया जा सकेगा। ईएसपीएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड के बाद टेस्ट मैच में किसी भी खिलाड़ी की मैच फीस करीब 8 लाख हो सकती है। इससे न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, बल्कि टी-20 जैसे छोटे फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट आकर्षण का केंद्र बनेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से टेस्ट क्रिकेट को दर्शकों की संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। टेस्ट क्रिकेट के प्रति राय और भावनाएं हर कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर बदलती रहती हैं, जिसमें इसे सर्वश्रेठ प्रारूप कहे जाने से लेकर क्या टेस्ट क्रिकेट का अस्तित्व खतरे में है तक शामिल है। कई प्रशंसक अब टी-20 क्रिकेट में अधिक रुचि रखते हैं, जो युवा दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक है। इसमें सबसे ज्यादा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसी लीगों ने खेल के छोटे प्रारूपों की लोकप्रियता में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है।

ऐसे में आईसीसी और दुनियाभर के क्रिकेट बोर्ड टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। ऐसा ही एक उपाय विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की शुरुआत है। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप शीर्ष 9 टेस्ट खेलने वाले देशों के बीच एक प्रतियोगिता है, जिसका फाइनल हर दो साल में आयोजित किया जाता है। एक अन्य उपाय खेल की पहुंच का विस्तार है। आईसीसी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे नए बाजारों में टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। आईसीसी डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से टेस्ट क्रिकेट को प्रशंसकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। संघर्षरत टेस्ट देश भी क्रिकेट के लंबे प्रारूप को सुरक्षित रखने के लिए अधिक फंडिंग और समर्थन की मांग कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी 2025 से टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए तीन बड़े क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर अन्य क्रिकेट बोर्ड के लिए एक नया फंड जारी कर सकती है। इसका लक्ष्य टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देना है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि अन्य बोर्ड आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी लीग से बराबर का मुकाबला कर अपनी जगह बना सके। मुख्य रूप से इसकी पहल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष मार्क बेयर्ड ने की थी, जिसका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी समर्थन किया था। आईसीसी की इस पहल का उद्देश्य यह भी है कि इससे अलग-अलग बोर्ड के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी मैच फीस देने के लिए सेंट्रल फंड बनाया जा सकेगा।

ईएसपीएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड के बाद टेस्ट मैच में किसी प्लेयर की मैच फीस करीब 8 लाख हो सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल दिसंबर तक इस प्रस्ताव को अनुमति मिल जाएगी और अगले वर्ष से इसको लागू किया जाएगा। इससे न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, बल्कि टी-20 जैसे छोटे फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये फंड कम धन राशि वाले क्रिकेट बोर्ड को भी लाभ पहुंचाएगा। क्रिकेट बोर्ड को जारी की जाने वाली नई राशि डेढ़ करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 125 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रिचर्ड थाम्पसन का समर्थन इस प्रस्ताव को हासिल है। हालांकि इसकी चर्चा अभी शुरुआती स्तर पर ही है और अब तक आईसीसी द्वारा बोर्ड या कार्यकारी समिति के स्तर पर इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है।

भारत, ऑस्टेलिया और इंग्लैंड को छोड़कर टेस्ट खेलने वाले अन्य देशों को टेस्ट क्रिकेट में नुकसान उठाना पड़ता है। इस साल की शुरुआत में क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जानी ग्रेव ने बताया था कि साल की शुरुआत में ऑस्टेलिया के दौरे में बोर्ड को कुल 20 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आया। 2023 में ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, कैरिबियाई धरती पर तीन टी-20 खेलने के लिए राजी हो गई थी जिससे उन्हें फायदा हुआ था। पिछले महीने ही इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला के एवज में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वेस्टइंडीज को अपने घर पर अंडर-19 दौरे की सुविधा भी मुहैया कराने वाला है। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि एक समय था जब क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट को खेल प्रेमी खूब पसंद करते थे लेकिन टी- 20 के आने से उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, वहीं टेस्ट क्रिकेट लगातार अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि कई देश पांच दिवसीय क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिम्बाब्वे गरीब और छोटे देशों में क्रिकेट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। बोर्ड के पास पैसा नहीं है। यही कारण है कि उसने 2017 में फैसला लिया था कि वह अधिक से अधिक मैच अपने देश से बाहर खेलेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद फैंस वनडे और टेस्ट क्रिकेट को कम पसंद कर रहे हैं। टी-20 क्रिकेट तीन से चार घंटे में समाप्त हो जाता है जिसके लिए प्रसारक को भी आसानी होती है जबकि एक वनडे मैच 8 से 9 घंटे के बीच खत्म होता है, वहीं टेस्ट पांच दिन तक चलता है, जिससे प्रसारकों की दिलचस्पी भी कम हो गई है। ऐसे में आईसीसी की इस पहल से एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

● **आशीष नेमा**

फिल्म इंडस्ट्री एक रंगीन दुनिया है। पर्दे पर चमकती जिंदगी के पीछे कई स्याही कहानियां हैं। इसमें हीरो और हीरोइन भी हैं। कई स्टार हीरो के निजी मामले सनसनीखेज बन गए हैं।

308 अफेयर, 3 शादियां, कोई साधारण हीरो नहीं

बॉलीवुड में ही नहीं साउथ का भी है सुपरस्टार

आप आपको एक ऐसे हीरो की कहानी बताते हैं, जिनकी 2-4 नहीं बल्कि 308 गर्लफ्रेंड्स थीं। एक्टिंग की क-ख-ग तो उन्होंने बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टारडम ने उन्हें ऐसे रास्तों पर पहुंचा दिया, जहां वह विवादों में उलझते चले गए। हालांकि, इन तमाम मसलों के बीच चर्चा उनकी प्रेम कहानियों की ज्यादा होती है। ये एक्टर बॉलीवुड ही नहीं साउथ का भी बड़ा नाम है। उनका नाम है संजय दत्त।

मान्यता दत्त की पहली मुलाकात संजय दत्त से 2006 में हुई थी। फिर दोनों बहुत जल्दी एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मान्यता से शादी करने से पहले संजय दत्त ने दो शादियां की थीं। संजय दत्त से शादी के बाद मान्यता ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। मान्यता संजय दत्त से 18 साल छोटी हैं। उनका प्यार सराहनीय है। चाहे वो संजय दत्त की कैंसर से जंग हो या फिर जेल जाना। वह हमेशा से ही संजय दत्त की ढाल रही हैं। दोनों के जुड़वां बच्चे शहरान और इकरा हैं। हालांकि, उनकी पहले की कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। संजय दत्त ने 1980 के दशक से बी-टाउन में अपना करियर शुरू किया था और एक्टर अपने करियर में अब तक 130 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। लेकिन उनके अफेयर की संख्या इससे भी ज्यादा रही हैं।

माधुरी दीक्षित को भी कर चुके हैं डेट... *मीडिया रिपोर्ट्स में संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड्स होने का दावा किया जाता है, जो हकीकत है। दरअसल, संजय दत्त की जिंदगी पर संजू नाम की फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में उन्होंने खुद ही 308 लड़कियों से उनका अफेयर होने की बात कबूली थी। उन्होंने अपनी पीढ़ी की लगभग हर एक्ट्रेस को डेट किया है। रेखा और माधुरी दीक्षित तक कोई भी उनके प्रेम जाल से नहीं बच सका। ऋचा शर्मा की पहली पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी। इसके बाद संजय दत्त ने 1998 में रिया पिल्लई से दोबारा शादी की। लेकिन ये शादी ज्यादा टिक नहीं पाई और दोनों अलग हो गए।*

एक्टर बनने से पहले ट्रैवल एजेंट थे जैकी श्रॉफ, देव आनंद ने दिया था पहला रोल

जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के सफल एक्टर हैं, जिनके बेटे टाइगर श्रॉफ भी एक्टिंग में खूब नाम कमा रहे हैं। एक्टर ने दिवंगत सुपरस्टार देव आनंद को याद किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो शेयर किया, जिस पर लिखा है, देव साहब के आशीर्वाद से मैं फिल्मी दुनिया में आया।

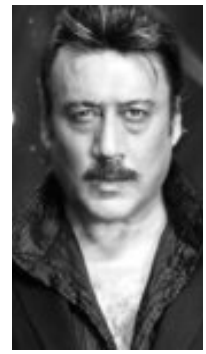

जैकी श्रॉफ ने देव आनंद की 1982 की फिल्म स्वामी दादा से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। देव आनंद से पहली मुलाकात में उन्हें सेकेंड लीड रोल ऑफर किया गया था, लेकिन 15 दिन बाद देव आनंद ने अपना मन बदल लिया और मिथुन चक्रवर्ती को यह रोल दे दिया।

जैकी को शक्ति कपूर के एक गुर्गे के रूप में एक बिना श्रेय वाली भूमिका में कास्ट कर लिया था। जैकी इससे पहले एक ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करते थे और एक विज्ञापन कंपनी में भी काम करते थे। विज्ञापन में उनके कार्यकाल ने उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट दिया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें स्वामी दादा में कास्ट कर लिया गया।

1981 में ब्लॉकबस्टर दे चुकीं एक्ट्रेस, कभी दी थी श्रीदेवी-माधुरी को टक्कर

राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के साथ फिल्म लव स्टोरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली विजयता पंडित आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। अपनी डेब्यू फिल्म से ही वह रातोंरात स्टार बन गई थीं। लेकिन प्यार में पड़ जाने की वजह से उनका बना बनाया करियर डूब गया। अब सालों बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि क्यों ब्लॉकबस्टर देकर भी वह एक्टिंग से दूर हो गई थीं। अपनी डेब्यू फिल्म लव स्टोरी की रिलीज के बाद उनका नाम को-स्टार कुमार गौरव के साथ जुड़ चुका था। खुद विजयता पंडित ने इस बात का खुलासा भी किया है कि वह दोनों एक समय में आने के बाद एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुमार गौरव तो उनसे शादी भी करने वाले थे। लेकिन उनके पिता राजेंद्र कुमार को उनका रिश्ता पसंद नहीं था। वह उनके रिश्ते के खिलाफ थे। यही वजह थी कि उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया।

अफेयर के चलते पटरी से उतर गया करियर

कुमार गौरव-विजयता पंडित के खूब हुए थे प्यार के चर्चे... *कुमार गौरव को अपनी पहली ही फिल्म के दौरान विजयता पंडित से प्यार हो गया था। इस बात से राजेंद्र कुमार वाकिफ थे, लेकिन उन्हें ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। कुमार गौरव की सगाई राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से हुई थी। बाद में ये सगाई ज्यादा टिक नहीं पाई। अफवाहें रहीं कि इसके पीछे का कारण विजयता रहीं। हाल ही में विजयता ने लेहरन को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं, उन्होंने बताया कि मुझे कई फिल्मों से बाहर किया गया है। मैंने अनिल कपूर के साथ मोहब्बत में काम किया था। यह एक महिला प्रधान फिल्म थी, दर्शकों ने मेरे काम की सराहना भी की, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली।*

दो बार रचाई शादी

विजयता ने इस रिश्ते से बाहर आने के बाद फिल्म कार थीफ के डायरेक्टर समीर मल्कान से शादी रचाई थी। लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और उनका तलाक हो गया। एक्ट्रेस ने पहली शादी टूटने के बाद म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से शादी की। उनके दूसरे पति को कैंसर की बीमारी ने छीन लिया। पति के देहांत के बाद विजयता पंडित आर्थिक तंगी से गुजरीं, उन्होंने अकेले ही अपने दम पर जिंदगी गुजारी।

सील मछली का शिकार...

जल संस्थान की पाइपलाइन छोड़कर, शहर में चारों ओर जल ही जल है। दीवार पर सरकारी विज्ञापन में लिखा है, जल ही जीवन है, लेकिन ठीक उसके नीचे खुला मैनहोल है, जो किसी को नहीं दिख रहा है। पिछले दो दिनों में कई लोग उसमें जीवन की संभावनाओं को खोजते-खोजते जल समाधि ले चुके हैं। एक खुशकिस्मत भीतर ही भीतर बहकर दूसरे मोहल्ले के नाले से बरामद हुआ। उसने बताया कि मैनहोल के अंदर निगम का एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है-इस अंजुमन में आपको आना है बार-बार, दीवार-ओ-दर को गौर से पहचान लीजिए।

नगर निगम की एक सड़क दूसरी से पूछती है-सखी सड़क! तुम्हारा तो अभी तीन महीने पहले ही गौना हुआ था। सुहागन की तरह सोलह शृंगार किए शहर की सेज पर पधारी थीं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बरसात की पहली ही फुहार में तुम उजड़ा चमन नजर आने लगीं! सड़क जवाब देती है-बहन, सब कमीशन का खेल है। इसके लिए भी वही ठेकेदार और इंजीनियर जिम्मेदार हैं, जिनकी काली करतूतों से तुम दर्जनों गड्ढों की बिन ब्याही मां बन गईं। उसी कमीने कमीशन ने मेरी मांग के सिंदूर पर बुलडोजर चला दिया।

उधर, शहर की चकाचौंध-विकास और फेस्टीविटी से दूर, वाल्मीकि मोहल्ले में चुराई ईंटों, प्लास्टिक की शीट और टूटे एस्बेस्टर की छत से बने कमरे में दीपक परेशान होकर चहलकदमी कर रहा था। परेशानी की वजह थी बिटिया का एक छोटा-सा सवाल- पापा! एस्किमो लोग सील का शिकार कैसे करते हैं?

बिटिया को ईडब्ल्यूएस कोटे में इलाके के नामी स्कूल यादव वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाकर दीपक खुश था कि बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर कुछ बन जाएगी। उसे क्या पता था कि ऐसे सवालों से भी दो चार होना पड़ेगा। पहले उसने सवाल को टालने की कोशिश की कि, कल तुम ट्यूशन की टीचर से पूछ लेना। पर पता लगा कि ट्यूशन टीचर ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे कि, सिलेबस या ज्यादा से ज्यादा मुहल्ले से संबंधित सवाल पूछ लो। 250 रुपए ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन में अंटार्कटिका जाना नामुमकिन है।

अब दीपक के सामने बेटी को इस सवाल का एकदम ठीक-ठीक जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने बेटी को साथ लिया और एक सीवर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सीवर के ढक्कन को हटाया और बोला देख बिटिया, अंटार्कटिका में वहां के इनुइट लोग इसी तरह जमीन में सुराख बना देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि कब कोई सील मछली आए।

बिटिया ने हैरानी से पूछा, पापा! क्या अंटार्कटिका में नालियों में सील मछली पाई जाती है?

हम सीवर साफ करने वाले उनका गंदा साफ करते हैं। गंदगी में नाक तक डूब जाते हैं। और वे हमें देखकर नाक में रुमाल रखकर परे हट जाते हैं। हमें देखकर किसी बाबू का दिल आज तक पिघला है... ?

अरे दुर-पगली... दीपक ने प्यार से बिटिया को झिड़कते हुए कहा, अंटार्कटिका में चारों ओर बरफ ही बरफ और बरफ के नीचे पानी का महासमंदर और उस महासमंदर में रहती हैं सील मछलियां!

बरफ के नीचे समंदर! भला यह कैसे हो सकता है? बरफ तो समंदर में पिघल जाएगी कि नहीं बुद्धू? बिटिया ने तमककर कहा।

कुछ नहीं पिघलता बिटिया। यही तो विधाता की सृष्टि है दीपक ने कहा, अब देखो जमीन के ऊपर कितनी रौनक, कितनी चहल पहल है। लाल सांता की-टोपी लगाए बाबू लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, मॉल में शापिंग कर रहे हैं। बड़े-बड़े मकानों-रेस्टोरेंटों और मॉल में हग-मूत रहे हैं। उनकी गंदगी शहर के गंदे नाले में बह रही है। हम सीवर साफ करने वाले उनका गंदा साफ करते हैं। गंदगी में नाक तक डूब जाते हैं। और वे हमें देखकर नाक में रुमाल रखकर परे हट जाते हैं। हमें देखकर किसी बाबू का दिल आज तक पिघला है? और जब इंसान का दिल नहीं पिघलता तो बरफ क्या चीज है बिटिया?

बाप कहानी को आगे बढ़ाता है, जैसे मैं इस सीवर के गंदे पानी में उतरता हूं, उसी तरह बरफ के नीचे महासमंदर के पानी में सील मछली रहती है।

बिटिया पूछती है, पापा आप सील मछली बन जाते हो?

बाप हंसकर जवाब देता है, अरे बिटिया, मैं तो पानी में उतरता हूं एक चड्डी पहनकर पर सील मछली तो एकदम नंग-धड़ंग रहती है।

बेटी पूछती है, फिर क्या होता है पापा?

सील मछली को सांस लेने के लिए हवा में बाहर आना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे गंदे पानी में रहते हुए मुझे भी सांस लेने के लिए इस मैनहोल से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे सील मछली बरफ में बने सुराख से सांस लेने के लिए अपनी मुंडी बाहर निकालती है, उसी समय शिकारी बरछा चला देता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जैसे सीवर साफ करने वाले लोग बाहर सांस लेने के लिए निकलने की कोशिश करते हैं और मैनहोल की जहरीली हवा की बरछी हमारे फेफड़ों को फाड़ देती है, हमारे दिमाग की नसों को सुन्न कर देती है और हम गंदगी से बजबजाते पानी में धीरे-धीरे डूबते चले जाते हैं... और सील मछली मर जाती है।

एक लंबी चुप्पी के बाद पापा कहते हैं, सील मछली हमसे खुशकिस्मत है बिटिया। पूछो क्यों? क्योंकि सील मछली शिकार पर अब पाबंदी लग गई है।

फिर अपने में ही बुदबुदाता हुआ कहता है, जाने कब दूसरे शिकारों पर पाबंदी लगेगी?

● **अनाम**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

PRESENTING

Our new corporate identity

JKCement

A SOLID LEGACY OF TRUST

The trunk spreads wide
The branches reach high
Spurring us on
To reach for the sky.
'Y' for our founding father
Late Shri Yadupati Singhania ji

Energy and sustainability
Define our Abundance Tree.
Green is our vision
Grey, our foundation
Blue is the limitless sky of opportunities
That inspires our transition.

JK Cement Ltd.
Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh. Tel : 0512 2371478-81.
Corporate Office : Padam Tower, 19, DDA Community Centre, Okhla, Phase - 1
New Delhi - 110020. Tel.: 011 - 49220000

www.jkcement.com